JOURNAL

New Frontiers of Research

(Multidisciplinary Multilingual Referred Research Journal)

Vol. 03 No. 05 & 06 Special Issue - Dec16

Pt. Bhagwat Prasad Dubey Smriti
Samaj Evam Vigyan Unnayan Samiti

C.M.D.P.G. COLLEGE
BILASPUR (C.G.)

NEW FRONTIERS OF RESEARCH

Six Monthly Multidisciplinary Multilingual Research Journal

Volume 02 Number 01 [illegible]

CONTENTS

1. "कोरबा जिले (छ.ग.) की पर्यटन संभावना का मूल्यांकन (उत्तरदाता की कथन प्राथमिकता पर आधारित)"
डॉ. पी.एल. चन्द्राकर 1-11

2. मनरेगा का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में
डॉ. आदित्य कुमार दुबे, कु. आभा श्रीवास्तव 12-17

3. बिरहोर जनजाति का सामाजिक व आर्थिक अध्ययन (वि.स. कोटा जिला बिलासपुर के संदर्भ में)
श्रीमती श्वेता सिंह 18-24

4. महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम् में प्रमुख पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण
शशिरेखा सरकार 25-31

5. "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की क्रियान्वयन करने में भूमिका (कोटा विकास खण्ड, बिलासपुर जिला के ग्राम पंचायतों के संदर्भ में)
अखिलेश कुमार पाण्डेय 32-34

6. कोरबा जिले (छ.ग.) के कोरबा जनजाति में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन
सुनील कुमार श्रीवास 35-40

7. जलवायु का कृषि पर प्रभाव : एक अध्ययन
डॉ. संजय सिंह, श्रीमती पल्लवी चतुर्वेदी 41-44

8. Rainfall Variability, Food Security And Human Mobility In The Janjgir – Champa District Of Chhattisgarh State, India
[illegible] Paul 45-51

CONTENTS

9. A Spatial Analysis Of Forest Cover Using Gis And Remote Sensing Techniques
(A Case Study In Achanakmar Wildlife Sanctuary)
Kajal Kr Sikdar 52-58

10. The Socio-economic Evolution Of Banga Tribe At Kota In Bilaspur District Of Chhattisgarh
Debabrata Ghosh 58-61

11. The Impact Of Captivity On Behaviour Of Wild Animal: A Case Study From Kanan Pendari,Bilaspur(C.G).
Dipak Mandal 62-67

12. Marketing Oriented Organization And Its Values
Dr. U.L. Agrawal , Dr. S.C. Bajpai 68-70

13. Marketing Strategies In Library
Mr. Salik Ram 71-78

14. Changes Of Food Habits Among The Tribes Of Korba District (C.G)
Dr. Mojaffar Ahamad, Dr. P.L. Chandrakar 79-85

संपादक की कलम से .....

संपादकीय

"न्यू फ्रंटियर्स ऑफ रिसर्च" के इस द्वितीय अंक का प्रकाशन विविध विषयों पर शोधरत शोधार्थी एवं विषय विशेषज्ञों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक साबित होगा। इस अंक में हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, पर्यावरण, भूगोल आदि विषयों पर आधारित विद्वतजनों द्वारा शोधपत्र प्रकाशित किये गए हैं। सी.एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर के शासी निकाय के युवा, कल्पनाशील एवं कर्मठ अध्यक्ष पं. संजय दुबे जी एवं आचार्य डॉ. डी. के. चक्रवर्ती की यह आकांक्षा और निर्देश था कि महाविद्यालय परिवार के द्वारा उच्च स्तरीय रिसर्च जर्नल का द्वितीय अंक का प्रकाशन समयानुसार किया जाना चाहिये, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए यह अंक प्रकाशित किया जा रहा है।

मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि प्राध्यापक एवं शोधार्थीगण अपने स्तरीय शोध पत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित कर इस शोध – पत्रिका के निरंतर प्रकाशन में हमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। पत्रिका को उच्च स्तरीय बनाने हेतु आपके सुझाव सादर आमंत्रित है।

(डॉ. के.के. जैन)
भौतिक विभाग
सी.एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

New Frontiers Of Research Vol. 3 Dec. 2016 ISSN No. 2347-2085

"कोरबा जिले (छ.ग.) की पर्यटन संभाव्यता का मूल्यांकन (उत्तरदाता की कथन प्राथमिकता पर आधारित)"

डॉ. पी.एल. चन्द्राकर

1. प्रस्तावना:

किसी देश या प्रदेश के समुचित विकास में पर्यटन का अलग ही महत्व है। आज विश्व में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। पर्यटन जीवन से जुड़ा एक अभिन्न अंग है जिस तरह एक पक्षी को पिंजड़े में कैदकर, उसे शेष दुनिया से नावाकिफ कर देते है, उसी तरह इंसान भी बिना पर्यटन के सम्पूर्णता को हासिल नहीं कर सकता। पर्यटन पिंजड़े से मुक्ति का दूसरा नाम है, कि आप उड़ान भर सके, चहचहा सके, गुनगुना सके। पर्यटन हमें विविध सांस्कृतिक, भाषाएं, भौगोलिक विभिन्नताएं, भिन्न–भिन्न, पहनावे, खानपान होने के बावजूद एक सूत्र में बांधते हैं।

पर्यटन एक धुंआ रहित उद्योग है, जो एक साथ शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, व्यापार तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ावा देता है तथा विदेशी मुद्रा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए आज दुनिया के कई देश अपने पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित कर अपनी अर्थव्यवस्था एवं विकास को सुदृढ़ करने हेतु प्रयासरत है। हमारे देश में भी कई राज्यों की अर्थव्यवस्था का आधार पर्यटन उद्योग है।

2. अध्ययन क्षेत्र:

छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर मध्य में स्थित कोरबा पिछड़ा हुआ आदिवासी बहुल जिला है। ग्लोब में यह जिला 22'3' से 22'59'30'' उत्तरी अक्षांश एवं 82' 8' 30'' से 83' 8' 15'' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 7145.44 वर्ग कि.मी. तथा 2001 की जनगणनानुसार कुल जनसंख्या 1012121 थी। जिसमें से 419889 अर्थात् 41. 50 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति हैं यहां पहाड़ी कोरवा, पण्डो, धनुहार, मझवार, बिंझवार, कंवर, गोंड, बैगा आदि जनजातियां निवास करती है। यहां की औसत साक्षरता दर 63.24 प्रतिशत तथा लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जीविकोपार्जन करती है। जिले का अधिकांश भाग पहाड़ी, पठारी एवं सघन वनाच्छादित है, जहां हसदेव, अहिरन, मनियारी, चोरनई, गेज, तान आदि नदियां अपने प्रवाह मार्ग पर सुन्दर जल प्रपात बनाती हुई सदियों से सतत् सुप्रवाहित है। किन्तु आज सूखती नदियां जल प्रपात पर्यटन के लिए एक चिन्तनीय विषय बन कर उभरा है। काला हीरा कहा जाने वाला कोयला संसाधन,

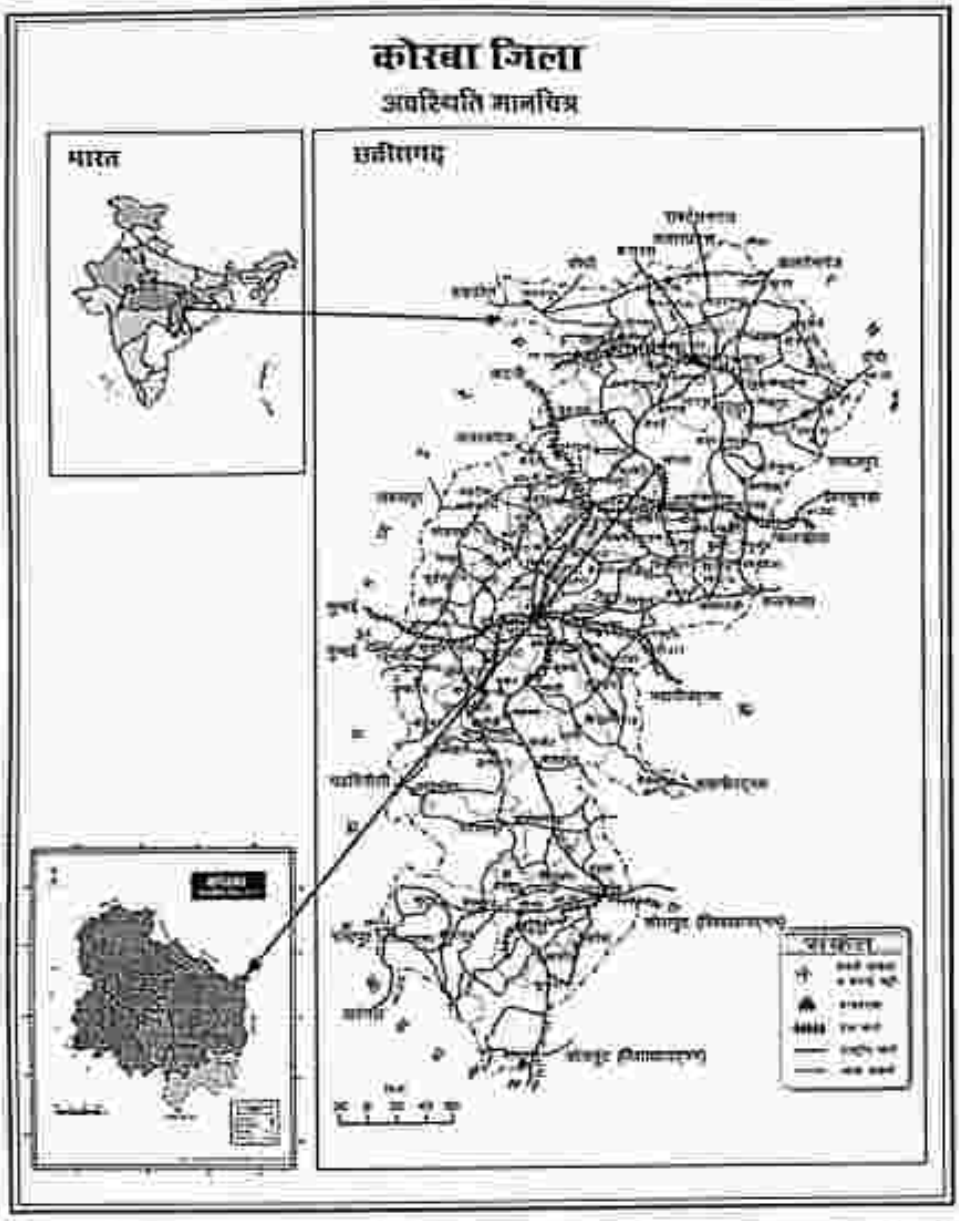

ताप विद्युत एवं एल्युमीनियम उत्पादन के लिए कोरबा की न केवल देश में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में एक अलग पहचान है।

यहां के आदिवासियों की अद्वितीय प्राचीन संस्कृति व्यवस्था, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर, जलाशय, प्राकृतिक सौन्दर्य सैकड़ो वर्ष प्राचीन वृक्ष, जड़ी–बूटियां आदि प्रचार–प्रसार, प्राकृतिक अवरोध, अशिक्षा और विविध सुविधाओं के अभाव में गुमनाम एवं बिखरी हुई अवस्था में पड़ी हुई है। यदि उनकी पहचान कर प्रकाश में लाया जाये तथा उन्हें पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाये तो निश्चय ही कोरबा जिला में पर्यटन भी एक उद्योग बनकर उसे नई पहचान देगा तथा जिले के विकास में सहायक बनेगा और साथ ही यहां ग्रामीण पर्यटन, इको–टूरिज्म, इथनो टूरिज्म तथा औद्योगिक पर्यटन में अपार सम्भाव्यता छिपी

हुई है।

3. अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध पत्र कोरबा जिले में पर्यटन की सम्भाव्यता एवं प्रत्याशा का गहन अध्ययन है। इस अध्ययन में जिले के पर्यटन विकास में सहायक विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जायेगा।

1. कोरबा जिले के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन।
2. कोरबा जिले के पर्यटन केन्द्रों की वर्तमान दशा का अध्ययन एवं नवीन पर्यटन स्थलों की पहचान।
3. पर्यटन केन्द्रो की प्रत्याशा एवं सम्भाव्यता का आंकलन एवं मापन।
4. कोरबा जिले में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन।
5. समस्याओं का आंकलन एवं विकास हेतु सुझाव एवं आयोजन प्रस्तुत करना।

4. शोध परिकल्पना :

प्रस्तुत शोध पत्र में जिले में पर्यटन की सम्भाव्यता एवं प्रत्याशा के अध्ययन एवं मापन निम्नलिखित परिकल्पनाओं की जांच के आधार पर किया जायेगा। .

1. पर्यटन, मार्ग एवं सुविधाओं के विकास से पर्यटन,उद्योग के रूप में विकसित होता है।
2. शासकीय रूचि एवं प्रचार–प्रसार से पर्यटन के प्रति बाह्य आकर्षण उत्पन्न होता हैं ।
3. शिक्षा के विकास से पर्यटन का विकास होता है ।

5. शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध पत्र को तथ्य पूर्ण एवं प्रामाणिक बनाने प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं एवं जानकारियों को आधार बनाया गया हैं। प्राथमिक आंकड़े अनुसूची, साक्षात्कार, एवं फोटोग्राफी द्वारा संग्रहण किया गया है।

6. कोरबा जिले के पर्यटन स्थल:

कोरबा जिले में छोटे बड़े कुल 20 पर्यटन स्थल है उनकों विशेषताओं के आधार पर ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक, औद्योगिक, प्राकृतिक, ईको पर्यटन, मनोरंजन, स्थानिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन आदि वर्गो में बांटा जा सकता (सारणी–1 एवं मानचित्र–1) है।

कोरबा जिले की लोककला हजारों वर्ष प्राचीन है। लोककलाओं में जन समूह के धार्मिक विश्वास, रहन–सहन, आचार–विचार तथा उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कोरबा जिला के लोक कला में बार नृत्य, कर्मा नृत्य सुआनृत्य महत्वपूर्ण है। यहों मेला, उत्सव, नवरात्रि, हनुमान जंयती, कोसा वस्त्र (हस्त शिल्प कला) प्रसिद्ध है।

सारणी–1

कोरबा जिला : पर्यटन स्थलों का तहसीलवार विवरण एवं स्थिति विस्तार

क्र.	पर्यटन स्थल	तहसील	भौगोलिक स्थिति विस्तार	समुद्र सतह से औसत ऊंचाई मीटर में	पर्यटन का प्रकार	पहुंच मार्ग
1	पाली	पाली	22° 22' N 82° 18' E	320	ऐतिहासिक शिव मंदिर	बिलासपुर–अम्बिकापुर
2	लाफा (चैतुरगढ़)	पाली	22° 30' N 82° 18' E	988	पुरातात्विक गढ़ (किला) देवी मंदिर	पाली–लाफा
3	तुम्मान जटाशंकरी जलप्रपात	कटघोरा	22° 33' N 82° 27' E	723	प्राकृतिक सौंदर्य पुरातात्विक गढ़ जल–प्रपात (ऊंचाई 15 मी.)	बिलासपुर–कटघोरा–चुर्री
4	कटघोरा	कटघोरा	22° 30' N 82° 32' E	328	मंदिर एवं प्राकृतिक सौंदर्य	बिलासपुर–कटघोरा
5	मिनीमाता हसदेव बांगो जलाशय	पोंड़ी उपरोड़ा	22° 36' से 23° 12' 81° 28' से 82° 52'	304	कृत्रिम बांध, विद्युत उत्पादन केन्द्र	बिलासपुर–अम्बिकापुर
A	बांध एवं (विद्युत उत्पादन क्षेत्र)		22° 36' N 22° 35' E		बोटिंग प्राकृतिक सौंदर्य बोटिंग प्राकृतिक सौंदर्य	
B	बुका नौका विहार		22° 45' N	559	बोटिंग-प्राकृतिक सौंदर्य	
C	टिहरी सरई (नौका विहार)		82° 30' E		बोटिंग प्राकृतिक सौंदर्य	
D	सतरेंगा (नौका विहार)		22° 34' N	760		कोरबा–देवपहरी
E	बोडानाला		82° 43' E			
6	मातिनगढ़	पोंड़ी उपरोड़ा	22° 44' N 82° 28' E	533	प्राचीन किला देवी मंदिर	बिलासपुर–चिरमिरी
7.	केन्दई (मनियारी नदी) जल प्रपात	पोंड़ी उपरोड़ा	22° 44' N 82° 35' E	409	जल–प्रपात (ऊंचाई 17 मी.)	बिलासपुर–अम्बिकापुर
8.	कोसगाईगढ़ [illegible]	कोरबा	22° 31' N 82° 40' E	530	प्राचीन किला देवी मंदिर	कोरबा–देवपहरी
9.	देवपहरी महादेव पहाड़	कोरबा	22° 37' N 82° 46' E	989	आस्था एवं प्राकृतिक सौंदर्य	कोरबा–देवपहरी

ISSN No. 2347-2088

New Frontiers Of Research Vol. 3 Dec. 2016

10	अरसिया जल–प्रपात	पोढ़ी उपरोड़ा	22° 44' N 82° 44' E	473	जल–प्रपात (ऊंचाई 30 मी.) लोरमी घाटा	बिलासपुर–अम्बिकापुर
11	कोरबा नगर (एन.टी.पी.सी., बाल्को, रीवा मढ़ी, सर्वमंगला मंदिर, हसदो बराज)	कोरबा	22° 21' N 82° 44' E	289	औद्योगिक पर्यटन	बिलासपुर–कोरबा, चाँपा–कोरबा
12	कुदुरमाल	कोरबा	22° 10' N 82° 44' E	288	कबीर पंथी प्राचीन तीर्थ	चाँपा–कोरबा
13	कनकी	करतला	22° 13' N 82° 40' E	257	स्वयंभू महादेव एवं प्रवासी पक्षी	चाँपा–कोरबा
14	मड़वारानी	करतला	22° 12' N 82° 41' E	670	देवी मंदिर	चाँपा–कोरबा
15	छुरी	कटघोरा	22° 29' N 82° 35' E	369	कोसा वस्त्र बाजार	बिलासपुर–कोरबा

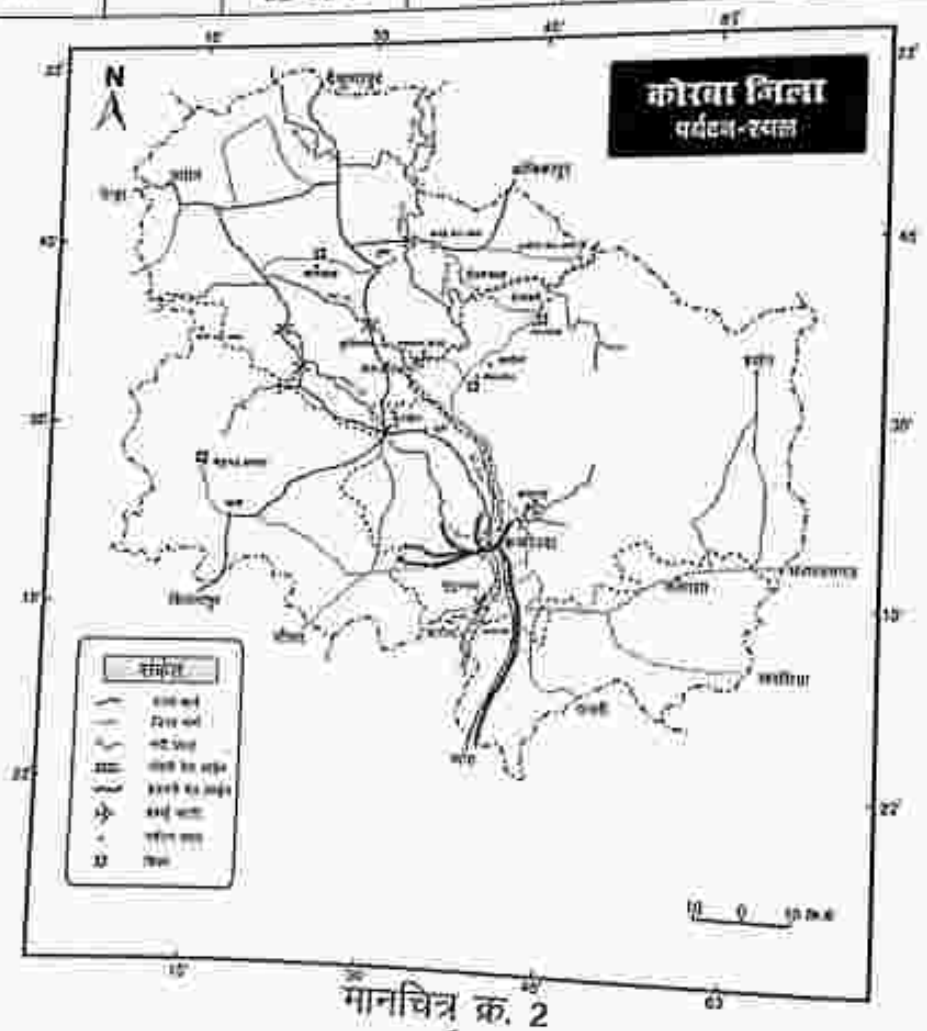

मानचित्र क्र. 2

7.पर्यटन सम्भाव्यता का मापनः

एक पर्यटक जब किसी पर्यटन स्थल का पर्यटन करना चाहता है तो उसे कई कारक प्रभावित करते है। अधोसंरचना, सेवा एवं सुरक्षा आधारभूत आवश्यकता, लागत मूल्य एवं पर्यटन स्थल की प्रकृति आदि प्रमुख कारक पर्यटक को किसी पर्यटन स्थल के चयन हेतु प्रभावित करती है इनमें से सभी कारको को पर्यटन अपनी सोच और समझ के अनुसार अलग–अलग महत्व एवं श्रेणी प्रदान करता है। अध्ययन क्षेत्र कोरबा जिला के अलग–अलग पर्यटन स्थलों में उत्तरदाता पर्यटकों से उनकों प्रभावित करने वाले कारकों के सम्बंध में प्रश्न पुछा गया सभी उत्तरदाता पर्यटकों ने प्रभावित करने वाले कारकों को अलग अलग श्रेणी (Rank) प्रदान किया। (सारणी 2) उत्तरदाता की श्रेणीकरण के आधार पर गेरीट रैकिंग तकनीक(Garretts Ranking Technique) से उत्तरदाता पर्यटकों प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक (Most significant factors) ज्ञात किया गया है और निम्न सुत्रानुसार पर्यटकों को प्रभावित करने वाले कारकों की प्रतिषत स्थिति (Percentage Position) ज्ञात कर गेरीट अंक (Guarret Score) में बदला गया है इसके बाद प्रत्येक कारक के गेरीट अंक को औसत मूल्य में बदलकर रैंक का निर्धारण किया गया है –

सूत्र (Formula)

Percent Position = 100 (Rij-0.5) / Nj

Where,

Rij = Rank given for the ith factor by the jth respondents

Nj = Number of factors ranked by the jth respondents

सारणी : 2

कोरबा जिला : पर्यटन हेतु प्रभावित करने वाले कारकों का प्रतिदर्श उत्तरदाता पर्यटकों द्वारा श्रेणीकरण

क्र.	कारक	रैंक						कुल
		I	II	III	VI	V	VI	
1	अधोसंरचना	12	19	20	18	21	30	120
2	सेवा एवं सुरक्षा	28	27	19	16	12	16	120
3	आधारभूत आवश्यकता	17	19	26	20	29	09	120
4	लागत मूल्य	16	17	21	30	24	12	120
5	प्रकृति	14	18	24	28	21	15	120
6	सम्पूर्ण संतुष्टि	09	11	20	23	32	25	120
गैरिट सारणी मूल्य		77	63	54	46	36	23	

ISSN No. 2347-2685

सारणी : 3

गेरिट रैंकिंग तकनीक चयनित कारकों का परिणाम

क्र.	कारक	अंक						गेरिट अंक	औसत अंक	गेरिट रैंक
		I	II	III	IV	V	VI			
1	अधोसंरचना	924	1197	1080	828	756	690	5475	45.62	V
2	सेवा एवं सुरक्षा	2156	1701	1026	828	432	368	6511	54.25	I
3	आधारभूत आवश्यकता	1309	1197	1404	920	1044	207	6081	50.67	II
4	लागत मूल्य	1232	1071	1134	1380	864	276	5957	49.64	III
5	प्रकृति	1078	1134	1296	1288	756	345	5897	49.14	IV
6	सम्पूर्ण संतुष्टि	693	693	1080	1058	1152	575	5251	43.75	VI

सारणी कमांक 3 के अनुसार गेरीट रैंकिंग चयनित कारकों का परिणाम में गेरीट अंक (Garrett score) एवं औसत अंक (Average Score) प्रतिदर्श उत्तरदाता पर्यटकों ने सबसे अधिक सेवा एवं सुरक्षा (54.25%) को प्रदान किया है तथा इसके बाद दूसरा आधारभूत आवश्यकता (50.67 प्रतिशत) एवं तीसरा लागत मूल्य (49.64 प्रतिशत) को दिया है और सबसे कम सम्पूर्ण संतुष्टि (over all satisfaction) को (43.75 प्रतिशत) दिया है। अतः उत्तरदाता पर्यटकों के अनुसार कोरबा जिला में पर्यटन सम्भावयता बढाने हेतु सेवा सुरक्षा आधारभूत आवश्यकता एवं लागत मूल्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

8. जिले में पर्यटन विकास की समस्याऐं एवं सुझावः

मैक्समूलर ने कहा था कि "यदि मुझे विश्व में प्रकृति पदत्त सुन्दरता शक्ति और सभी प्रकार की संपत्ति से पूरी तरह समृद्ध राष्ट्र ढूंढने के लिए कहा जाए तो मै भारत की ओर इशारा करूंगा।" मैक्समूलर की इस कथन को पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि भारत में पर्यटन विकास की अत्यधिक संभावनाएं है।

भारत का छत्तीसगढ़ राज्य और इसका कोरबा जिला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। जिला के हरे भरे जंगल वन्यजीव, जलप्रपात, गुफा, पर्वत, जलाशय तथा प्राचीन एवं नवीन सांस्कृतिक सौन्दर्य को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने पर पर्यटन सम्भाव्यता (Potentials) निश्चित ही तेजी से बढ़ेगी और भविष्य में अधिक संख्या में यहां पर्यटक आने लगेंगे। जिले में पर्यटन विकास की निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं है।

1. जिला में स्थित छत्तीसगढ़ के प्राचीन गढ़ चैतुरगढ़ एवं कोसगईगढ़ तथा गड़वारानी इस समय सर्वाधिक लोगों का आस्था एवं विश्वास का केन्द्र है इन तीनों स्थानों में देवी का प्राचीन मंदिर है किन्तु इन स्थानों की यातायात सुविधा संतोशजनक नहीं है।

1. छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बहुददेश्यीय मिनीमात हसदेव जलाशय कोरबा जिला में विस्तष्त है। इस जलाशय में पर्यटन की असीमित सम्भावनाएं है। किन्तु इस जलाशय में सुरक्षित तैराकी, हाऊस बोट, जलाशय के मध्य चारों ओर जल से घिरे पहाड़ों का सौन्दर्यीकरण तथा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास बनी जायक बाड़ी परियोजना (गोदावरी नदी) की तरह पक्षी अभ्यारण्य जैसी अतिरिक्त आकषर्ण एवं सुविधा पर्यटकों की मांग है जिसका सरकार योजना मात्र बनाई है?

2. पाली एवं कनकी में जिला के प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है, किन्तु ये दोनों मंदिर असुरिक्षित है। पाली के शिवमंदिर से आये दिन बहुमूल्य मूर्तियों (परिक्षिस्त) की चोरी होती रहती है। जबकि कनकी के स्वयंम्भू शिवलिंग में निरस्तर जलाभिषेक के कारण क्षरण तीव्र गति से हो रहा है शिवलिंग में क्षरण के कारण बड़ा छिद्र बन गया (छायाचित्र) है इसकी रोकथाम के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा कनकी पहुंचने हेतु मार्ग कच्चा है। तथा यहाँ के प्रवासी पक्षियों के संबंध में

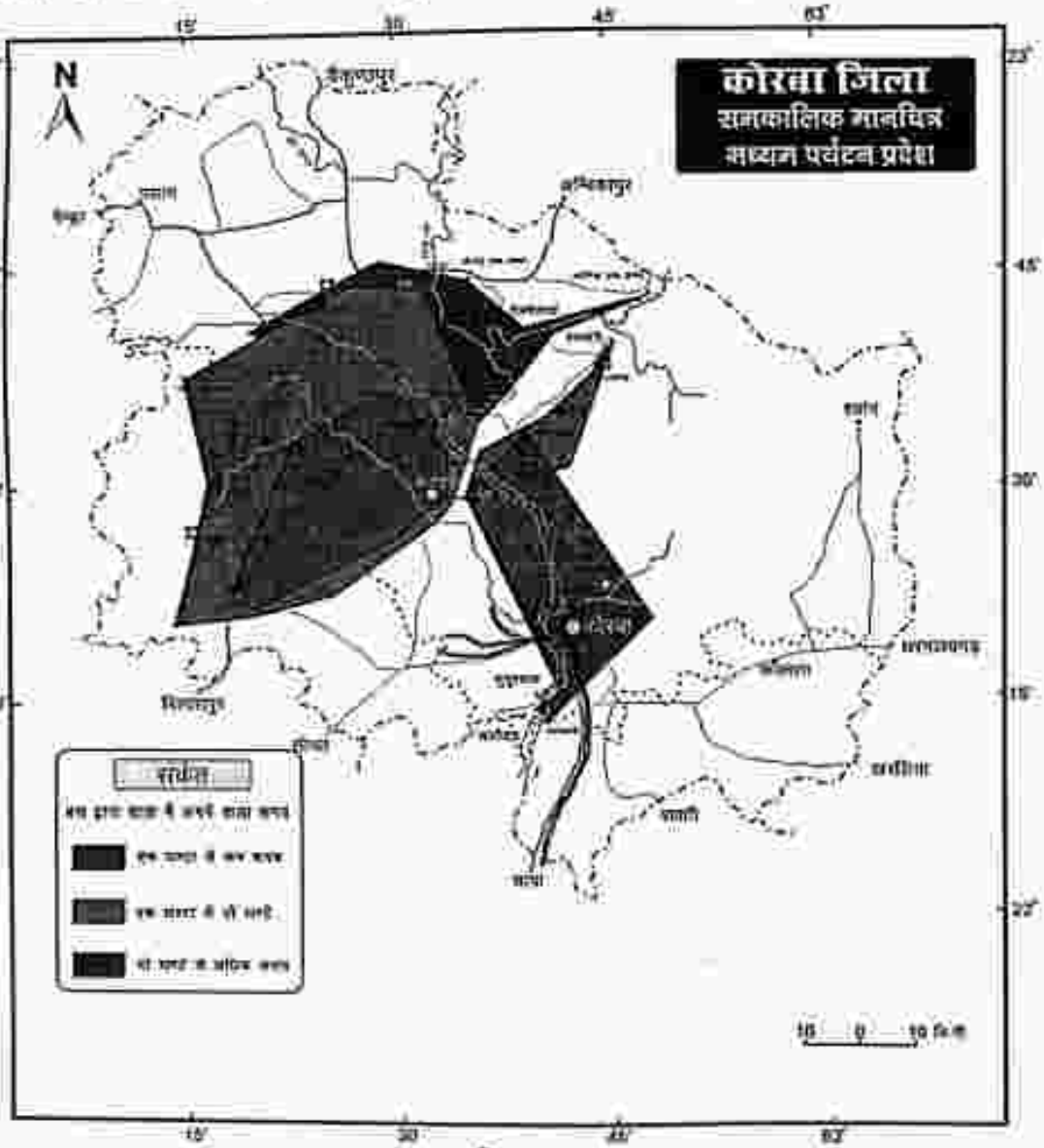

मानचित्र क्र. – 3

ISSN No. 2347-2685

पर्यटकों को ठीक से ज्ञान नहीं है।

3. जिला को प्रसिद्ध बार नृत्य, जसगीत के साथ जवारा विसर्जन, सुवानृत्य, कर्मा नृत्य, जड़ी बुटी शैलचित्र सँर्क आर्ट आदि सांस्कृतिक विरासत को अब तक सुनियोजित ढंग से प्रकाश में नहीं लाया गया है।

4. जिले के प्राय: सभी पर्यटन स्थलों में अतिरिक्त आकर्षण जैसे संग्रहालय गार्डन जू दर्शनीय स्थलों पर पोस्टर, बाजार, सुरक्षा, गाईड, बिजली आदि का अभाव है। गाईड के अभाव में पर्यटक पर्यटन स्थल का अधूरा दर्शन करते है ऐसा साक्षात्कार के दौरान ज्ञात हुआ।

5. स्थानीय लोग, एस.ई.सी.एल. चेम्बर ऑफ कामर्स, एन.सी.पी.सी. स्टारलाइट (बालकों) आदि का जिले में पर्यटन विकास के प्रति चेतना एवं अभिरूची की कमी है।

6. ट्रैकिंग (पैदल) पर्यटन, पर्वतारोहण (रॉक क्लाइविंग) भूपर्यटन (ज्योग्राफिक टूरिज्म) कारवां पर्यटन की अपार सम्भावना है परन्तु इस दिशा में अभी तक कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है।

7. जिले में विद्यमान पर्यटन स्थलों का बाजारीकरण प्रचार–प्रसार एवं वेवसाइट में प्रदर्शन नहीं किया गया है।

8. किसी पर्यटन स्थल के विकास में पर्यटन एवं आवास लागत मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रेल सुविधा कोरबा जिले के मात्र दो पर्यटन स्थलों में है। शेष पर्यटन स्थलों में या यह कहे कि अधिकांश पर्यटन स्थलों में निजी वाहन या किराये की वाहन से पर्यटन करना पड़ता है तथा आवास सुविधा सीमित है अत: परिवहन एवं आवास के लिए पर्यटकों को अधिक पैसे व्यय करने पड़ते है। इस प्रकार जिला के पर्यटन स्थलों का पर्यटन करने में लागत अधिक आता है जिस कारण से ज्यादातर लोग यहां पर्यटन नहीं कर पाते है।

9. जिले के प्रमुख पर्यटक स्त्रोत बिलासपुर, जांजगीर, चाम्पा, रायगढ़, अम्बिकापुर, कोरिया, रायपुर, दुर्ग आदि जिले एवं उनके प्रमुख नगर है किन्तु इन पर्यटन स्त्रोतों से पर्यटन ट्रेवल एजेन्सी की सुविधा आज भी नहीं है।

10. जिले में परम्परागत व्यवसाय कृषि, वनोपज संग्रहण, मत्स्यभारण, खनन एवं खनिज संसाधनों से संबंधित व्यवसायों में 95–98 प्रतिशत लोग संलग्न है रोजगार एवं आय के नये स्त्रोत पर्यटन के प्रति अभिरूची एवं चेतना लोगो में नगण्य है।

11. निजी टैक्सी चालक, होटल मालिक, पर्यटन से संबंध शासकीय एवं अशासकीय कर्मचारियों एवं सेवक फोटोग्राफर आदि की पर्यटकों के साथ व्यवहार एवं विश्वसनीयता बढ़ाने की आवश्यकता है।

12. राज्य शासन पर्यटन विकास हेतु तरह–तरह की नीतियॉं बनाई है किन्तु उसकी जानकारी और कियान्वयन समुचित ढंग से नहीं हो रहा है।

सुझाव:

छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा जिला इतिहास प्रसिद्ध कलचुरि राजवंश की प्रथम राजधानी रही है। यहां ऐतिहासिक,

पुरातात्विक, धार्मिक/ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार के पर्यटन स्थल मौजूद हैं। यहां के सुन्दर और मनोरम जल प्रपात, हरे भरे घने जंगल एवं वन्य जीव, सुन्दर जलाशय, प्राचीन किला एवं मठ, शिव मंदिर, देवी देवता के मंदिर, प्रवासी पक्षी, रॉक आर्ट (शैलचित्र), गुफा, आदिवासी नृत्य, जड़ी बूटी, कोरबा स्थित विशाल विद्युत एवं एल्युमिनियम संयत्र कोयला खदान आदि में पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार संभावनाएं हैं। जिले पर्यटन की सम्भावना को बढ़ाने के लिये आज आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों और प्रशासन को सुनियोजित ढंग से इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की और जिले की खूबियों को पर्यटकों के समक्ष उचित ढंग से प्रस्तुत करने की जिले में पर्यटन विकास हेतु निम्न बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है-

1. कोरबा जिले को अवकाश कालिन (Holiday Tourism) पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए पर्यटन स्थलों को आकर्षक एवं सुविधा जनक बनाने के लिए सरकार को आधारभूत संरचना विशेषकर परिवहन मार्ग एवं सुरक्षा का आवश्यक विकास करना चाहिए।

2. स्थानीय लोग, चेम्बर ऑफ कामर्स, एस.ई.सी.एल., स्टार लाइट (बालको) एन.टी.पी.सी. एवं सरकार को पंचायत, विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय समिति बनाकर पर्यटन स्थलों में अतिरिक्त आकर्षण जैसे हाउस बोट, ट्रेवल एजेन्सी, पक्षी अभ्यारण्य, जड़ी बूटी का उद्यान में होटल, धर्मशाला, बाजार, बिजली आदि का विकास करना चाहिए।

3. पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोग एवं स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार एवं लाभ कमाने के नये पर्यटन उद्योग से जुड़ने हेतु सरकारी सहायता एवं प्रोत्साहन मिलना चाहिये तथा उनमें जागृति लाना चाहिए।

4. स्थानीय पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को पर्यटकों के साथ व्यवहार एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के बीच अन्तर्सम्बन्ध विषय पर समय-समय पर सेमीनार एवं वर्कशाप का आयोजन कर व्यक्तित्व का विकास एवं चरित्र का निर्माण करना चाहिए और अतिथि देवो भवः की विचारधारा को चरितार्थ करना चाहिए।

5. ट्रेवल एजेन्सी एवं पत्र पत्रिका का विकास कर परिवहन लागत को कम किया जा सकता है। अतः इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।

6. जिला के पर्यटन स्थलों की खूबियों को वेबसाइट, पोस्टर, दूरदर्शन समाचार पत्र के माध्यम से पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7. जिला में पर्यटन के प्रति आकर्षण चेतना जागृत करने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को जिला में पर्यटन विकास की संभावना एवं सम्भावनाएं विषय को पाठ्य पुस्तक में जोड़कर अध्ययन कराया जाना चाहिए।

8. जिला में पर्यटन का सुनियोजित एवं शाश्वत विकास करने हेतु विकसित पर्यटन स्थलों का अनुकरण करना चाहिए।

9. कोरबा जिला में कुदुरमाल कबीर पंथियों का सबसे प्राचीन तीर्थ है इस पर्यटन केन्द्र में घरेलू एवं विदेशी दोनों पर्यटकों तरह के पर्यटक आते है। हेतु यहां सुविधाओं का विकास एवं प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

10. छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन नीति में प्रदेश एवं कोरबा जिला के पर्यटन विकास हेतु बहुत सारे नीतियों एवं योजनाएं बनाई गई है किन्तु कई योजनाओं का अभी तक कियान्वयन नहीं हो पाया तथा नीतियों से आम लोग अपरिचित है ऐसी स्थिति में सरकार और पर्यटन मण्डल को अपनी नीतियों एवं योजनाओं के बारे में ग्राम पंचायत स्तर पर एवं लोगों तक प्रचार–प्रसार करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

Mishra R.P. (1990) : Tourism complex planning : A case study of karnataka meso complex neography of the mountains heritage publishers New Delhi p 266- 277

दास गुप्ता पापिया (2004) : पर्यटन एक अध्ययन म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल (म.प्र.)

Bhatia A-K (2006) : International Tourism management Sterling publishers New Delhi

Bhatia AK (2010) : Tourism Development Principales Practices sterling publishers New Delhi

Swain S.K. (2012) : Tourism Principles and Practices oxford university prass New Delhi

Singh L.K. (2008) : Fundamental of tourism & Travel Isha books Delhi.

Singh L.K. (2008) : Indian Cultural Hevitage Perspective for Tourism Isha Books Delhi.

व्यास राजेश कुमार (2008) : भारत में पर्यटन विद्या विहार, नई दिल्ली

त्रिपाटी के एवं (2003) : छत्तीसगढ़ एटलस एस शारदा पब्लिकेशन बिलासपुर (छ.ग.)

चन्द्राकर पी.
चन्द्राकर पी एवं (2010) : अमरकंटक वैभव मृत्युन्जय प्रकाशन मृत्युन्जय आश्रम अमरकंटक (म.प्र.)

चन्द्राकर पी. अहमद एम. (Sept. 2009) : Rural Tourism Development in Bilaspur District (C.G.) A Geographical Study uttar Bharat Bhoogol Patrika The Association of Novik Indian Geographers Gorakhpur (U.P.) P 94-98

डॉ. पी.एल. चन्द्राकर, भूगोल विभाग,
सीएमडी पीजी महाविद्यालय, बिलासपुर छ.ग.

मनरेगा का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में

डॉ. आदित्य कुमार दुबे , कु.ऋचा श्रीवास्तव

प्रस्तावना

आजादी के 69 वर्षों में भारत देश ने निरन्तर प्रगति की है परंतु आज भी हमारा देश पूर्ण विकसित नही हो पाया है । भारत गांवों का देश है, आज भी भारत की लगभग 68.84 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। यदि हमें देश का पूर्ण रूप से विकास करना है तो हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत एवं विकसित करना होगा। निरंतर बिकास के पथ पर अग्रसर इस देश में आज भी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान अब तक नही हो पाया है, उनमें सबसे प्रमुख समस्या गरीबी और बेरोजगारी की है । बेरोजगारी की गंभीर समस्या पर भारत में गंभीरतापूर्वक दीर्घकालिक नीति नही अपनाई गई है, इस संबंध में तदर्थ एवं तात्कालिक नीति ही अपनाई जाती रही है । भारत में रोजगार वृद्धि संबंधी नीति पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा लागू की गई ।

पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कई रोजगार संबंधी विशेष कार्यक्रम चलाए गए जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY), जवाहर रोजगार योजना (JRY), जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना (JGSY), रोजगार आश्वासन योजना, काम के बदले अनाज योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण युवक रोजगार प्रशिक्षण योजना (TRYSEM) इत्यादि । विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर एवं विकास के अनवरत प्रयासों के बावजूद बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं निकल पाया है।

गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा एक पहल की गई । सन् 2005 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट' की शुरूआत की गई । इसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया और 7 सितंबर 2005 से लागू किया गया । सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरूआत आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई । 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट' (मनरेगा) कर दिया गया ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, दाउ कन्याण सिंह भवन, रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1069/वि–3/रा.ग्रा.रो.गा.यो./2006 दिनांक 3 मार्च 2006 –राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त अधिनियम की धारा

ISSN No. 2347-2685

New Frontiers Of Research Vol. 3 Dec. 2015

3 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के लिए प्रकाशित करती है ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट सिर्फ एक योजना या कार्यक्रम नही है बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है । यह कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से भिन्न है क्योंकि इसमें रोजगार की कानूनी गारंटी है । इस एक्ट को संसद द्वारा पारित करके विधान द्वारा अधिनियमित किया गया है । इस एक्ट के तहत ग्रामीणों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई है । यह एक ऐसा अधिनियम है जिसमें रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है ताकि सभी ग्रामीणों को रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराए जाएं और वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र और आवास को पूरा कर पायें ।

उद्देश्य

इस एक्ट का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन पाने का अधिकार होगा। मजदूरी भुगतान में लिंग भेद नही किया जाएगा अर्थात महिला एवं पुरूष में कोई भेद–भाव नही होगा। सभी को समान मजदूरी दी जाएगी। मजदूरी का भुगतान समय दर पद्धति या कार्य दर पद्धति से किया जाएगा।

इस एक्ट के निम्नलिखित उद्देश्य है –

- इस एक्ट का उद्देश्य लोगों को आवेदन करने के 15 दिन के अंदर 100 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना है।
- यदि 15 दिन के अंदर रोजगार नही मिलता है तो उन्हे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का प्रावधान है।
- हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी 167 रू. प्रतिदिन पाने का अधिकार है।
- लोगो को गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में काम उपलब्ध कराया जाएगा ।
- यदि कार्य 5 कि.मी. से ज्यादा दूरी पर हो तो अतिरिक्त भाड़े और व्यय के लिए, न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी । इस योजना के अंतर्गत एक तिहाई महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ।
- श्रमिको की हाजरी का रिकार्ड नियमित रूप से रखे गए मस्टर रोल से जांचा जाएगा।

यह एक्ट पंचायती राज संस्थान द्वारा संचालित होता है। पंचायती राज संस्थान ग्रामीण देश में स्थानीय शासन का निकाय है जो प्रशासन के तीन स्तरों गांव, ब्लॉक और जिला के रूप में काम करता है। यह एक्ट पांचों स्तरों पर कार्य करता है ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और केन्द्र स्तर पर।

कार्य – क्षेत्र

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई जिसे 2007–08 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक अंततः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। इस शोध अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों से आठ ग्रामों का चयन किया गया है।

परिकल्पनाएं

शोध पत्र में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है –

- छत्तीसगढ़ राज्य में इस एक्ट के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान समय पर होता है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कम हुआ है।
- हितग्राहियों की षिकायत निवारण का प्रावधान है।

समंको का संकलन

इस शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक समंकों का संकलन किया गया है। प्राथमिक समंकों का संकलन अनुसूची एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा किया गया है। अध्ययन के लिए वर्ष 2015–16 को शामिल किया गया है।

क्रियान्वयन

अधिनियम की धारा 13 (1) के अनुसार योजना के क्रियान्वयन एवं नियोजन हेतु ग्राम/ जनपद/ जिला पंचायतें प्रमुख संस्थायें होंगी । योजनान्तर्गत लागत के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये जायेंगे । शेष कार्यों का क्रियान्वयन अन्य एजेंसियों द्वारा किया जायेगा ।

अधिनियम की धारा 14 (6) के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रतिवर्ष जिले के लिए लेबर बजट तैयार किया जायेगा तथा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिला पंचायत को कार्य योजना प्रस्तुत की जायेगी।

इस एक्ट के क्रियान्वयन हेतु भारत शासन द्वारा अलग से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् स्थापित किया गया है। जिसके माध्यम से भारत शासन द्वारा राज्यों को राशि प्रदान की जायेगी । राज्यों को समय–समय पर यह राशि भारत शासन के नियमों के तहत प्राप्त होगी । इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी छत्तीसगढ़ निधि नियम, 2011" बनाया गया है जो जारी अधिसूचना क्रमांक 441/पं. ग्रा. वि. वि./22/2012 दिनांक 6 मार्च 2012 – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 32 (2) खण्ड (ड़) (च) एवं धारा 21 (1), (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बना है ।

इस एक्ट के तहत बेरोजगारी भत्ते की दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार निश्चित करेगी ।

इस एक्ट के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक श्रमिक को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी पाने का हक है। मजदूरी भुगतान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को राशि का आवंटन किया जाता है और उसी आधार पर लोगों को रोजगार दिया जाता है। इसकी जानकारी निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है–

तालिका – 1 : छत्तीसगढ़ राज्य – वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वर्ष 2015–16

क्रमांक	विवरण	राशि
1.	उपलब्ध राशि	20,41,14,257
2.	रोजगार कार्ड वितरण पंजीकृत परिवारों की संख्या	39,68,221
3.	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	1,10,54,430
4.	जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या	39,01,459
5.	परिवारों द्वारा रोजगार की मांग	26,11,916
6.	व्यक्तियों द्वारा रोजगार की मांग	55,88,747
7.	परिवारों को उपलब्ध कराया गया रोजगार	26,10,531
8.	व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया रोजगार	55,84,424

इस एक्ट की धारा 21 की उपधारा–1 के अंतर्गत कियान्वयन करने वाले राज्य में योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से राज्य, रोजगार गारंटी परिषद् की स्थापना करता है। मनरेगा 2005 की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारों को रोजगार गारंटी निधि नियमों को अधिसूचित करने की आवश्यकता होती है ।

जिला कार्यक्रम समन्वयक की सहायता के लिए कार्यक्रम अधिकारी और जिले के भीतर कार्य कर रहे राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों तथा निकायों के सभी अन्य अधिकारी धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए जायेंगे ।

छत्तीसगढ़ राज्य में 27 जिले, 146 विकासखण्ड और 10971 ग्राम पंचायतेंहैं जहां मनरेगा एक्ट सफलतापूर्वक संचालित है। मनरेगा एक्ट से संबंधित जानकारी तालिका क्रमांक 2 में दर्शित है –

तालिका – 2 : छत्तीसगढ़ राज्य –जॉब कार्ड संबंधित विवरण वर्ष 2015–16

क्रमांक	विवरण	राशि (लाख में)
1.	कुल जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या	36.79
2.	मजदूरों की कुल संख्या	89.73
3.	कार्यशील जॉब कार्डो की कुल संख्या	30.57
4.	कार्यशील मजदूरों की कुल संख्या	56.37
5.	100 दिन मजदूरी पूरा करने वाले परिवारों की संख्या	2,42,580

अध्ययन का निष्कर्ष–

तालिका 1 के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2015–16 में छत्तीसगढ़ राज्य को 20,41,14,257 राशि प्राप्त हुई। राज्य में रोजगार कार्ड वितरण पंजीकृत परिवारों की संख्या 39,68,221 है। जिनमें 26,11,916 परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गई लेकिन 26,10,531 परिवारों को ही रोजगार प्राप्त हो सका और राज्य में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 1,10,54,430 है जिनमें 55,88,747 व्यक्तियों द्वारा रोजगार की मांग की गई और 55,84,424 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया।

तालिका 2 के अध्ययन से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2015–16 में इस एक्ट के तहत 36.79 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए तथा मजदूरों की कुल संख्या 89.73 लाख है। जारी किए गए जॉब कार्ड में से 30.57 लाख कार्यशील जॉब कार्ड हैं और कुल मजदूरों में से 56.37 लाख कार्यशील मजदूर हैं परंतु 100 दिन मजदूरी करने वाले परिवारों की संख्या सिर्फ 2,42,580 है । संबंधित ग्राम सर्वेक्षण से पता चला कि एक्ट में 150 दिन कार्य देने का जो उल्लेख है उसका पूर्ण पालन नही हुआ । अनेक हितग्राहियों को मात्र 100 दिन ही कार्य दिवस प्राप्त हुआ।

इस शोध अध्ययन के लिए हमने गांवों में जाकर 200 से अधिक लोगो से अनुसूचियां भरवाई और उनके व्यक्तिगत साक्षात्कार भी लिए। संबंधित ग्राम के सचिव और सरपंच से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की । इससे अनेक तथ्य हमारे सामने आए जैसे– मनरेगा एक्ट के अंतर्गत मजदूरों को आवेदन के 15 दिन के अंदर कार्य उपलब्ध कराने का नियम है परंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा नही होता है। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य का निर्धारण कर राज्य शासन से अनुमोदित करकर ऐसे समय में जब उन्हें अपने कृषि कार्य की व्यस्तता नही होती है तब निर्धारित कार्य की मुनादी

ISSN No. 2347-2085

कराई जाती है। इसका प्रबंध स्थानीय स्तर पर होता है एवं सहभागिता से होता है। अतः इस प्रक्रिया से हितग्राही पूर्णतः संतुष्ट एवं खुश हैं।

हितग्राहियों को कार्य करने के पश्चात समय पर मजदूरी नही मिलती है जिसके कारण वे दूसरी जगह कम मजदूरी पर भी कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं तथा वे गांव छोड़कर बाहर जाकर कार्य करने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं। अतः मजदूरी की निश्चितता होनी चाहिए जिससे हितग्राहियों की आर्थिक संतुष्टि हो सके।

इस अध्ययन से यह भी सामने आया कि किसी भी हितग्राही को बेरोजगारी भत्ते की जानकारी नहीं है ना ही किसी ने बेरोजगारी भत्ते की मांग की है और ना ही उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हुआ है।

इस एक्ट के अंतर्गत शिकायत निवारण की व्यवस्था भी है, जिसमें हितग्राही अपनी शिकायतें निर्धारित फोन नम्बर पर कर सकते हैं, परन्तु उनकी शिकायतों का समाधान समुचित रूप से नही हो पाता। अनेक हितग्राही तो शिकायत करते ही नही हैं और जो करते हैं उनको कोई समाधान नही मिलता।

इस एक्ट से मजदूरों के पलायन में कमी तो आई है क्योंकि लोगों को अपने ही ग्राम में रोजगार उपलब्ध हो जाता है जिससे वे अपना ग्राम छोड़कर अन्यत्र नही जाना चाहते।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर पहली परिकल्पना असत्य है अतः हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान समय पर नही होता। दूसरी परिकल्पना सत्य है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन में कमी आई है। तीसरी परिकल्पना असत्य है क्योंकि हितग्राहियों की शिकायत निवारण का प्रावधान तो है पर शिकायतों का निवारण उचित प्रकार से नही होता है।

संदर्भ ग्रंथ

- रिसर्च मेथडॉलॉजी, वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा, पंचशील प्रकाशन जयपुर
- मनरेगा, डॉ. विष्णु राजगढ़िया, राजकमल प्रकाशन
- महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा I &II, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, R.K.Narula
- Dynamic Report, MGNREGA Public data portal for F.Y.2015-16 As on 1/12/2016
- www.mnregaweb4.nic.in dated as on 1/12/2016
- हितग्राहियों द्वारा संपादित अनुसूची

डॉ. आदित्य कुमार दुबे, कु.ऋचा श्रीवास्तव
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, सी.एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय

बिरहोर जनजाति का सामाजिक व आर्थिक अध्ययन

(वि.खं. कोटा जिला बिलासपुर के संदर्भ में)

श्वेता सिंह

प्रस्तावना

किसी मानव समूह को एक जनजाति मानने के लिए यथार्थ रूप से कसौटियां है, जन जातियां जाति जीवन की क्या विलक्षणा हैं। एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है, सामान्य भाषा बोलते है, और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निबंधात्मक नियमों का पालन करते है।

प्रदेश की विशेष पिछड़ी जन जाति बिरहोर मुख्यतः छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले में निवास करने वाली बिरहोर जनजाति विशेष जनजातियों में शामिल है। बिरहोर जनजाति के संबंध में ये मान्यता है कि ये जिस पेड़ को छू देते है, उस पर कभी बंदर नहीं चढ़ता है। ए.के. सिन्हा ने अपनी किताब छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातियां में बिरहोर जनजाति के विषय में विस्तार से लिखा है। बिरहोर जनजाति खाने के लिए बंदर का शिकार करती है लेकिन वो ऐसा क्यों करते है इसके पीछे भी एक कहानी है जो रामायण काल से संबंधित है।

शिकार से पहले मंत्र पढकर बुलाते है भूत बिरहो जनजाति के लोग शिकार कर जीवनयापन करते है। ये लोग मुख्य रूप से बंदर का शिकार करते है। ये लोग सामूहिक रूप से शिकार करते है। शिकार के लिए कोई निश्चित मुहुर्त या दिन नही होता। शिकार पर जाने से पहले बिरहोर लोग धार्मिक किया करते है, जिससे पता चल सके कि शिकार के लिए जानवर मिलेगा या नहीं। इसके लिए तीन आदमी एक जगह बैठते है और एक चावल लेकर थोड़ा–थोड़ा सबके हाथों में देता है। फिर सब जोहार–जोहार करके मंत्र पढते है और भूत को बुलाते है। बिरहोर का अर्थ होता है जंगल के लोग बिर का अर्थ जंगल और होर का मतलब आदमी। बिरहोर लोग छोटे कद के सिर बडा लम्बे बाल व नाक होती है। ये प्रोटो आस्ट्रेड श्रृंखला के है।

बिरहोर जनजाति अधिकांशतः झारखण्ड के निवास करने वाले है, और उनमें से कुछ लोग छत्तीसगढ़ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आ के बस गये है।

बिरहोर लगभग 10000 की जनसंख्या में है वर्तमान स्त्रोतों के अनुसार इनकी जनसंख्या कम हो गयी है। ये हिन्दू धर्म पर विश्वास करते है। वर्तमान में बिरहोर का बसाहट प्रदेश के कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, रायगढ़, बस्तर जिलें के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। बिरहोर व्यौरा खेती करते है और इनकी अर्थ व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गया है और व्यौरा खेती के कारण एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान स्थांनातरित होते रहे है और यायावर जैसे जीवन यापन

की शैली के कारण इनके सोचने समझने का ढंग व स्वभाव भी यायावर बन गया। इनके बसने व रहने का तरीका एक ग्राम के रूप में न रहकर बेहद बिखरा और बेतरतीब सा हो गया। एक बिरहोर का घर कहीं दूर घने जंगलों में तो किसी दूसरे का पहाड़ी पर तीसरे का ढलान परतों पर तो चौथे का पहाड़ी के नीचे या किसी कुंदरा में बना रहता है। घरों में आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। अधिक से अधिक एक स्थान पर या दो या तीन घर कुछ दायरों में बने होते है। इसका कारण यह है कि, विवाह के पश्चात् लडका अपनी पत्नि को लेकर दूसरा घर बनाता है।

बिरहोर बोली मुंदारी भाषाओं से मिलती जुलती है। और बिरहोर लोग छत्तीसगढी व बिरहोरी में भी बोल लेते है। हाट बाज़ार भी इनके लिए पर्व के समान है ये हाट के दिन हाट जाने से नहीं चुकते है। बिरहोर लोग डोम, चीख, घाघी, आदि जाति को छोटा मानते हुए उनके हाथ का भोजन नहीं करते है।

अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1. बिरहोर जनजाति का सामाजिक अध्ययन।
2. बिरहोर जनजाति का आर्थिक अध्ययन।

अध्ययन का महत्व :-

बिरहोर जनजाति समाज को ऊपर उठाने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाएं में इनके लिए विशेष राहत व विकासीय कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है। किन्तु इनके बावजूद भी ये समुदाय पुरानी पिछड़ी हुई स्थिति में जीवनयापन कर रहा है। चूंकि समाज में विकास में मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क की चेतना ही कार्य करती हैं। अतः इस चेतना का मूल्यांकन समय समय पर करके समाज की प्रगति का अध्ययन करना।

ये समाज सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेता है और इनका आधार एक सुदृढ़ न्यायिक व सामाजिक संगठन है किन्तु इन सबके बावजूद भी इस समुदाय के विकास का प्रवाह एक क्षेत्र तक ही सीमित है। इसके विकास की दर बहुत धीमी है इसलिए इनके सामाजिक चेनता में बंधन बने तथ्यों का अध्ययन कर उसे शोध के रूप में प्रस्तुतकर भविष्य की शासकीय योजनाओं हेतु निर्धारित कर दिशा में छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार न केवल जनजातियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है अपितु सरकारी योजनाओं के निर्धारण के क्षेत्र में भी प्रभावी व कारगर कदम साबित हो सकता है।

परिकल्पना :-

1. पहाडी बिरहोर जनजाति की शिक्षा स्थिति में सुधार होना चाहिए।
2. इस जनजाति के लोग आर्थिक जीविकोपार्जन हेतु सीमित विकल्पों में विकास होने की आवश्यकता है।
3. पहाडी बिरहोर जनजाति में नातेदारी व्यवस्था का विशेष महत्व होना चाहिए।

बिरहोर जनजाति की सामान्य विवेचना

बिरहोर भारत की प्रमुख जनजाति है मुख्यतः छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में निवास करने वाली बिरहोर जनजाति विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। बिरहोर जनजाति की संबंध में मान्यता है कि जिस पेड़ को छू जाते है। उस पर कभी बंदर नहीं चढ़ता । ए.के. सिन्हा ने अपनी किताब छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति में बिरहोर जनजाति के बारे में विस्तार से लिखा हैं ।

वर्गीकरणः– आर्थिक स्थिति के आधार पर बिरहोर के दो समूह है।

1- Uthlus : The Wandering Birhor's
2- Janghis: The Settled Birhor's

पूर्व में किये गये अध्ययन के अनुसार बिरहोर के घुमन्तू जीवन का पता चलता हैं। इन घुमन्तू बिरहोरों को 'उथलू', 'फिरता' या 'भुलन्तू' बिरहोर के नाम से जाना जाता हैं। परंतु बिरहोर जनजाति का एक समूह जिसने स्थायी जीवन पद्धति अपना ली हैं, 'जाँघी' या 'पनीया' बिरहोर के नाम से जाना जाता हैं। 'उथलू' बिरहोर वर्षा ऋतु के अतिरिक्त प्रत्येक समय एक जंगल से स्थानांतरित होते रहते हैं। जहां गए वहीं पत्तो के पीछे "सरना" देव स्थान स्थापित कर लिया, जंगलो में शिकार करने लगे, रस्सी बनाने लगे और किसी तरह अपना जीवनयापन करने लगे। उन्हें न तो अपने बिछुडे परिवार के सदस्यों की चिंता हैं और न उनसे मिलने की प्रबल अभिलाषा ही।

बिरहोर कुम्बा की स्थापना में निम्नलिखित चार कारको पर विशेष ध्यान दिया जाता हैं:–

1. वन संसाधनो का नजदीक होना,
2. पानी की आपूर्ति, झरना या तालाब के समीप होना,
3. साप्ताहिक आदिवासी बाजार के नजदीक होना,
4. सामीप्य में बसे दूसरे टंडा से दूर होना।

बिरहोर जनजाति सदियो से, शहरो से नहीं बल्कि गांवो से भी दूर गहन जंगली क्षेत्रो में सर्वथा एकांत में निवास करने की आदि रही हैं। इस कारणवश शिक्षा का प्रसार उसमें न्यूनतम हुआ हैं। यह मुख्यतः उनके जीविकोपार्जन की समस्या के कारण हुआ हैं। शिक्षा से इस कदर दूर रहने के कारण यह आधुनिक सभ्यता, जीवन शैली एवं विकास की मुख्य धारा से निरंतर दूर होते गए।

बिरहोर जनजातियो में लड़को को सत्रह–अटठारह वर्ष तथा लड़कियों को बारह–चौदह वर्ष होने पर विवाह योग्य समझा जाता हैं। विवाह के पश्चात् ही एक बिरहोर युवक को उस जनजाति का पूर्ण सदस्य माना जाता हैं। सामान्यतः इनमें एक पत्नी विवाह की ही प्रथा हैं।

अध्ययन पद्धति एवं उपकरण :–

किसी भी विषय पर अध्ययन एक निश्चित उद्देश्य के अंतर्गत किया जाता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है जब किया जाने वाला अध्ययन व्यवस्थित और योजनाबद्ध रूप से किया जाए। इस हेतु कुछ निश्चित पद्धतियों का सहारा लिया जाता है।

(क) निदर्शन पद्धति :-

प्रस्तुत अध्ययन हेतु तथ्य संकलन प्रमुख रूप से निदर्शन संकलन प्रमुख रूप से किया जाता है और इसमें उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति अपनाया जाता है। जब अनुसंधान जानबूझकर किसी निश्चित उद्देश्य हेतु समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाईयों का चुनाव करना है। तो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहते हैं।

(ख) अनुसंधान प्रारूप :-

इसमें अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रारूप लिया जायेगा। इस प्रकार के अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य एक घटना का परिचय प्राप्त करना अथवा उसके बारें में नवीन ज्ञान प्राप्त करना होता है।

(ग) तथ्यों का संग्रहण :-

प्रस्तुत शोध के अध्ययन के लिए तथ्यों का संग्रहण प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो स्त्रोतों का सहायता लिया जायेगा।

(1) प्राथमिक स्त्रोत :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक स्त्रोत द्वारा तथ्य संग्रहण के लिए निश्चित प्रश्नावली, अनुसूची भावात्कार आदि का प्रयोग किया जायेगा।

(2) द्वितीयक स्त्रोत :-

द्वितीयक स्त्रोत के अिंतर्गत विभिन्न शोध पत्रिकाओं, समाचार पत्र, पुस्तकों, शोध ग्रंथ एवं अन्य विभिन्न पत्रिकाओं का सहयोग लिया जायेगा।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय :-

बिरहोर जनजाति बिलासपुर जिले के विकासखण्ड कोटा के ग्राम सेमरिया, लूफा, उपरियापारा में बिरहोर सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है।

विकासखण्ड कोटा के चयनित ग्रामों का विवरण

विकासखण्ड कोटा 1 अप्रैल 1954 से स्थापित है। विकासखण्ड कोटा में 81 ग्राम पंचायत एवं उसके अधिनस्थ 162 ग्राम है, जिसमें से 161 राजस्व ग्राम एवं 1 वन ग्राम शामिल है। वर्तमान में विकासखण्ड कोटा की सी.एन.ए. 2011 के अनुसार सर्वेक्षित जनसंख्या 228358 है, जिसके अनुसार विकासखण्ड की लगभग 51 प्रतिशत जनसंख्या पुरूष एवं 49 प्रतिशत महिलाएँ है।

विकासखण्ड कोटा में हमनें बिरहोर जनजाति का स्वास्थ्य अध्ययन किया है, ये गांव जंगल में बसे हुए है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत आयें है।

शक्तिबहरा :-

यह गांव लूफा पंचायत के अंतर्गत आता हैं यह कोटा मुख्यालय से 35 किमी की दूरी पर है। जो जंगलों के बीच में बसा हुआ है। इस गांव की जनसंख्या 1225 है। यहाँ बिरहोर जनजाति की संख्या 30 है, जिसमें से 6 परिवार हैं। यहाँ बिरहोर जनजाति के अलावा यहाँ अन्य जाति समुदाय के लोग निवास करते है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी है। यहाँ बिरहोर जनजाति के लोग खेती एवं मजूदरी तथा अपना परम्परागत व्यवसाय करते है। यहाँ पठारी गुफा होने के कारण कृषि योग्य भूमि का अभाव है। जरूरत पडने पर किसी वस्तु के लिए बेलगहना आते

है।

सेमरिया, मांझीपारा :–

यह गांव मझगांव पंचायत के अंतर्गत आता है यह कोटा मुख्यालय से 12 किमी की दूरी पर है। जो जंगलों के बीच में बसा हुआ है। इस गांव की जनसंख्या 1925 है। यहाँ बिरहोर जनजाति की संख्या 65 है, जिसमें से 20 परिवार है। यहाँ बिरहोर जनजाति के अलावा यहाँ अन्य जाति समुदाय के लोग निवास करते है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी है। यहाँ बिरहोर जनजाति के लोग खेती एवं मजूदरी तथा अपना परम्परागत व्यवसाय करते है। जरूरत पड़ने पर किसी वस्तु के लिए कोटा आते है। जो 15 किमी की दूरी पर है।

उमरियादादर कोईलारीपारा :–

यह गांव उमरियादादर पंचायत के अंतर्गत आता है यह कोटा मुख्यालय से 38 किमी की दूरी पर है। जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। इस गांव की जनसंख्या 3514 है। यहाँ बिरहोर जनजाति की संख्या 166 है, जिसमें से 37 परिवार है। यहाँ बिरहोर जनजाति के अलावा यहाँ अन्य जाति समुदाय के लोग निवास करते है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी है। यहाँ बिरहोर जनजाति घंघोर जंगलों में रहते है यहाँ पर संचार साधन व बिजली आदि की सुविधा की कम है। यहाँ के लोग अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए चपोरा आते है। जो 10–12 किमी की दूरी पर है। इनका मुख्य व्यवसाय खेती एवं मजूदरी तथा अपना परम्परागत व्यवसाय है। यहाँ घंघोर जंगल होने के कारण कृषि योग्य भूमि का थोडा अभाव है।

निष्कर्ष

बिरहोरजनजाति समाज के सामाजिक अर्थव्यवस्था स्वरूप को पिछले अध्याय में यथा संभव प्रमाणित तौर पर बतलाने का छोटा सा प्रयास किया है, जिसे पढ़कर इस समाज की विभिन्न संगठनात्मक पक्षों की जानकारी मिल जाती है। सच है कि बिरहोरजनजाति आदि परम्परों का प्रतीक बना हुआ है। विकास के संबंध में इनकी उदासीनता इनके आर्थिक स्वरूप को धरातल से जुडी हुई है और इससे उभरना ही इनकी प्रगति के लिए बुनियादी प्राथमिकता कहीं जा सकती है।

1. यह बिरहोरसमाज जंगल व पहाड़ों के बीच रहकर जीवन बसर कर रहे है। इस समाज में दो घरों की दूरी बहुत होती है। इनमें घर परिवर्तन की अवमान्यताएँ काफी गहरे पैठ जमाये हुए है। यहाँ के घर अस्वच्छ व प्रदूषण युक्त है। यहाँ खिडकी एवं दरवाजें की व्यवस्था प्रायः नहीं है।

2. यहाँ की महिला की दिनचर्या महुआ या चरौंदा के भोजन चुनना, सुखाना, खरीफ के समय कृषि मजदूरी एवं खनवाना, निकलवाना फसल मजदूरी खुले सीजन में तेन्दूपत्ता चुनना व जलाउ लकडी चुनकर बेचना खाना बनाना एवं घरेलू कार्य करना आदि तक ही सीमित है। पुरूषों की दिनचर्या में खेती चाहे

ISSN No. 2347-2685

स्वयं की हो या मजदूरी पर हल जोतना, मजदूरी करना, स्वयं का कृषि कार्य करना, जलाउ लकडी बेचना बाकी दिनों में खेतों खोद खोदकर चुहा मार कर खाना, जंगलों में सुअर, खरगोश आदि का शिकार करना, तीन त्यौहार के अवसर में या गांठ में रूपया होने पर दारू पीना और मस्त होकर करमा और ढमचक नृत्य करते है।

3. खान पान के अंतर्गत बिरहोर औसतन आठ माह चांवल और सकडा सूटकी कान्दा खातें है। और कभी–कभी उपलब्ध होने पर आलू, बैगन, टमाटर, हरी सब्जी नया दाल भी खातें है। पर ऐसे अवसर बहुत कम आते है।

4. बिरहोर समाज मद्यपान के अंतर्गत महुआ की दारू और हडिया (चांवल की शराब) पीते है और धुम्रपान के रूप में बीड़ी, तम्बाखू का प्रयोग करते है। यहॉ स्त्री पुरूष दोनो इनका इस्तेमाल करते है। इनके सेवन में इस जनजाति समाज के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

5. यहॉ पुरूषों का पहनावा, धोती या लंगोटी, चड्डी व गंजी है, जबकि महिलाएँ धोती, साडी, ब्लाउज, पेटीकोट पहनती है। यह समाज ग्रामीण संस्कृति के प्रभाववश वस्त्र जो पहनने लगा है पर अभी भी वस्त्रों की उपयोगिता के संदर्भ में इनकी जागरूकता काफी कम है।

6. यहॉ के समाज में स्त्रियॉ हसुली, ककना, सिकडी, मुंगा, चंदवा, सिक्कों का हार, उचिया, नरकुना, कर्णफूल, चूडी, बिछिया, पैरी, बाजू, अंगूठी, आदि विशेष अवसरों पर पहनती है। इसके अतिरिक्त इस समाज मे विरासत की आस्थाओं से संबंधित लाख व मिट्टी से बनी माला भी पहनी जाती है। जिसे वे स्वयं बनाते है।

7. इस जनजाति समाज में शिक्षा की स्थिति न के बराबर है। प्रायः अधिकांश वयस्क अशिक्षित होते है। जिसकी वजह से इस समाज का विकास जड़ बना हुआ है। और लोग अंध–मान्यताओं व धार्मिक आस्थाओं के विकास के सारे प्रयासों को निरर्थक सिद्ध करने पर तुले हुए है। अतः इनकी अज्ञानता व विकास अवरोधक आस्थाओं को खत्म करने हेतु शिक्षा पर बहुत गंभीर प्रयास की आवश्यकता है।

8. इस जनजाति समाज का पारिवारिक स्वरूप अन्य समाज से कुछ भिन्नता लिए हुए है। यहॉ पर एकाकी एवं संयुक्त दोनो तरह के परिवार देखने को मिलते है। परन्तु एकाकी परिवार का ही वर्चस्व बना हुआ है। इसका कारण विवाह पश्चात् विवाहित जोडों को अलग कर घर बसा यहॉ देखने को मिलता है। इस समाज में सगाई का मोढ़ कना, बुदा भराई या मूठ बांधना जैसी शब्दावली से संबोधित किया जाता है। इस समाज की वैवाहिक व्यवस्था को व्यवस्थित एवं स्थायित्व देने हेतु इनमें फैली अज्ञानता को खत्म करने का प्रयास बहुत जरूरी है।

9. यहॉ संस्कारों के रूप में जन्म संस्कार व मृत्यु संस्कार को ले सकते है। यह संस्कार हिन्दू संस्कारों से काफी प्रभावित है। जन्म

संस्कार के अंतर्गत छट्टी रस्म, बरही रस्म, नामकरण संस्कार, घर हुकी रस्म आदि प्रमुख है। इस तरह मृतक संस्कार में तीजा रस्म, दसकर्म विशेष रूप से प्रचलित है।

10. बिरहोरसमाज का धार्मिक स्वरूप अन्य जनजातियों के समान ही जीव वाद से प्रभावित है। यहाँ के अलौकिक शक्तियाँ, भूत प्रेत पूर्वजों की आस्था का गहरा प्रभाव दिखलाई देता है। इस समाज में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं है। अपितु पूर्वजों की पूजा की जाती है। इस समाज में सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवेश आज भी अलौकिक शक्तियो में अंधविश्वासी मान्यताओं से संचालित हो रहा है। स्वास्थ्य से जुडी सभी समस्याओं का निदान इन्हीं अलौकिक शक्तियों से जुड़े तंत्र मंत्र द्वारा ढूंढा जाता है। यही वजह है कि समाज में बैगा देवार को काफी महत्व दिया जाता है, यदि वास्तव में इन जनजाति का विकास करना है तो इनमें प्रचलित अन्य आस्थाओं को जड़ों पर प्रहार करना होगा। यह कार्य वृहद्ध स्तर पर साक्षरता आदि के द्वारा किया जा सकता है।

11. इस समाज की सभी आवश्यकताओं का मूल बिन्दू इनकी आर्थिक दरिद्रता ही है। ये लोग आर्थिक जीवकोपार्जक हेतु सीमित विकल्पों पर निर्भर है। कृषि की अनिश्चितता, वनोपज का घटता स्वरूप मजदूरी के रूप में शोषण आदि अनेक अज्ञानता के कारण प्रचलित घटक इनकी अर्थव्यवस्था को जर्जर बनायें हुए है।

संदर्भ ग्रंथ

- शर्मा वीरेन्द्र प्रकाश, (1999), रिसर्च मेथडॉलॉजी, पंचशील प्रकाशन जयपुर
- तिवारी एस.के., शर्मा के. (1994), मध्यप्रदेश की जनजातियां, समाज व अर्थव्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ एकादमी, भोपाल
- हुसनैन नदीम, (1997), जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली
- चन्द्राकर पी.एल., (1994), मध्यप्रदेश के कोरवा जनजाति का सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण–एक भौगोलिक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबंध,गु.घा.दा. वि.विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

श्रीमती श्वेता सिंह, एफ.फिल.,
सी.वी.रमन वि.विद्यालय, कोटा

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना-मनरेगा की बेरोजगारी कम करने में भूमिका" (कोटा विकास खण्ड, बिलासपुर जिला के ग्राम करगीकला के संदर्भ में)

अखिलेश कुमार पाण्डेय, एम.फिल. समाजशास्त्र, शोध

प्रस्तावना

भारत के लगभग 80 प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं भारत देश पूर्वकाल से ही एक संस्कारधानी देश के रूप में जाना जाता है । यहाँ के लोग जितने ही संस्कारवान हैं उतने ही मानवतावाद के भी पुजारी हैं। भारत चूंकि गांवो का देश है इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा लोग गांवों में निवास करते है। गांवों में रहने वाले को जीवन यापन करने हेतु किसी व्यवसाय के माध्यम से अपनी रोजी–रोटी चलाना होता है। परन्तु उसके बाद भी वह अपने आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं ला सकता है। जिससे वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या ग्रामीण अंचल में व्यापक रूप से बढ़ती जा रही है।

तब भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगो के लिए एक ऐसे अधिनियम की शुरूआत की गई जिसके माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा सन् 2005 में लागू किया गया जिसका नाम "राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम" था जिसका नाम परिवर्तित होकर 2009 में "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार योजना" जिसके अन्तर्गत लोगो को एक वर्ष में सौ दिन का रोजगार देना अनिवार्य है और रोजगार नहीं होने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है।

अध्ययन विषय की आवश्यकता एवं महत्व

इसके निम्नलिखित महत्व है –

गार्थी

1. आर्थिक आत्मनिर्भरता –

पहला ध्येय यह है कि निर्धन ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है सभी अपनी–अपनी छोटी–छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। बल्कि स्वयं की पूंजी से सक्षम हो जाए।

2. समाजिक समरसता –

आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण महिलाओं में एक आत्मविश्वास आ जाता है। उनका संकोच दूर होता है एवं वे अपने समाज में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा पाती हैं जिससे उनको समाज में घुलने–मिलने का मौका मिल जाता है तथा वे एक सामाजिक अंग बन जाती हैं।

3. पारिवारिक –

आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों का प्रभाव, उनके अपने पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है । आत्मनिर्भरता से चाहे व आर्थिक हो या सामाजिक, परिवार में उनका सम्मान होता है तथा परिवार के जीवन स्तर में भी सुधार होता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रत्येक कार्य को करने का उद्देश्य होता है जिससे संरक्षण में वह कार्य अपनी गति एवं उद्देश्य को प्राप्त करता हुआ मंजिल पर पहुंच कर निर्णयों से फलीभूत होती है। इसी प्रकार इस शोध कार्य को करने का भी एक उद्देश्य है –

1. ग्रामीणों में आय वृद्धि की संभावनाओं को जानना
2. ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर की पहचान करना

3. परिवार में उनकी स्थिति का अध्ययन करना
4. ग्रामीणों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को जानना
5. घर और कार्य दोनों में समायोजना का पता लगाना
6. ग्रामीणों में जागरूकता का पता लगाना

अध्ययन – विषय से संबंधित उपकल्पनाएँ

परिकल्पना :–

शोधकर्ता जब शोध करने के लिए तैयार होता है तो उसके सामन दो प्रश्न आ खड़े हो जाते हैं, पहला यह कि विषय क्या हो अर्थात् किस विषय पर शोध करना है तथा दूसरा प्रश्न ये कि किस दशा किस सोच से शोधकार्य आगे बढ़ाया जाए। तब ऐसी स्थिति में शोधकर्ता अंदाज या विवेक पर आधारित एक अग्रिम सोच विकसित करता है और यही अग्रिम सोच की उपकल्पना है।

उपकल्पना का सामान्य अर्थ है पूर्व चिंतन । उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान की प्राथमिक सीढ़ी है। उपकल्पना ही वह विचार है जो सामाजिक अनुसंधान को जन्म देती है। उपकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच होती है।

1. पी.वी. यंग के अनुसार –

"उपकल्पना एक कार्यवाहक केन्द्रीय विचार है जो उपयोग खोज का आधार बनता है।"

2. लुण्डबर्ग के अनुसार –

"अपने मूल रूप में उपकल्पना एक अनुमान अथवा कल्पनात्मक विचार हो सकता है जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनता है।"

अध्ययन की सीमाएँ

इस अध्ययन में बिलासपुर जिले ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम–दाढ़ी का चयन किया गया है ।

इस अध्ययन की निम्नलिखित सीमाएँ है।

1. उत्तरदाताओं की संख्या 30 तक सीमित है–
2. ग्रामीण क्षेत्रों में 30 उत्तरदाताओं ग्रामीण को पूरे गांव का प्रतिनिधि माना गया है।
3. शिक्षा का स्तर इस अध्ययन को प्रभावित करता है।
4. यह एक सीमित क्षेत्र में किया गया अध्ययन है।

परिभाषाएँ –

1. पी.एम. कुक के अनुसार :– अनुसंधान एक निरपेक्ष व्यापक तथा बौद्धिक अन्वेषण है जिसमें विशिष्ट यंत्रो उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि एक समस्या का अधिक समुचित समाधान उपलब्ध हो सके।
2. सी.सी. कोफोर्ड के अनुसार :– अनुसंधान चिंतन की एक क्रमबद्ध तथा विशुद्ध प्रविधि है जिसमें विशिष्ट यंत्रों उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि एक समस्या का अधिक समुचित समाधान उपलब्ध हो सके।
3. पी.बी. यंग के अनुसार – अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है तथा यह उप अनुक्रमों पारस्परिक संबंधों कारणात्मक व्याख्याओं तथा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करती है जो कि प्राप्त तथ्यों को निर्धारित करती हैं।

हम कह सकते हैं कि शोध एक ऐसा व्यवस्थित नियंत्रित अनुभविक तथा सुक्ष्म अन्वेषण है कि शोध एक सामाजिक घटनाओं में व्याप्त अनुमानित संबंधों का अध्ययन परिकल्पनात्मक तर्क वाक्यों द्वारा किया जाता है।

परिणामों का सम्पूर्ण विवेचन

प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण क्षेत्र से 50 उत्तरदाताओं का चयन निदर्शन पद्धति से किया गया तथा अन्य तथ्य संकलन के पश्चात् प्राप्त परिणामों को संपूर्ण विवेचन निम्नलिखित प्रकार से किया गया।

परिणाम :–

1. गांव में 20–30 आयु वर्ग में 26.66 प्रतिशत के लोग काम करते है और 30–40 आयु वर्ग में 43.34 प्रतिशत लोग काम करते हैं। 40–50 आयु वर्ग 26.66 प्रतिशत लोग तथा 50 से अधिक में 3.33 लोग कार्य करते हैं।
2. शैक्षणिक स्तर का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 83.33 लोग शिक्षित है तथा 16.66 अशिक्षित है।
3. कुल 30 उत्तरदाताओं में से 46.66 प्रतिशत कृषि करते हैं। 16.66 लोग मिस्त्री 26.66 लोग कृषि मजदूरी 3.33 प्रतिशत लोग मिस्त्री का कार्य एवं 6.66 प्रतिशत लोग दुकानदारी का व्यवसाय करते हैं ।
4. लगभग 6.70 प्रतिशत उत्तरदाता परित्यक्ता हैं , 74 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित, 12.6 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित तथा 6.70 प्रतिशत उत्तरदाता विदुर विधवा की स्थिति में है।

उत्तरदाता के सुझाव –

1. सरकारी योजनाओं की जानकारी नियमित व सुचारू ढ़ंग से देनी चाहिए ।
2. ग्राम पंचायत के द्वारा लिये जा रहे कार्यों व उनके क्रियाकलापों की नियमित रूप से देखरेख होनी चाहिए।
3. अधिकारों की जानकारी व शिक्षा उच्च स्तर पर देनी चाहिए ।
4. ग्राम सभा की परिस्थितियों की जाँच कर उन पर ध्यान देना चाहिए व सरपंच एवं सचिव पर नजर रखनी चाहिए।
5. पलायन की समस्या को रोकने के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना चाहिए।
6. इस योजना के कार्यदिवस में वृद्धि होना चाहिए ।
7. इन योजना में काम करने वालों की मजबुरी नियमित रूप से साप्तहिक भुगतान होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ

- गुप्ता एवं शर्मा, ग्रामीण समाजशास्त्र
- एम.एल. गुप्ता, डी.डी. शर्मा, प्रारंभिक सामाजिक अनुसंधान
- आर.के. रस्तोगी, सामाजिक अनुसंधान, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी
- जैन एवं फोड़िया, भारत में पंचायती राज
- डॉ.एस.एन. सिंह, पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम

अखिलेश कुमार पाण्डेय, एम.फिल. समाजशास्त्र, शोधार्थी
डॉ. सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

New Frontiers Of Research Vol. 3 Dec. 2016 ISSN No. 2347-2855

कोरबा जिले (छ.ग.) के कोरवा जनजाति में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन

एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सुनील कुमार श्रीवास, शोधार्थी

सारांश :– पहाड़ी कोरवा जनजाति समाज के सामाजिक आर्थिक स्वरूप को विभिन्न कोणों में यथा संभव प्रमाणिक तौर पर बतलाने का एक छोटा से प्रयास किया है जिससे संक्षेप में इस समाज की विभिन्न संगठनात्मक पक्षों की जानकारी मिल जाती है। सत्य है कि पहाड़ी कोरवा जनजाति आदि परम्पराओं का प्रतिक बना हुआ है। विकास के संबंध इनकी उदासीनता इनके आर्थिक स्वरूप को धरातल से जोड़ी हुई है और इससे उबरना ही इनकी प्रगति के लिए बुनियादी प्राथमिकता कही जा सकती है। यह पहाड़ी कोरवा समाज जंगल व पहाड़ों के बीच रहकर जीवन बसर कर है। इस समाज में दो घरों के बीच दूरी बहुत होती है। इनमें एक परिवर्तन की अधमान्यताएँ काफी गहरें में पैठ जमाये है। यहां के घर के अंतरास्था पर पहला है।यहां की महिला की दिनचर्या महुआ या चरौटा के भोजन में चुनना सुखना खरीफ के साथ कृषि मजदूरी एवं खनवाना, निकालना फसल मजदूरी खुल सीज़न में तेन्दूपत्ता चुनना व जलाऊ लकड़ी चुनकर बेचना, खाना बनाना एवं घरेलू कार्य करना आदि तक ही सिमित है। पुरुषों की दिनचर्या में खेती चाहे स्वंय की हो या मजदूरी पर, हल जोतना, मजदूरी करना, खेत की कृषि कार्य करने, जलाऊ लकड़ी बेचना, बाकी दिनों में खेतों में खोद–खोदकर कुछ मारना और खाना, जंगलो में सुअर, खरगोश आदि का शिकार करना, तीज – त्यौहारों के अवसर में व गाठ में रुपया होने पर दारू पानी और मस्त होकर करमा और कमचक नृत्य करते है। इन जनजाति क्षेत्रों में कृषि हेतु आधारभूत सुविधाओं का नितान्त अभाव भी एक विशेष घटक है। जब तक इन कठिनाईयों के निदान हेतु क्रान्तिकारी प्रयास नहीं किया जायेगा। तब तक इनके आर्थिक स्तर में सुधार सभंव नहीं होगा।

प्रस्तावना –

भारत वर्ष समग्र जनसंख्या और समस्त भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि बड़ा देष है इतना ही नहीं वरन् समग्र आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से इस देश में एशिया, अफ्रिका, आस्ट्रेलिया, लेटिन अमेरिका और उत्तर अमेरिका की तुलना में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। जिस प्रकार भारत वर्ष दुनियां में आदिवासी जनसंख्या वाला एक बड़ा देश है उसी प्रकार मध्यप्रदेश में देश के विभिन्न राज्यों की तुलना में जनसंख्या सर्वाधिक रहती है। प्रदेश का आदिवासी परिदृश्य कई अर्थों में अनुठा है। इसकी समद्धता व्यापक और बहुवर्णिय है। मध्यप्रदेश की आदिम जातियां हमेशा कौतुहल और जिज्ञासा का केन्द्र रही है। ये 46 आदिम जातियां प्रदेश के लगभग सभी जिलों में फैली है।

मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। इस प्रदेश में मध्यभारत के सभी आदिवासी समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। प्रदेश की कुल आदिवासी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 53 लाख 99 हजार 34 है जो देश की कुल आदिवासी आबादी का लगभग एक चौथाई भाग है।

जन जाति क्या है –

किसी मानव समूह को एक जन जाति

ISSN No. 2347-2685

जानने के लिए यथार्थ रूप से कसौटियां है, जन जातियां जाति जीवन की नया सिलसिला है। एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है। जिसका एक सामान्य नाम होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते है, सामान्य भाषा बोलते है, और विवाह व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निबंधात्मक नियमों करते है। प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के दो मत रहे हैं। एक यह कि ये आदिवासी छोटा नागपुर में पाये जाने वाले मुंडा आदिवासियों के उपसमुह हैं। कर्नल ई.टी. डाल्टन का मत दूसरा है उन्होंने कोरवा जनजाति को कोलेरिन श्रृंखला की ही एक कड़ी बताया है। इस तरह कोलेरियन श्रृंखला की यह लड़ी (कोरवा नाम से जाने वाला समूह) अपने मूल समूह से दूर रहकर एक लंबे अंतराल में तितर–बितर हो गई।

कोरवा अपने मूल निवास छोटा नागपुर से चलकर एक लंबे समय में कन्हार नदी के दक्षिण में भुतपूर्व कोरवा स्टेट (वर्तमान में कोरबा व रायगढ़ जिला) के खुड़िया क्षेत्र में बस गये इस तरह यह सामूदायिक सैलाब खुड़िया की आंतरिक और घने जंगलों में बसते हुए धीरे–धीरे छोटे–छोटे समूह में सरगुजा राज्य के पर्वतीय अंचलों में समाहित होते हुए बिहार के पलातु में बसते हुए आगे बढ़ गये। अंत में विंध्य की तुंग पहाड़ियों के उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में होते हुए मिर्जापुर के पहाड़ी अंचलों में बस गये। इस जनजाति के फैलने का दायरा लंबा रहा लेकिन वास्तव में इनके जमाव आदि बसाहट का स्थल प्रमुख रूप से खुड़िया के ऊँचे पठार और कर्मस्थली ही रही है।

मध्यप्रदेश में पहाड़ी कोरवा जनजाति ने खुड़िया और सीमावर्ती सरगुजा राज्य की पहाड़ियों और जंगलो को अपना रहवास में वास करने वाली खुड़िया रानी इनकी इष्ट देवी बनी। जंगल काटकर खेती करते हुए शिकार और जंगली कंद मूल पर पूर्णरूप से आश्रित थे जीवन यापन करने लगे। तत्कालिन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में जंगल इनके लिए अर्थहीन था क्योंकि सारी वन संपदा के मालिक थे। अपनी अन्य छोटी–छोटी आवश्यकताओं जैसे तम्बाकू, बिड़ी व नमक आदि की पूर्ति के लिए मैदानी इलाके से आने वाले यात्रियों तथा साहूकारों को लूटते भी थे। 1790 के आसपास कोरवा के शासक ने कोरवाओं को पहाड़ के नीचे के अंचलों में बसाने के लिए काफी प्रयास किये उपर से इन्हे नीचे उतारने का उद्देश्य जंगल को नष्ट होने से बचाना और लूटपाट को कम करना था। धीरे–धीरे ये पहाड़ियों के नीचे के ग्रामीण अंचलों में बसे। वे स्थानीय बोली में डिहारिया अर्थात डिहारिया कोरवा कहलाये। डिहारिया का अर्थ है जो जमीन पर ग्रामों में रहे और खेती उनका प्रमुख धंधा हो, जो कोरवा इतना प्रयास करने पर भी नीचे नहीं उतरें वे पहाड़ी कोरवा समुदाय जो उपसमुहों पहाड़ी या डिहारिया में बट गये।

वर्तमान में कोरवाओ की बसाहट का

 ISSN No. 2347-2685

क्षेत्र प्रदेश के बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले, सरगुजा की सामरी, अंबिकापुर और फरसा तहसील तथा बिलासपुर जिले की कटघोरा तहसील के कुल पहाड़ी क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

पहाड़ी कोरबा थ्योंरा खेती रहे और यह इनकी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गया। थ्योरा खेती के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होते रहे यायावर बन गये। इनके बसने व रहने का तरीका एक ग्राम के रूप में न रहकर बेहद बिखरा और बेतरतीब सा हो गया। एक पहाड़ी कोरबा का घर कहीं दूर घने जंगलों में तो दूसरे का किसी पहाड़ी के ऊपर तो तीसरे का ढलान पर्तों पर तो चौथे का पहाड़ी के नीचे या किसी कुंदरा में बना हुआ रहता है। घरों में आने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है अधिक से अधिक एक स्थान पर दो या तीन घर कुछ दूरी के दायरे में बने होते हैं। इसका कारण यह है कि विवाह के पश्चात् लड़का अपनी पत्नी को लेकर दूसरा घर बनाता है।

कोरवा बोली मुंदारी समूह की भाषाओं से मिलती जुलती है। कोरवा लोग सरगुजिया में भी बोल लेते हैं।

माघ में (दामफोड़) का त्यौहार फसल की खुशहाली में मनाते हैं। इस दिन सभी अनाज मिलाकर रोटी बनाकर खाते हैं। नया हंडियां ली जाती है। फागुन में होली मनातें हैं। नई फसल आने पर नयारपानी त्यौहार मनाते हैं। इस दिन पूजा कर नया अनाज खाते है। पूर्वजों की भी पूजा करते है। दीपावली भी मनाई जाती है।

हाट बजार भी इनके लिए पर्व के समान है। ये हाट जाने से नहीं चुकते है। कोरवा लोग डोम, चीक, घासी नाई धोबी आदि जाति को छोटा मानते हुए उनके हाथ का बना भोजन नहीं करतें। नगेसिया, टेहारी, कलवार अहीर कच्ची, जात समझे जाते है। नगेसिया से विवाह करने पर कोरवा औरतें उनकी लड़की का बना खाना नहीं खाती है, पुरूष खा सकते है।

अध्ययन का उद्देश्य –

1. पहाड़ी कोरवा जनजाति का सामाजिक अध्ययन।

2. पहाडी कोरवा जनजाति का अर्थिक अध्ययन।

कार्यक्षेत्र :–

कोरबा जिले के ग्राम मदनपुर (सरडीह), सिमकेदा (तितरडाद), अमलडिहा (कयमहुआ), लवेध (डुमरडीह), क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा जनजाति के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर का अध्ययन करना है।

अध्ययन का महत्व :–

जनजाति समाज को उपर उठाने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाएं में इनके लिए विशेष राहत व विकासीय कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है। किन्तु इनके बावजूद भी ये समुदाय पुरानी पिछड़ी हुई स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। चूंकि समाज में विकास में मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क की चेतना ही कार्य करती

है। अतः इस चेतना का मूल्यांकन समय–समय पर करके समाज की प्रगति का अध्ययन करना।

ये समाज सभी सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेता है और इनका आधार एक सुदृढ़ न्यायिक व सामाजिक संगठन है किन्तु इन सबके बावजूद भी इस समुदाय के विकास का प्रवाह एक क्षेत्र तक ही सिमीत है। इसके विकास की दर बहुत धीमी है। इस प्रकार न केवल जनजातियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है अपितु सरकारी योजनाओं के निर्धारण के क्षेत्र में भी प्रभावी व कारगर कदम साबित हो सकता है।

परिकल्पना :–

1. पहाड़ी कोरबा जनजाति का षिक्षा रिथति में सुधार होना चाहिए।
2. इस जनजाति के लोग आर्थिक जीतिकोपार्जन हेतु सिमीत विकल्पों में विकास होने की आवश्यकता है।
3. पहाड़ी कोरबा जनजाति में नातेदारी व्यवस्था महत्व होना चाहिए।

कोरबा जिले के चयनित ग्रामों का विवरण सिमकेदा (तितरदाढ़ पारा), अमलडीहा (करूमौहा पारा), लबेद (हुमरडीह, बलीपुर पारा), मदनपुर व केराकछार (सहडीह पारा) ये चार चयनित ग्राम हैं। जिनमें हमनें पहाड़ी कोरबा जनजाति के स्वास्थ्य का अध्ययन किया। ये गांव जंगलों में बसे हुए है। तथा कोरबा जिले के अंतर्गत आते हैं। यह गांव उरगा से ष्यांग के मार्ग में पड़ता है।

तीतरदांक –

यह पारा सिमकेदा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। और यह चिर्रा से 6 किमी की दूरी पर स्थित है। जो अत्यधिक घने जंगलों के बीच में हुआ है। इस गांव की जनसंख्या कुल 600 है और यहां पहाड़ी कोरवा जनजाति की जनसंख्या 40 से 45 है साथा 10 परिवार हैं। यह पहाड़ी कोरबा के अलावा गोंड़ एवं पटेल जनजाति निवास करते हैं। यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी है। यहां पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग एवं मजदूरी तथा अपना पंरपरागत व्यवसाय चटाई बनाने का कार्य करते हैं। यहां पर पानी, बिजली, सामुदायिक भवन, स्कूल व स्वास्थ्य केन्द्र व सड़क एवं आवागमन के साधन नहीं होने के कारण इन्हें सदैव अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। यह पठारी भू–भाग होने के कारण कृषि योग्य भूमि का अभाव है। साथ ही उत्पादन क्षमता अत्यधिक कम है। जरूरत पड़ने पर किसी वस्तु के लिए आते हैं।

करू महुआ –

यह पारा अमलडीहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और करू महुआ यहां से 3 किमी. अंदर में बसा हुआ है। यहां से चिर्रा 20 किमी. दूरी पर है। यहां की कुल जनसंख्या 650 है। जिसमें पहाड़ी कोरवा जनजाति की जनसंख्या 50 है तथा 10 परिवार है। यहां के कोरवा परिवार के लोग तितर–बीतर बसे हुए हैं। कुछ परिवारों का घर अन्य घरों से 2 किमी. दूरी पर बसा है। यहां परबैगा, राठीयां

ISSN No. 2347-2685

एवं पटेल जाति के लोग अधिक रहेत हैं। पहाड़ी कोरबा जनजाति का मुख्य व्यवसाय गांजा की खेती करना, मजदूरी व बनी – भूती है। यहां भी पानी, बिजली, स्कूल एवं स्वास्थ्य केन्द्र एवं आवागमन का साधन एवं सड़क का अभाव है। इन्हें किसी प्रकार की वस्तु के लिए श्यांग आना पड़ता है जो कि यहां से 10 किमी. की दूरी पर है। यहां के लोगों में स्वास्थ्य की समस्या अधिक पाई गई है क्योंकि इनके आस–पास स्वास्थ्य केन्द्र का अभाव है। जिसमें स्वास्थ्य खराब होने पर इलाज स्वंय करते है। यहां के लोग प्राय सुबह से जंगल जा हैं और शाम को लौटते हैं। यहां पर पहाड़ी कोरबा कुछ संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं।

प्राक्कथन–

मध्यप्रदेश में बहुत सी जनजातियां हैं इनमें से कुछ के विषय में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। किन्तु कुछ ऐसी भी जनजातियां है जिनका केवल हमने नाम ही सुना है। पहाड़ी कोरबा मध्यप्रदेश भुभाग में बसने वाली आदिम जनजाती है जिसका अध्ययन मैंने कोरबा जिलों के ग्रामों में किया है। इस अध्ययन के लिए क्षेत्रकार्य, सहभागी निरिक्षण, साक्षात्कार व्यक्तिगत अध्ययन, अनुसूचि का उपयोग किया है।

इस लघु शोध में मैने एक अल्प परिचित जनजाति के बारे सामाजिक एवं आर्थिक जानकारी दी है इसमें मैने कोई समाज शास्त्रीय सिद्धांत प्रस्थापित नहीं करना चाहा है मेरा उद्देष्य केवल इस जाति का सामाजिक एवं आर्थिक परिचय देना ही है इसलिए मैने इनके निवास क्षेत्र का परिचय, जनसंख्या, भौतिक संस्कृति, आर्थिक क्रियाकलाप व मान्यताओं की झांकी प्रस्तुत की है। साथ ही अंत में इन लोगों में क्या परिवर्तन आ रहे है, इनकी क्या समस्याएं है, तथा इन समस्याओं का समाधान कैसे हो इसके बारे में जानकारी दी गई है।

आर्थिक स्तर का अध्ययन–

भारतीय जनजाति अर्थव्यवस्था सर्वत्र मिश्रित प्रकार की पाई गई है। ये अपने जीवकोपार्जन के लिए जिस अर्थ–व्यवस्था के द्वारा प्रयत्नशील रहते हैं, वह सीमित प्राकृतिक संसाधनों और प्राचीन औद्योगिकी ज्ञान के अर्न्तगत ही जुटाई जाती है। उनके अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कार्यो में विशिष्टीकरण नहीं पाया जाता है। अपितु एक ही जनजाति कई प्रकार के कार्यों में संलग्र देखी जाती है। इस तरह इन जनजातियों के आर्थिक जीवन को न तो प्रकटतः व्यवस्थित कहा जा सकता है और नहीं खाद्य संग्रहण जैसे वनोपज से जुड़े कार्यो तक सीमित रखा जा सकता है। यह एक सार्वभौमिक सत्यता है कि इनके जीवकोपार्जन से जुड़े आर्थिक स्त्रोत का प्रमुख आधार वनों या जंगलों पर ही काफी हद तक निर्भर है। जो इन आर्थिक संरचना के अर्थोपाजन से जुड़े कार्य इनके आर्थिक स्थिति संनरचना के अंर्तगत शिकार एवं खाद्य संग्रहण पशुपालन कृषि मजदूरी शिल्पकारी एवं उद्योग में कार्यरत श्रमिक वर्ग आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित किये जा सकते हैं।

आज विकास के इस दौर में भी अधिकांश

जनजातियाँ वनोपज संग्रण के कार्य में लगी हुई है। और कहीं परंपरागत अथवा नवीन विशिष्टीकरण के प्रोत्साहन स्वरूप कुछ जनजातियाँ शिल्पकारियों से जुड़ी हुई है। पर कृषि कार्य ही ऐसा है जिसे प्रायः सभी जनजाति समाज में किसी न किसी रूप से उनके आर्थिक जीवन का आधारजन व्यवसाय है। अत्यन्त ही पिछड़ी जाति में आज भी कहीं–कहीं झूम खेती की प्रथा प्रचलन में है। पर इनकी संख्या नगण्य ही है। क्योंकि सरकारी प्रतिबंधों के कठोरता से लागू किये जाने के कारण अब यह प्रथा स्वतः ही समाप्त होता जा रही है।

निष्कर्ष :–

यह पहाड़ी कोरवा समाज जंगल व पहाड़ों के बीच रहकर जीवन बसर कर रहा है। यह पहाड़ी कोरवा समाज जंगल व पहाडों के बीच रहकर जीवन बसर कर है। इस समाज में दो घरों के बीच दुरी बहुत होती है। इनमें घड परिर्वतन की अवमान्यताएँ काफी गहरें में पैठ जमाये है। यहां के घर के अस्वास्थ्य पर पड़ता है।यहाँ की महिला की दिनचर्या महुआ या चरौदा के भोजन में चुनना सुखाना खरीफ के समय कृषि मज़दूरी एवं खनवाना, निकालना फसल मज़दूरी खुल सीज़न में तेन्दूपत्ता चुनना व जलाऊ लकड़ी चुनकर बेचना, खाना बनाना एवं घरेलू कार्य करना आदि तक ही सिमित है। पुरूषों की दिनचर्या में खेती चाहे स्वंय की हो या मज़दूरी पर, हल जोतना, मजदूरी करना, स्वंय का कृषि कार्य करने, जलाऊ लकड़ी बेचना, बाकी दिनों में खेतों में खोद–खोदकर चुहा मारना और खाना, जंगलो में सुअर, खरगोश आदि का शिकार करना, तीज – त्यौहारों के अवसर में या गांठ में रूपया होने पर दारू पानी और मस्त होकर करमा और ढमचक नृत्य करते है। इन जनजाति क्षेत्रों में कृषि हेतु आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव भी एक विशेष घटक है। जब तक इन कठिनाईयों के निदान हेतु क्रान्तिकारी प्रयास नहीं किया जायेगा। तब तक इनके आर्थिक स्तर में सुधार संभव नहीं होगा।

सुनील कुमार श्रीवास, एम.फिल. समाजशास्त्र, शोधार्थी
डॉ. सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

ISSN No. 2347-2685

मानसून का कृषि पर प्रभाव : एक अध्ययन

डॉ. संजय सिंह – श्रीमती अंजली चतुर्वेदी

भारतीय कृषि पर मानसून का संपूर्ण प्रभाव रहता है। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं फिर भी हम भगवान पर आश्रित हैं, यह एक बड़ी विडम्बना है। पिछले 10 वर्ष में अच्छी वर्षा हुई है किन्तु हमारी कृषि 8.71 प्रतिशत पिछड़ी है, यह सोचने का विषय है। मानसून की अब तक रफ्तार से सरकार खुश है, उसे भरोसा है कि बारिश से मंहगाई में कमी आएगी। साथ ही खाद्य उत्पादन भी बढ़ेगा। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। कृषि मंत्री के अनुसार 29 राज्यों के सभी 638 जिलों की दलहन उत्पादन क्षेत्र में शामिल किया गया है। पूर्व में 16 राज्यों के 843 जिलों को शामिल किया गया था। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार 641 जिलों में से 182 में सामान्य से कम बारिश हुई है तथा 14 जिले में अति अल्प वर्षा हुई अर्थात् 70 प्रतिशत क्षेत्रों में बारिश की अच्छी तथा 30 प्रतिशत क्षेत्रों में बारिश कम हुई, जो मानसून की वास्तविकता को स्पश्ट करती है। 28 प्रतिशत क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। वहीं 58 प्रतिशत क्षेत्रों में कहीं कम वर्षा तथा कहीं अधिक वर्षा हुई है। वर्षा की असमानता के कारण कृषि क्षेत्र में हानि हो रही है।

अध्ययन का उद्देश्य –

मौजूदा मानसून का कृषि उत्पादन में पड़ रहे प्रभाव का अध्ययन करना है।

अध्ययन की परिकल्पना –

प्रस्तुत शोध पत्र में निम्नलिखित परिकल्पना निर्धारित की गई है –

1. इस वर्ष मानसून 100 प्रतिशत रहेगा।
2. कृषि की पैदावार सर्वोत्तम होगी।
3. कृषि रकबे में वृद्धि होगी।
4. अरहर की फसलों में वृद्धि होगी।

अध्ययन की सीमाएं –

1. द्वितीय समंकों को लिया गया है।
2. समंक अनिश्चित है, समंकों में अत्याधिक परिवर्तन है।
3. समंक केवल अगस्त माह का लिया गया है एवं वर्ष से तुलना किया गया है।

सांख्यिकी विधियों का प्रयोग –

प्रस्तुत अध्ययन में टाईम सिरीज, अंतगण, बाह्यगण, काई, जेड और टी परीक्षण किया गया है।

मानसून की भारत के विभिन्न राज्यों में स्थिति –

- **मध्य प्रदेश** – लगभग 869 मि.मी. वर्षा हुई। वर्षा होनी थी 637.5 मि.मी. अर्थात् 28 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई, लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि सोयाबीन की फसल गत वर्ष में प्रभावित हुई भी और इस वर्ष भी प्रभावित हो रही है। दो वर्षों में अल्प वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल खराब हुई भी और अतिवृश्टि के कारण मध्य प्रदेश में 16 बड़े बांध में से 15 बड़े बांधों में 90 प्रतिशत से अधिक पानी भर गया। 10 बड़ी नदियां हैं, सभी में 90 प्रतिशत से अधिक पानी आ जाने के कारण 18000 हेक्टेयर में रोपित फसलें

को नुकसान हुआ।

- छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ में सभी बड़े बांध लगभग 95 प्रतिशत भर चुके हैं। इस प्रदेश में 779.4 मि.मी. वर्षा हुई है जबकि होनी थी 721.4 मि.मी. अर्थात् 8. 1 मि.मी. अधिक वर्षा हुई। यह भारत का मैदानी क्षेत्र है जहां अधिकांश क्षेत्रों में धान की खेती होती है। यहां पर पानी से खेती को नुकसान कम होता है तथा फायदा अधिक। राज्य में 27 बड़े बांध हैं जिनमें लगभग 90 से 95 प्रतिशत बांध पानी से भर चुके हैं, अतः कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति अच्छी है।
- गुजरात – 366.3 मि.मी. बारिश हुई लेकिन बारिश होनी थी 463.4 मि.मी. अर्थात् लगभग 21 प्रतिशत कम वर्षा हुई। लगभग 7072410 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। पिछले वर्ष की तुलना में 462 लाख हेक्टयर अधिक है जो गत वर्श 6609950 हेक्टेयर बुवाई हुई थी। दलहन के रकबे में 30.93 प्रतिशत वृद्धि हुई। कृषि विषेशज्ञ के अनुसार जहां–जहां व्यवस्था नहीं है वहां–वहां किसानों को कम पानी के कारण 50 प्रतिशत हानि उठानी पड़ सकती है।
- पंजाब – पंजाब में 261.6 मि.मी. वर्षा हुई किन्तु 336.2 मि.मी वर्षा होनी थी। राज्य के 20 जिलों में से 7 जिलों में सामान्य से 2 प्रतिशत अधिक और 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। देष के सबसे बड़े बांध भाखड़ा में 1629. 59 फिट पानी भर चुका है जबकि 1667. 71 फिट तक पानी भरा जा सकता है।
- हरियाणा – इस राज्य में 255.2 मि.मी. बारिश हुई जबकि 304.4 मि.मी. होनी चाहिए। राज्य के 10 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, वहीं 8 जिलों में सामान्य सक कम बारिश हुई अर्थात् कहा जा सकता है कि जहां अधिक बारिश हुई है, वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है।
- महाराष्ट्र – पांच वर्ष में सबसे बेहतर मानसून से अब तक 20 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। कृषि वैज्ञानिक डॉ. एल.बी. पवार के अनुसार इस वर्ष मानसून सबसे बेहतर है। सूखाग्रस्त व गढचाड़ा और पिछले में भी वर्षा की स्थिति अच्छी है। राज्य में लगभग 84 प्रतिशत हिस्से में बुवाई हुई है। उम्मीद है कि दलहन का उत्पादन 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 18 जिलों में सामान्य व 21 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। अधिकांश बांधों में 88 प्रतिशत पानी भर चुका है, गत वर्ष में 47 प्रतिशत ही पानी भरा था।
- बिहार – कुल बारिश 568.8 मि.मी. हुई जबकि 665.7 मि.मी. होनी चाहिए अर्थात् 15 प्रतिशत कम बारिश हुई। 5 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई तथा 18 जिलों में कम वर्षा रिकार्ड की गई। अरहर के उत्पादन में अपार वृद्धि होने की संभावना है। राज्यों में 15 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर उत्पादन होने की संभावना है। आशा की जाती है कि इस वर्ष अरहर की रिकार्ड पैदावार गत वर्ष की

तुलना में 63 लाख टन उत्पादन हुआ। अतः इस वर्ष 10 लाख टन उत्पादन होने की संभावना है।

- झारखण्ड – लगभग 9.1 मि.मी. पानी कम गिरा है। 643.1 मि.मी. की बारिश हुई जबकि बारिश होनी थी 710.3 मि. मी.। 11 जिले में 9.1 मि.मी. पानी गिरा था और 12 जिलों में आवश्यकता से अधिक पानी गिरा है। सितंबर माह तक 43.1 मि.मी. पानी बांधों में लबालब भर चुके हैं, शेष भरने को हैं। भूजल स्तर सर्वोत्तम होने की संभावना है।

भारत वर्ष में इस वर्ष अच्छे मानसून होने के कारण जी.डी.पी. बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है, किन्तु कृषि विशेषज्ञ इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि पंजाब में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि वहां 98 प्रतिशत भूमि सिंचित है।

कृषि वैज्ञानिक हिमांशु ठक्कर के अनुसार – भूजल ही हमारा आधार है। वर्षा का पानी 1 वर्ष में समाप्त हो जाती है एवं भूजल से ही खेती के कार्य सम्पादित होते हैं। भारत में विडम्बना यह है कि दाल के लिये कम कर्ज एवं गन्ने के लिये अधिक कर्ज मिलता है। दाल में कम पानी लगता है और भारत में दाल की मांग बढ़ती ही जा रही है, किन्तु सरकार उदासीन है।

देश के प्रमुख बांधों में पानी की स्थिति

क्रमांक	प्रमुख भाग	जलाशय की संख्या	जलाशय की क्षमता	पानी की उपलब्धता प्रतिशत
1	उत्तर भाग	6	–	10.46
2	दक्षिण भाग	31	39.00	20.36
3	पश्चिमी भाग	27	66.00	17.92
4	पूर्वी भाग	15	–	10.46
5	मध्य भाग	12	27.67	50.00

कृषि विशेषज्ञ देवेन्द्र शर्मा के अनुसार हम दालें आयात कर रहे हैं। दाल की कीमत ऊंचे दरों पर विक्रय किया जा रहा है। दालों के बुवाई के लिये बैंक ऋण नहीं देती, किसानों को निश्चित आय देने के लिये आयोग का गठन होना चाहिये। अमेरिका और यूरोपियन सरकारें किसानों को भारी मदद करती है। अगले 10 वर्षों में अमेरिका सब्सिडी व अन्य मदद के तौर पर 64000 अरब रूपये खर्च करेगा, जबकि हमारे देश में 17 राज्यों में किसानों की औसत आय सालाना 20,000 रूपये है। इसमें वह अनाज भी शामिल है जो वह अपने परिवारों के लिये रख लेता है। अन्य शब्दों में इन राज्यों में किसान की मासिक आय सिर्फ 1666 रूपये है।

राष्ट्रीय स्तर पर एन.एस.एस.ओ. ने किसानों की मासिक आय प्रति परिवार 3000/– रूपये आंकी है। अगर सरकार किसानों की आय तय नहीं करती है तो किसानों की खुदकुशी नहीं रूकेगी, चाहे मानसून कितना भी अच्छा हो। पंजाब में सिंचित भूमि 98 प्रतिशत है अर्थात् मानसून पर आधारित कृषि नहीं है, फिर भी किसान आत्महत्या करते हैं। 1970 में गेहूं 600 रूपये क्विंटल था, आज वह बढ़कर 1450 क्विंटल तक पहुंच गया है। वहीं 46 वर्षों में सरकारी कर्मचारी का वेतन 300 गुना और कार्पोरेट में वेतन 1000 गुना तक बढ़ा है लेकिन किसानों को क्या मिला। किसानों की मौजूदा हालत आर्थिक सुधारों का ही परिणाम है। अच्छे

मानसून से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वर्ष 121 लाख हेक्टेयर दलहन की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। इसे निम्न तालिका में स्पष्ट किया जा सकता है –

फसल	अवधि		वृद्धि / कमी प्रतिशत
	5 अगस्त 2015	5 अगस्त 2016	
धान	270.10	291.95	+2.12
मोटा धान	158.66	163.77	+3.22
सिलहन	157.65	167.58	+6.30
गन्ना	46.11	47.87	+1.65
कपास	105.05	46.48	–8.7

परिकल्पना का परीक्षण –

प्रथम परिकल्पना पूर्णरूप से सत्य साबित नहीं होती। दूसरी परिकल्पना सत्य साबित होती है जैसे की मोटे अनाज, राहर दाल आदि की पैदावार में वृद्धि हो रही है। तीसरी परिकल्पना भी सत्य साबित होती है। कृषि रकबा भी बढ़ रहा है। चौथी परिकल्पना अरहर के फसलों के रकबे में वृद्धि हुई है और बुवाई भी गत वर्ष की तुलना में अधिक हुई है (सांख्यिकीय गणनाओं के अनुसार)।

निष्कर्ष –

29 राज्यों के सभी 638 जिलों को दलहन उत्पादन क्षेत्र में शामिल किया गया है। पूर्व में 16 राज्य के 482 जिले ही इसमें शामिल थे, पर कृषि विशेषज्ञों की राय अलग है। उनका औसत के हिसाब से 10 साल का सबसे अच्छा मानसून माना गया है, पर राय अलग है। 641 जिलों में से 182 में सामान्य से कम बारिश हुई है, 14 जिले अति अल्व वर्षा वाले है अर्थात् देष का 30 प्रतिषत हिस्सा पानी से की कमी से प्रभावित रहा है। 28 प्रतिशत क्षेत्रों में सामान्य से अधिक पानी गिर चुका है दोनों को जोड़ दिया जाये तो 58 जिलों में कम/अधिक पानी गिरा है और अधिक पानी से खेती को नुकसान होने वाला है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. Water resome Morage moet water lukere.
2. Introductory climate cleanea telly sloan.
3. www.skynet weatletter om.
4. www.livemint.com
5. www.imdpune.govt.in
6. www.data.gov.in
7. www.Imdgoa.gav.in
8. www.Data world bank.org
9. www.indirat.com.

डॉ. संजय सिंह, सहायक प्राध्यापक, व्यवसाय प्रबंध विभाग
सी.एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
श्रीमती अंजली चतुर्वेदी, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय
सी.एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

ISSN No. 2347-2685

RAINFALL VARIABILITY , FOOD SECURITY AND HUMAN MOBILITY IN THE JANJGIR – CHAMPA DISTRICT OF CHHATTISGARH STATE, INDIA

Gurudas Paul, Research Scholar

1.Introduction:

Changing weather patterns such as less predictable seasons, increasing events of erratic rainfall or prolonged droughts are the most important factors threatening the sustainability of agriculture and food security . Dwindling agricultural productivity interacts with a range of escalating stresses on rural livelihoods, that is, land pressure, soil erosion, deforestation and depleted water resources that would otherwise exist regardless of the climate change (Iglesias et al., 2007). When livelihoods are subjected to continuous stress, farmers and farm labours might migrate either seasonally, temporarily or permanently and consider it as the most immediate coping strategy (Afifi,2011; Afifi & Warner, 2008). This article investigates whether this applies to four villages in the Janjgir-Champa district of Chhattisgarh state, India. It essentially addresses the three pillars of sustainability: economic (agriculture and livelihood); environment (rainfall and climate); and social (poverty and migration); and uses inductive and deductive approaches to help narrow down the focus from theory to practice and from global to local. An overarching attempt is made to study the inter-linkages between these three pillars from the climate change adaptation perspective. The sample size of the household survey is 180, broken down to four villages. Moreover, the research is supported by meteorological data and information about the rainfall patterns and changes in the research site. Limitations encountered by this study were broadly categorized as methodological shortcomings and physical difficulties. Lack of sufficient baseline data, lack of sufficient time ,expert interviews were some of the limitations faced. Due to the non-availability of detailed household level information, simple random sampling for the household survey was used. To minimize the impact of these limitations, the research team was sufficiently oriented to use proxy indicators to obtain the correct information. Triangulation was also carried out to improve the reliability and validity of this research.

2. SELECTION OF THE STUDY AREA:

Chhattisgarh, being a newly state after 1st November ,2001, importance of Janjgir –Champa district has eight Tahasils and nine development blocks.It is situated in the middle portion of Chhattisgar and the earlier recoreds reveals that population character are more variable from the past century to recent. As the entire region is unique in the state and no such type of work has been done on this district ,this new constructed district is chosen for analysis.

3.PROFILE OF STUDY AREA

Chhattisgarh lies between 17°472 and 24°062 N latitude and 80°152 and 84°242 E longitude. The state measures 640 km from north to south and 336 km from east to west with a total area of 135,194 km2. Janjgir-Champa district, where the research was carried out, is a relatively new district bifurcated from the undivided Bilaspur district. According to the 2011 Population Census Report (Government of India, 2011), Janjgir-Champa has 15 small towns and 892 villages. The district has a total population of 1,619707 people with 815717 males and 803990 females. The district registered a population growth of 22.94% in the last decade.

4. SOCIO-DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE SURVEY HOUSEHOLDS IN RESEARCH SITE:

Although the four villages of the study are treated as one unit, some differences among the villages were observed and are worth mentioning in the article. Table 1 shows the main characteristics of the households of the survey conducted in the four research villages. The majority of the population belongs to the marginalized groups in terms of castes and tribes. Jullan Pakaria has the highest percentage of Most Backward Classes (MBCs). Land ownership is used as a proxy for wealth/poverty. The village Silli has the highest percentage of landless households and at the same time the highest percentage of households with migrants. This indicates that there could be a correlation between being landless and the willingness to migrate due to a lack of commitment back home. Banahil has the highest percentage of small landowners (50%) and Akaltari the highest percentage of large and very large landowners (48%).

5.METHODOLOGY:

Janjgir- Champa District –my study area,provides the opportunity to analysis the "population Characteristics in jangir-Champa District".To represent the spatial distribution,growth ,rural and urban differentiation of literac level, mortality, fertility, migration and concentration of the district,Some map have been drawn based on above said primary and secondary data Will the help of these data many quantitative and qualitative technique have been applied to analysis the district on mentioned topic.

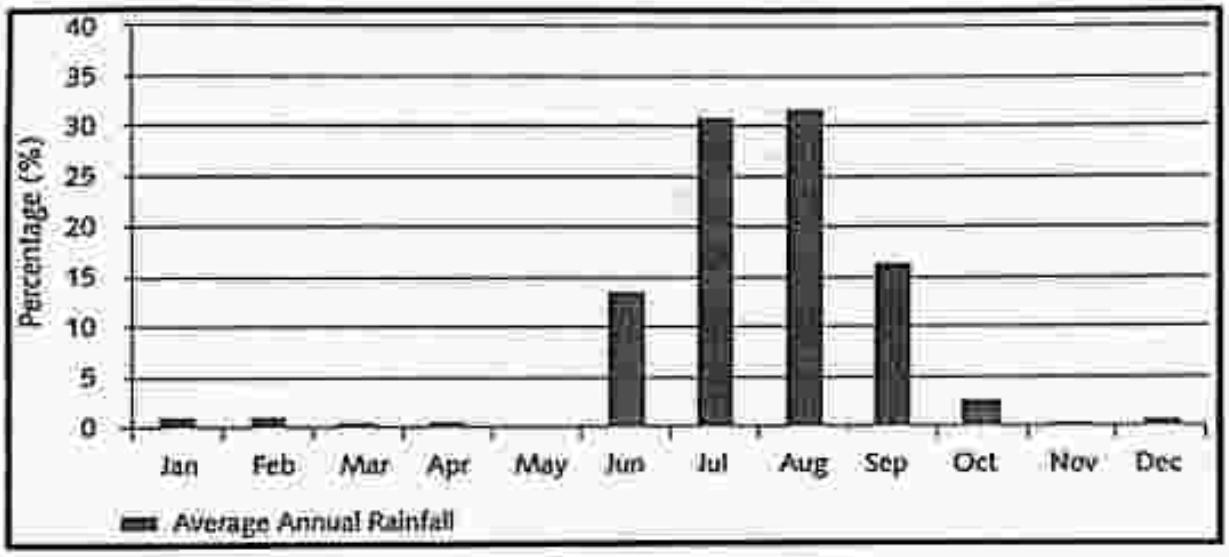

Fig. No. -1

Name of the village	Akaltra	Silli	Jullan Pakaria	Banahil	Total
Number of households interviewed	21	30	87	42	180
Male	20	26	66	35	147
Female	1	4	21	7	33
General	1(4.8%)	3(10%)	1(1.1%)	1(2.4%)	6(3.3%)
MBC	19(90.5%)	22(73.3%)	66(75.8%)	36(85.7%)	143(79.4%)
S.C	0	4(13.3%)	11(12.6%)	2(4.8%)	17(9.4%)
S.T	0	1(3.3%)	9(10.3%)	3(7.1%)	13(7.2%)
Other	1	0	0	0	1(0.56%)
Number (and percentage)of Households With Migrants	5(23.8%)	20(66.7%)	37(42.5%)	13(30.9%)	75(41.7%)
Average Number of Migrants Per Households	3.6	2.9	2.3	2.4	2.8
Number of Landless Households	5(24%)	8(27%)	16(18%)	15(36%)	44(24%)

Table No.-1

ISSN No. 2347-2006

6. Brief Overview of rainfall variability, food security and human mobility in Chhattisgarh:-

6.1. Rainfall variability and agricultural productivity:-

The Indian monsoon period, from 1871 to 2009, shows a well-defined epochal variability with each epoch of approximately three decades. Although it does not show any significant trend, when averaged over this period, a slight negative trend i.e. 0.4 mm/year is seen. Pockets of increasing/decreasing monsoon rainfall trends have been reported in 36 meteorological sub-divisions across India. Particularly, central India depicts a decreasing trend, which is significant over Chhattisgarh and east Madhya Pradesh (MoEF, 2010). Analysis of the rainfall data for the state of Chhattisgarh showed that blocks in the central part of the state, adjoining Janjgir-Champa, Raipur and Bilaspur experience low average annual and average seasonal rainfall (Gupta,2002). Rural areas in the state are most vulnerable to impacts of disasters and climate change. With a significant population dependent on rain-fed agriculture, animal husbandry, fisheries, and forest-based livelihoods, any change in precipitation and temperature patterns could significantly impact lives of the vulnerable communities (Planning Commission, Government of India, 2011).

6.2. Food security and lively hood:-

In Chhattisgarh, rice is the main crop-grown in about 3.7 million hectares, covering 77% of the net sown area. Small and marginal farmers cultivate 38% of the cropped area but constitute 75% of the state's cultivators. Only about 20% of the area is under irrigation, and the rest is under rain-fed conditions. Due to the change in rainfall patterns, a shift in the monsoon in terms of delayed onset farmers in Chhattisgarh has adopted various measures; the farmers earlier used to grow long duration tall varieties of rice which flower in the month of October and mature by the middle of November. As a consequence of decreasing rainfall trends, especially in the month of October, the long duration varieties started failing and farmers have more and more relied on short or medium duration rice varieties for the past 10 years (Sastri, 2009). Although the situation has improved in other states of India, child malnutrition rates in Chhattisgarh continued to be above 50%, even in the past decade (Pathak & Singh, 2011).

6.3. Human mobility and migration due to rainfall variability

In Chhattisgarh, seasonal migration in search of wage labour is very common in many districts. Most of the migrants are farmers with little land holdings who were able to grow only one crop of rice in a year. After one season of agricultural employment, a large number of landless farm labourers choose seasonal migration due to the lack of productive assets or availability of alternative employment options in the villages. People who belong to the MBC, scheduled castes and scheduled tribes migrate in large numbers. Since the state has the lowest share of irrigated land (20%), families cannot sustain themselves on rain-fed agriculture, given the problems facing the latter (Anon, 2008). Despite the creation of nearly 5911 lakh person days of work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranty Act (MGNREGA) during the 11th five year plan period, rural out-migration has increased in the recent years, suggesting the higher risks faced by the vulnerable rural populations (Planning Commission, Government of India, 2011).

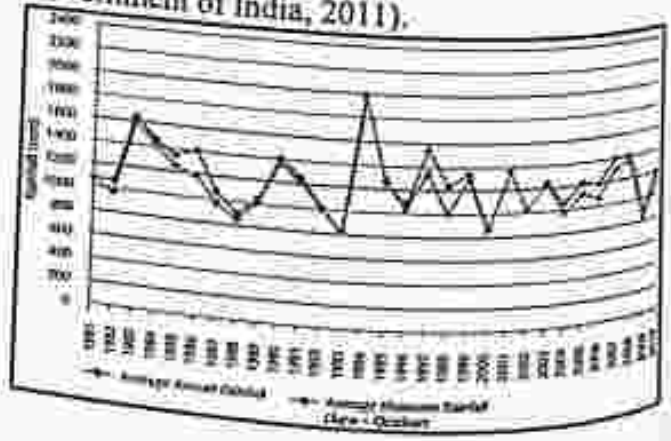

CLIMATE

imate of a country includes the study of nperature, rainfall, atmosphere pruner as well as direction and velocity of winds over a long period time. These elements of climate are longly luenced by latitudinal extent, relief and area tribution of land and water.

) Temperature :-

e distribution of atmosphere in Janjgir-Champa trict is uneven. The summer season starts late in months of March the continuous increase in nperature and decrease in relative humidity make wind hot and dry. There are very high temperature mains in Janjgir-Champa district. May is usually hottest month of with mean monthly temperature .95°c and minimum monthly temperature 20.65°c the month of January in Janjgir-Champa district . e temperature remains more or less constant during rainy seasons and the fall in temperature is emaciated with increase in relative humidity. The lowest temperature recorded for january. Janjgir-Champa district is the hotest district of Chhattisgarh state. So it is called by "Champa Chhattisgarh ka tel ki karahe."

(i) Rainfall :-

The climate of the district is characterised by a hot dry and well distributed rainfall in the south - west monsoon season. Most of the annual rainfall in the district is concentrated in the period extending from may-June to mid october. This period is known as rainy season. About 80%-90% at annual rainfall is receieved during to october. The average rainfall of this district is 1226.12 mm.

The monsoon arrives in the district normally between 6th -14th June to 12th october. This district faces the problem of monsoonal breaks or the monsoonal faliure. The north - westren Cyclones bring some rain in the months of January, February and March.

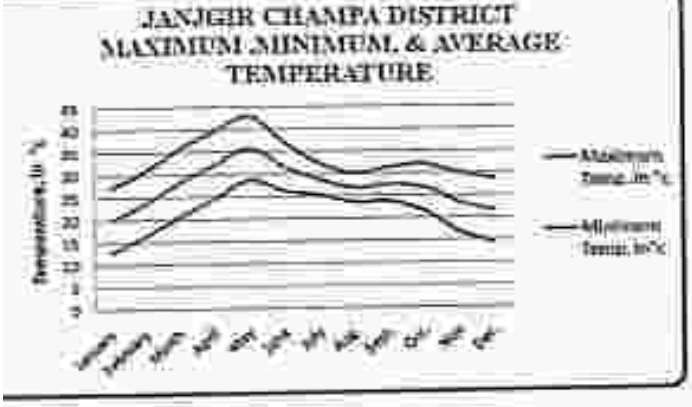

Fig.No.-3

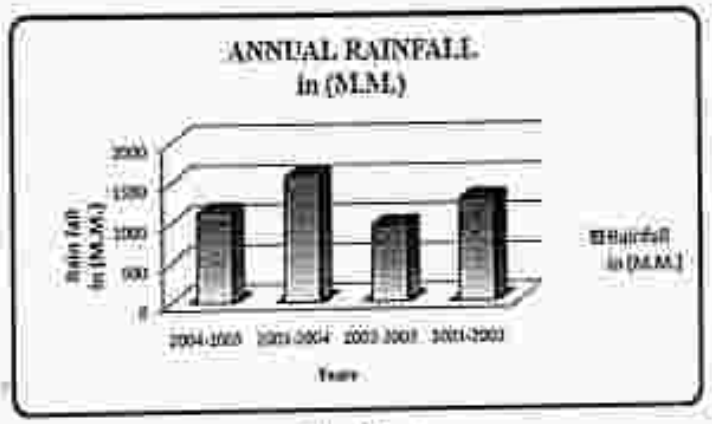

Fig.No.-4

. LIVELIHOOD AND FOOD ECURITY:-

Since agriculture is the major livelihood ctivity of the communities living in the area, most f the discussions during research time revolved round the challenges and risk factors related to griculture. Although the yield has gone up since 000, and reported regionally and nationally as an chievement, it does not capture the complex ynamics involved between farmers, farm labourers, arming practices and more importantly the cost of roductivity. Some of the key challenges of griculture in the study area were delayed monsoons; ingle annual harvest; recurrent crop diseases; input-ntensive unsustainable agriculture; labour shortage during peak harvesting seasons; and poor support price for the producer. Monoculture of rice has been practiced in the region for hundreds of years for cultural and traditional reasons, which include food consumption habits, soil conditions and flood irrigation patterns forcing the farmers to go for only the rice crop in the study area. Local government representatives interviewed in the research area recommend the farmers to diversify their agricultural production ,participants, most of the times, the canal water provided by the government does not allow for a second crop to paddy rice. They informed that local institutions, such as village Panchayat offices (institutions of local self-government elected by people every five years), Anganwadi centres (crèche/

igration destinations. Table 5 shows that 41.6% of e studies households have migration experience. he majority of the migrants seek better livelihoods (87.7%) and an improvement of their financial ituation as compared to educational migrants who ake up only 1.8% of the migrants within the ousehold sample. The household survey also reveals at 61.3% of the migrants are males, although the PRA sessions showed clearly that people rather igrate in families. The seasonal migration is the ost dominating type, which indicates that the weather has an important impact on such a decision. The majority (57.5%) of the migrants are still away and have not yet returned. It is clear from field-based evidence that there have been many circumstances which led to the communities in the villages to choose migration as a major coping strategy.

This has occurred after the majority of the support systems have either failed or proved to be inadequate to ensure access to services and entitlements at their destinations.

Indicators	Total
Total number of households 180 Number of households with migration experience	75 (41.6%)
Total number of migrants	212
Economic migrants	186 (87.7%)
Educational migrants	4 (1.8%)
Other migrants	22 (10.4%)
Gender of migrants Male	130 (61.3%)
Female	82 (38.2%)
Average age of migrants	21.3
Education level of migrants	5.8
Type of migration Seasonal	138 (65.2%)
Temporal	60 (28.3%)
Other	14 (6.6%)
Migration status Current	122 (57.5%)
Returned unspecified	88 (41.5%)
	2 (1%)

Table No. 2

Fig. No. 5

11. SUMMARY AND CONCLUSION:-

Changing rainfall patterns in terms of drought, shorter and shifting rainy seasons as well as erratic rain have a negative impact on the food security and livelihoods of the communities in the research area. It is clear that migration is caused directly (shorter and delayed rain seasons) and indirectly (decreased income due to less crop production caused in turn by less rain) by water scarcity. Although most of the agriculture depends on irrigation by the canal water, the availability of rain water does affect people, the livestock and the crops, especially because the canal water depends on the availability of rain water. Additionally, the communities explicitly mention that the new power plants in the region compete for the canal water and fresh air, and crowd them out by employing people from other regions. The interviewed government representatives blame the monoculture of paddy as a food security threat for the farmers, while the latter in turn refers to the unavailability of sufficient canal water as a reason for them not to grow a second annual crop. It is likely that recognizing drought-induced migration would also be viewed as a failure of government mechanisms; and therefore, government agencies might on one hand rather highlight the monoculture issue and on the other heavily underreport migration. As a result, some of the people are migrating to other places in search of better/alternative livelihoods. Although the communities are also attracted by the pull factors in urban areas, when they move there, they face new types of challenges. In the areas of destination, they are not necessarily surrounded by the best circumstances, which creates other challenges for them and their families. In addition, there are negative implications on child education in cases where people migrate in families and stay away for longer than six months a year. A useful strategy would be considering the locals – who constantly suffer from low food production caused by rainfall problems – in the power plants by providing them with the necessary corresponding skills, in order for them to have improved or even alternative livelihoods in the case of water patchiness or crop failure, without having to move elsewhere. Since the rain resources are limited in the area of study and likely in other similar areas in the same and in other regions, and it is not foreseen that this situation might improve in the near future, then the most relevant recommendation would be making the best out of the available resources. It is crucial to raise awareness of the farmers about the importance of rationalizing the usage of the little water available in ponds and the necessity of not polluting it by using it as a sewer for disposing human and animal waste. Raising awareness among farmers about the possibility of diversifying the agricultural production by introducing new crops could also be useful for the overall benefit of communities, specifically in terms of improved food security and reduced vulnerability. Nevertheless, it is advisable that in return, the decision-makers in the district balance the accessibility to the canal water between the farmers and the power plants, such that both activities work in parallel and the gains of the limited resources in both sectors are maximized.

REFERENCE:-

Afifi, T. (2011). Economic or environmental migration? The push factors in Niger. International Migration, 49(s1), e95–e124.

International Organization for Migration, Special Issue, Oxford, UK.

Mitra, A. (2003). Occupational choices, networks and transfers: An exegesis based on micro data from Delhi slums. New Delhi: Manohar.

Anon. (2008). Distress migration – identity and entitlements: A study on migrant construction workers and the health status of their children in the national capital region 2007–2008. New Delhi: Mobile Crèches Publication.

Government of India. (2011). Census of India: Provisional report 2011. Registrar general and census commissioner. Ministry of Home Affairs. New Delhi, India: Government of India.

Gupta, M. (1993). Rural-urban migration, informal sector and development policies: A theoretical analysis. Journal of Development Economics, 41(1), 137–151.

RESEARCH SCHOLAR - Gurudas Paul
Dr.C.V.Raman University, Kot

A Spatial Analysis of Forest Cover Using GIS and Remote Sensing Techniques

A Case Study in Achanakmar Wildlife Sanctuary

Supervisor: Dr. Manjula Dubey, Kajal Kr Sikdar, M.Phil. Scholar

ABSTRACT:

Hilly area, forested area is commonly inaccessible in terms data collection by actual visiting. The paradigm of data collection is now shifted towards a direction. Recently we can get accurate and timely data of hilly, forested or any inaccessible part of the earth's surface by clicking the mouse. Remote sensing data particularly satellite imageries are now very much useful for getting authentic and periodical data of any part of our planet. In the study Landsat image (LISS III) of 2010 was used as data base for the analysis of forest cover of the study area. By using the technique of unsupervised classification land use map has been prepared and based on the method of maximum likelihood the land use and land cover are classified as moderately dense forest, dense forest, open land, water bodies. Unsupervised classification method carried out prior to field visit in order to determine strata for ground trust. In order to go deep the analysis of the forest cover NDVI has also been prepared from the said image. Minimum NDVI value found is -0.38047and maximum is 0.7965. The calculated mean value of NDVI is 0.20803. Most of the area is under thick vegetation cover i.e. bearing the NDV value more than 0.6750.The result gives a spatial overview and analytic interpretation of the study area that can be used as input to land management and policy decision.

KEYWORDS: Wildlife Sanctuary, NDVI, Image Classification, Standard FCC, Land Use, Core Zone.

INTRODUCTION:

Forests and woodlands are significant land cover covering nearly 40% of the total earth's surface, and are the most biologically diverse ecosystems in the world (WRI, IUCN and UNEP, 1992). Forest constitute a key natural resource and also act as a respiratory organ in the ecosystem. The conservation of forest is of utmost important in the recent era as the above mentioned forested area is diminishing with a rapid rate. In an forest area vegetation cover is the only dominant land cover with a negligble ammount of cultural landuse. To take the care of bio diversity we should take cake the vegetation cover as it is the habitat of most of the species.temporal change of landuse depicts a clear view of the status of forest cover during that particular time period.

Satellite Remote Sensing has become an important tool for monitoring and management of natural resources and the environment. Remotely sensed data are widely used in landuse/landcover classification. Landcover relates to the discernible Earth surface expressions, such as vegetation, soil, water or anthropogenic features, and thus describes the Earth's

ISSN No. 2347-2006

physical state in terms of the natural environment and the man-made structures (Xavier Baulies and Gerard Szejwach, 1998).

STUDY AREA:

The Achanakmar-Amarkantak Biosphere Reserve Located in the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, the Achanakmar-Amarkantak Biosphere Reserve is one of the premium biosphere reserves in India. The reserve covers a huge area of 3835.51 sq. km. and it falls in almost northern part of Bio-geographic zone. About 68.10% out of the total area of this reserve lies in the Bilaspur district in Chhattisgarh. The other major portions of the reserve fall in the Anuppur (16.20 %) and Dindori (15.70 %) districts of Madhya Pradesh. The protected ... Achanakmar Sanctuary is located in Bila... district, within the area of the Biosph... Reserve. The sanctuary has a to... geographical area of 551.15 sq. km. T... Achanakmar- Amarkantak Biosph... Reserve has been divided into core and b... zone. The entire area of the Achanak... Sanctuary is designated as the core zone... the reserve and the rest of the 3284.36... km. are serving as the buffer zone, of t... reserve. Out of the total area of the bu... zone, an area of 1224.98 sq. km. falls in t... state of Madhya Pradesh and the remain... area of 2059.38 sq. km. falls in t... Chhattisgarh state.

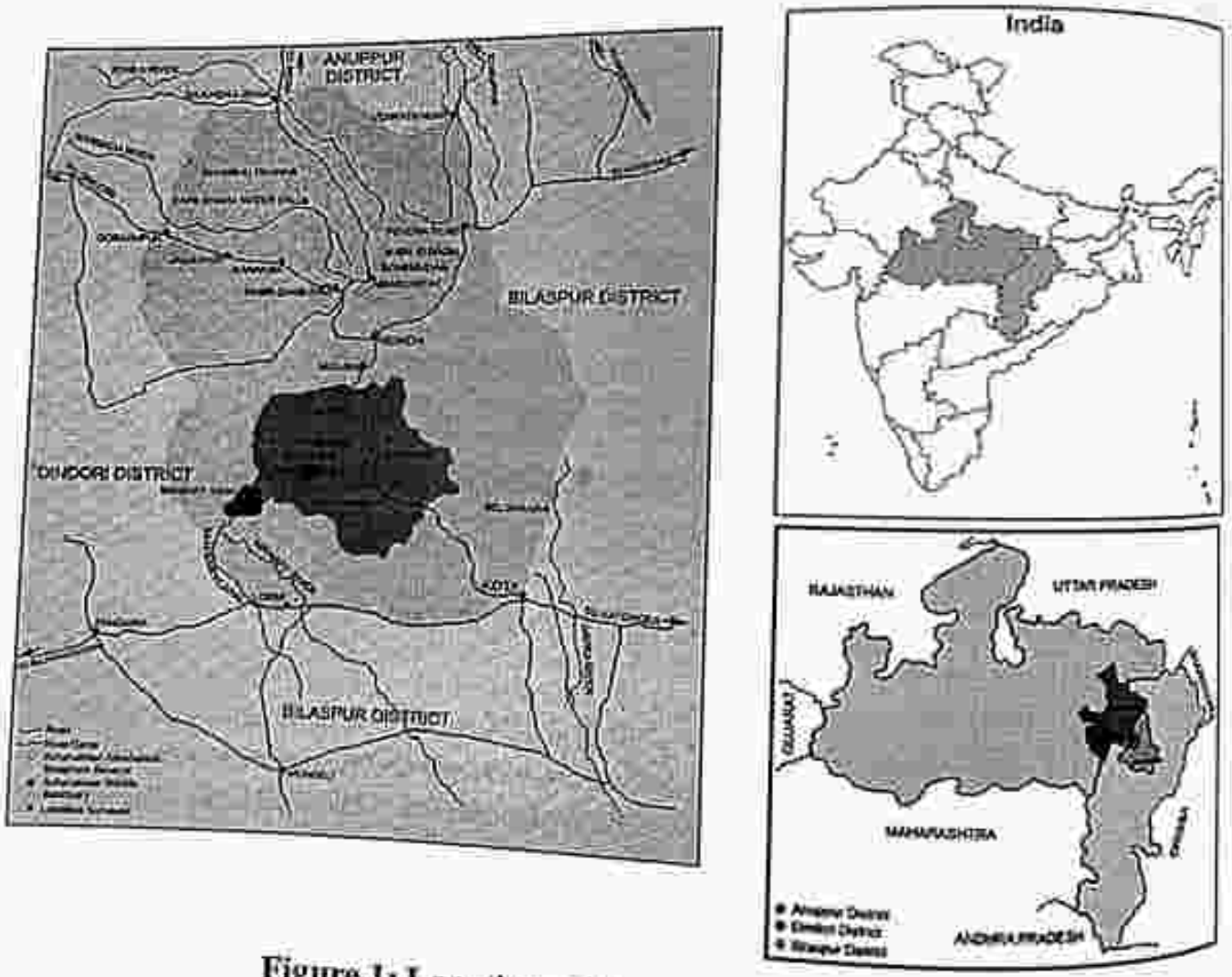

Figure.1: Location of the Study Area

The Achanakmar wildlife sanctuary was stablished in 1975, under provisions of the Vildlife Protection Act of 1972. Achanakmar as been declared a Tiger Reserve under the roject Tiger in 2009. It comprises 557.55 m2 of forest, and is linked by the hilly anha-Achanakmar Corridor to the tiger eserve in Kanha, Madhya Pradesh. The gion is mainly hilly. The altitude of the hhattisgarh Achanakmar Wildlife anctuary ranges from 200 meters to 1000 eters above sea level.

OBJECTIVES:

The study tries give a spatial analysis of the forest as well identifies the coexistence of forest and human habitation in the core of Achanakmar Biosphere Reserve (Achanakmar Wildlife Sanctuary).

DATABASE AND METHODOLOGY:

For the study landsat image (LISS III) were acquired for the year of 2010, as recent images is not easily available. The zonation map of the biosphere reserve was obtained from forest department.

The following flowchart is showing the methodological approach of the entire study.

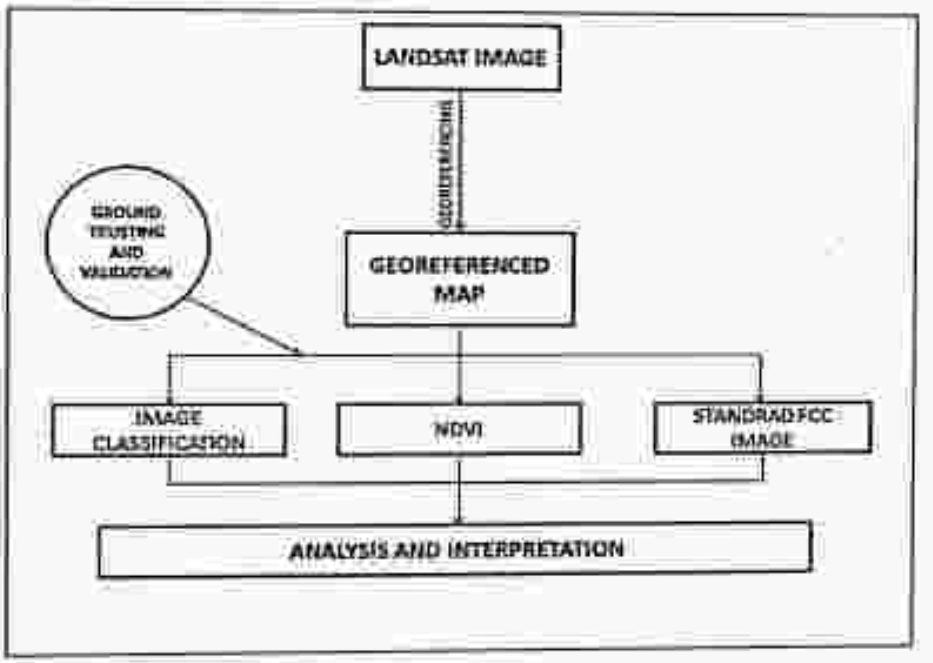

Figure.2: Graphical Representation of Methodology of the Study

A brief description of the particular method used in the study has been given below for a better understanding.

Normalized Diffrence Vegetation Index (NDVI):

Normalized difference vegetation index (NDVI) is a ratio used to determine the density of vegetation in an area based on visible and near-infra-red (NIR) sunlight reflected by plants (Hassan Ahmadi, Asima Nusrath 2010). The NDVI algorithm subtracts the red reflectance values from the near-infrared and divides it by the sum of near-infrared and red bands. NDVI= (NIR-RED) / (NIR+RED). Theoretically, NDVI values are represented as a ratio ranging in value from -1 to 1 but in practice extreme

negative values represent water, values around zero represent bare soil and values over 6 represent dense green vegetation

High positive values of NDVI correspond to dense vegetation cover that is actively growing, where negative values are usually associated with bare soil, snow, clouds or non-vegetated surfaces.

Unsupervised Classification: Unsupervised classification is a method which examines a large number of unknown pixels and divides into a number of classed based on natural groupings present in the image values. unlike supervised classification, unsupervised classification does not require analyst-specified training data. The basic premise is that values within a given cover type should be close together in the measurement space (i.e. have similar gray levels), whereas data in different classes should be comparatively well separated (i.e. have very different gray levels)

False Color Composite (FCC): With the objective of enhancing the vegetation in the image the FCC (band 4=red, band 3=green and band 2=blue) technique was selected. The result looks like similar to prints of color infrared photography (CIR). The most striking characteristic of false color composite is that vegetation appears in a red-purple color. In the visible part of the spectrum, plants reflect mostly green light, but their infrared reflection is even higher. Therefore, vegetation in a false color composite is shown as a combination of some blue but even redder, resulting in a reddish tint of purple

RESULT AND ANALYSIS:

STRUCTURE AND DESIGN OF ACHANAKMAR BIOSPHERE RESERVE:

A. The core zone consisting of 55155.0 ha. is a protected forest under Lamni range, Achanakmar range and Game range. It is most undisturbed with conserved habitat in terms of vegetation and wildlife. Nearly 1460 species of flora belonging to 759 plant genera and 374 species of fauna belonging to 256 genera are known and many species are still to be taxonomically identified from this area. All the forestry operations including collection of NTFP have been stopped by Government of India and State Government from the core zone. Some forest living tribes inhabit in the core zone. Their population is low and distributed sparsely from each other.

B. Buffer zone surrounds the core zone and consists of 28396.889 ha. It consists of protected and reserve forests as well as small agricultural land in between, running

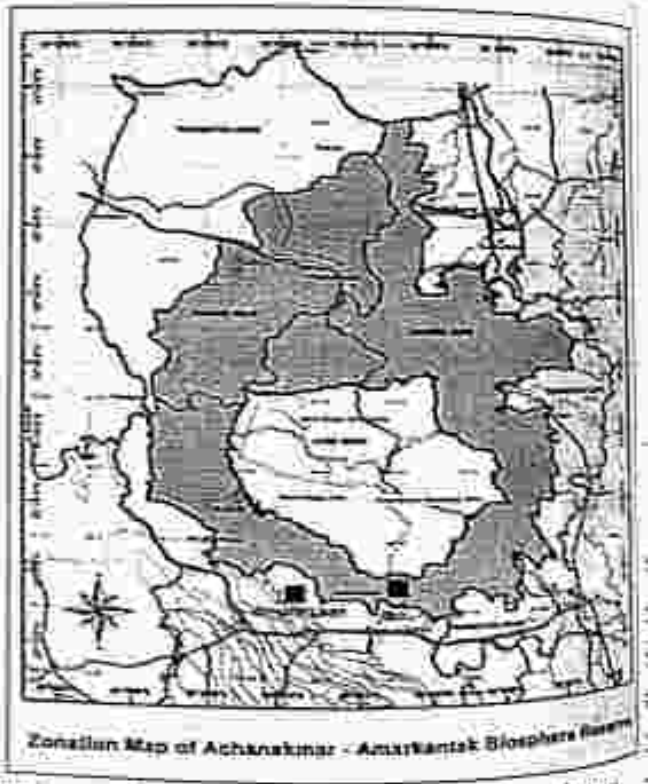

Figure.3: Zonation Map of Achanakmar Biosphere Reserve

vater, small tempotary water Check dam, built p areas and scattered settlement.

C. Transition zone is the outermost area f the BR consisting of approximately 99999.111ha. It covers the buffer zone. It onsists of reserve forests, managed forests, gricultural land, builtup areas and ettlements. Achanakmar-Amarkantak BR ontains 418 revenue and forest villages. Of hich, 396 villages exist in buffer and ansition zones. In all, about 4, 17,643 eople live in the BR as per census 2001. ribal population residing in BR consists of 8.1% and schedule caste population is .46%.

TANDARD FCC MAP OF THE TUDY AREA:

he following map is a standard FCC map f the study area which mainly reflecting red olor almost throughout the map. This red olour actually indicating vegetation covers.

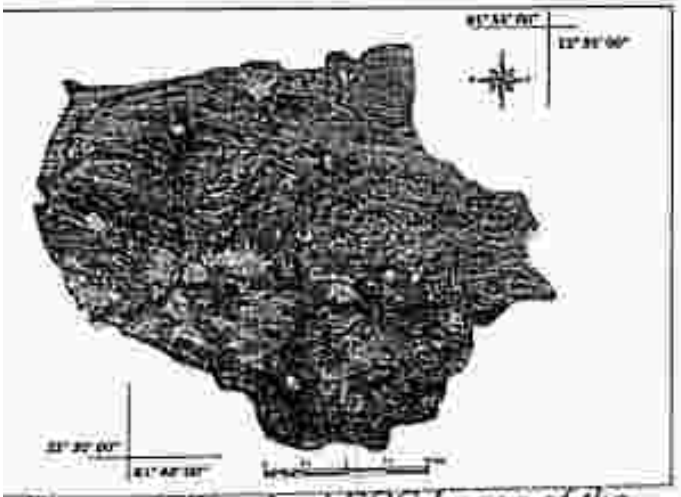

Figure.4: Standard FCC Image of the Study area

s it is a forested area, red is a very common olour but there are variations of the colour. ome parts are very deep and some patches owing light reddish. Ground trusting and oss check from Google satellite map owing that deep red reflecting areas are low elevated area where high altitude forest area showing light reddish reflection. The reason basically is that the reflection of sunlight was greater on high altitude and lesser on low altitude. Some parts mainly in the middle and south western part showing bluish reflection which is actually agricultural land cleared by the local people. It proofs that human community lives there. The sinuous bluish lines across the map are indicating flow of river. No other important features could be fond from this FCC map as it is a forested land covering a large area and it is also a low quality LISS III image.

LANDUSE CLASSSIFICATION:

The area under different land categories is given in the table no1. Only 4 land categories have been found in that area as it is a densely forested area and also the core zone of Achanakmar Biosphere Reserve. Among the total 551.15 sq km area, most of the area (517.9133 sq km) is under vegetation cover. Among them 242.3203 sq km is moderately dense forest and 275.593 sq km is dense forest. Only 29.1024 sq km land area is open or may be classified as agricultural with settlement. Few rivers are also found which is categorized as water bodies.

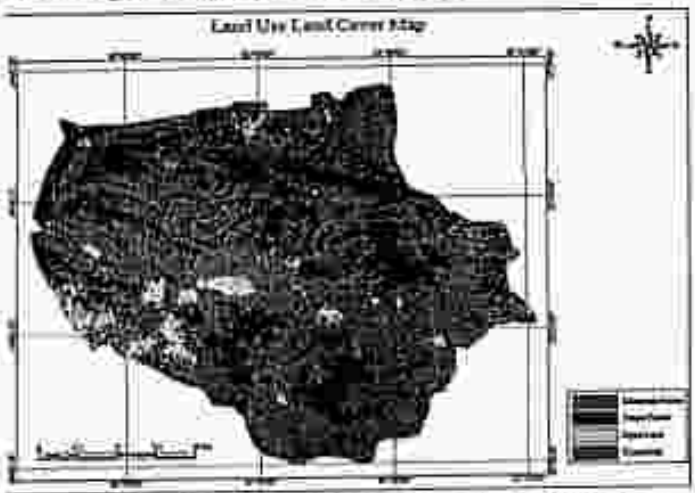

Figure.5: Land Use Land Cover Map of the Study Area

ISSN No. 2347-2685

Land Use Category	Area In Sq Km	Area In %
MODERATE VEGETATION	275.893	50
DENSE VEGETATION	242.3203	44
OPEN OR AGRICULTURAL LAND	29.1024	5
WATER BODIES	3.59	1

Table.1: Area of Different Land Categories

NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX CLASSIFICATION:

Table 2 shows that the range of NDVI is from -0.38047 to 0.79653 in the above mentioned year. It is clear from table 2 that only 7.93 percent of that area is remaining without vegetation cover which is indicated by red colour. Rest of the area is covered with vegetation. Only 10.63 % of the area is under sparse vegetation cover and 29.28%, 23.30%, 28.80% is covered with relatively low dense, moderately dense and high dense vegetation cover. As it is a core zone of a forest it is normal that the area will be under thick vegetation cover. This classification depicts that almost 80% of the area is covered with thick vegetation cover with NDVI value of more than 0.67500.

NDVI COLOUR	MINIMUM VALUE	MAXIMUM VALUE	PERCENTAGE OF AREA	REMARKS
	-0.38047	0.65000	7.93	No Vegetation
	0.65001	0.67500	10.63	Sparse Vegetation
	0.67501	0.70000	29.28	Low Dense Vegetation
	0.70001	0.71500	23.30	Moderately Dense Vegetation
	0.71500	0.79653	28.80	High Dense Vegetation

Table.3: Vegetated Area Classification

CONCLUSION:

The area is under thick vegetation cove but there are some patches of non vegetative area that is mainly agricultural land cleared by the tribal community for cultivation. It is obviously alarming that more a large amount of area is occupied and cleared by human community. As per the forest conservation rule core zone of a biosphere reserve should be intact and kept absolutely undisturbed. A core zone secures legal protection and management and research activities that do not affect natural processes and wildlife are allowed. Strict nature reserves and wilderness portions of the area are designated as core areas of BR. The forest authority has to consider this problem. That is the reason the forest authority arranging for rehabilitation and resettlement in the periphery of the BR for the tribal people residing in core zone.

REFERENCE:

Ahmad Hassan, Nusrath Asima 2010: Vegetation change detection of Neka River in Iran by using remote sensing and GIS. Int. Journal of Geography and Geology, vol. 2, No. 1; pp 58-67

Bannari, A. D.; Morin, F.; Bonn, and Huete, A. R. A Review of Vegetation Indices. Remote Sensing Reviews. (13), 1995, pp. 95-120. Clark labs, (1999) IDRISI for Windows, URL http://www.clarklabs.org/03prod/idrisi.htm

Daniels R.J.R., (1989), A Conservation Strategy for the Birds of Uttara Kannada district, Ph.D thesis, Centre for Ecological Sciences, Indian Institute of Science, Bangalore, pg.: 27-47.

ForestryCommissionofGhana.OwabiWildlife Sanctuary,Kumasi,Ghana.2006.Availableat http://www.fcghana.org. Date Accessed: 10 February, 2011.

Wachiye SA. Kuria DN, Musiega D (2011) GIS based forest cover change and vulnerability analysis: A case study of the Nandi North forest zone. Journal of Geography and Regional Planning. 6(5): 159-171

WRI _ IUCN _ UNEP (1992). Global Biodiversity Strategy: Guidelines for Action to Save, Study and Use Earths Biotic Wealth Sustainably and Equitably.

Supervisor: Dr. Manjula Dubey
Dr.C.V.Raman University, Kota
Kajal Kr Sikdar, M.Phil. Scholar
Dr.C.V.Raman University, Kota

THE SOCIO-ECONOMIC EVOLUTION OF BAIGA TRIBE AT KOTA IN BILASPUR DISTRICT OF CHHATTISGARH

Debabrata Ghosh (Research Scholar)

ABSTRACT:

Chhattisgarh is dominated by tribal population. Tribals are aborigine of Chhattisgarh. Tribes of Chhattisgarh are unique in their lifestyles and have retained their own culture and traditions for centuries. Chhattisgarh is home for 42 different tribes, including 5 Primitive Tribal Groups (PTG). Baiga Tribe inhabited in ten villages of Kota block of Bilaspur district in Chhattisgarh state was selected for the study. The selection of the Baiga Tribe for study was based on the fact that they was identified as one of the Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) of India; because of their isolated living, dependency on forest economy, low literacy and high mortality rate. According to census 2011 the total population of the Baiga tribe in Chhattisgarh is 89744, which is 0.35% of the total population of the state (25545198). Though government of India and state government of Chhattisgarh provide special attention for the development of primitive Tribal groups, yet the literacy level, income and living condition of the Baiga tribe in comparison with other tribes are much discouraging. They are still facing the problems of hunger, malnutrition, poverty, poor literacy, poor health facility and deprivation from natural resources. In order to get clear view of these issues this study attempts to examine the changing socio-economic conditions and livelihood of the Baiga Primitive Tribal Group and impact of various tribal developmental schemes implemented among them. Two main research approaches; structured questionnaire and semi structured interviews were used in the data collection. A structured questionnaire together with open-ended question was used to collect quantitative and qualitative information on demography, household and other socio-economic characteristics of Baiga tribes in selected villages of Kota block in including population, Age-Sex Structure, working population, household income, housing condition, health and sanitary condition, education and literacy and transport and communication. An open-ended questionnaire was designed for selected group and community leaders to solicit their views and perceptions.

Key words: Aborigine, Primitive Tribal Group, Particularly Vulnerable Tribal Group, Demography, Age-Sex structure.

INTRODUCTION:

Kota Block of Bilaspur District, is lies between 22° 21' 32.13'' N to 22° 20' 17.86'' N latitude and 81° 55' 34.9'' E to 81° 56' 08.11'' E longitude. It has an average elevation of 330 meters (1082 feet) above mean sea level. It has a total area of 779.09 sq km. Kota Block of Bilaspur District is recognized as a "Scheduled area" by the government of India. Kota is inhabited by number of tribes like Agariya, Andh, Baiga, Bhaina, Binjhwar, Birhor, Dhanwar, Gadaba, Gond, Halba, Oraon, Sahariya, Sawar etc. Among the various tribes, Baiga is the most vulnerable tribal group in Kota. As a forest living community previously they are totally depend on forest for their livelihood and practiced shifting agriculture. But In order to prevent deforestation government of India constituted numerous acts regarding the protection of the forest. It is argued that the constitutional acts regarding the protection of the forest had both positive and negative effects. On one hand, it has made it possible for the country to preserve some of its forest resources and on the other hand, the constitution of the forest reserves had taken agricultural land from the forest fringe Baiga tribal communities, which had negative impact

on their livelihood. Due to the forest reserve acts they are now compelled to do settled agriculture outside the forest area into small patches of land. Besides settled agriculture they also worked as agricultural laborers, craftsmanship and daily wage laborers. They are still engaged in traditional age-old practices, such as hunting, food gathering, fishing and shifting cultivation (locally known as "Bewar" cultivation) for their livelihood, though in a rudimentary manner. So there is an urgent need to take suitable policy measures for the wholesome and sustainable development of the Baiga tribe.

OBJECTIVE OF THE STUDY:

The overarching purposes of this research is to measures recent scenarios regarding the socio-economic development of Baiga tribe in few selected villages of Kota block of Bilaspur district and also assess the effects of forest reserve acts and of increasing deforestation on the livelihood patterns on the Baiga tribe in the study region.

In line with that some specific objectives have been set to help realize this ultimate purpose. The study was undertaken with the following major objectives –

(I) To examine the spatial distribution and growth of Baiga tribal population in some selected villages of the study region (Kota block).

(II) To find out the different sources of livelihood of the selected primitive Tribal Group (Baiga Tribe) and how does it vary amongst the primitive tribal households in the study area.

(IV) To evaluate the occupational structure of Baiga tribal population.

(V) To find out the changes in socio-economic conditions of the Baiga tribe in recent years.

(VI) To find out the impact of developmental intervention on the selected primitive tribal community (Baiga tribe) in the study area (Kota block).

(VII) To provide suggestions to alleviate poverty and to take the primitive tribal community to the main stream.

LIMITATIONS:

The data has available in terms of Government Published Records, Gram panchayat, District statistical abstracts, Census handbooks, and Tribal Development Department of Chhattisgarh and local tribal people. Lack of upgraded data available in Government Published Record and each Village level has lead problems for data collection and therefore data collected during field work do not match with government records. Beside this, information given by tribal people during field work was also inadequate hence interpretation is entirely based on available data and information in the context of present study.

MATERIAL AND METHODS:

The survey to collect data, presented in this paper was conducted during the period of 2015-2016 in ten selected villages of Kota block namely Lufa, Upka, Baheramuda, Karwa, Kurdar, Umariya, Chhuiya, Tatidhar, Sargond and Nawapara. The two main research approaches, structured questionnaire and semi-structured interviews were used in data collection. Baiga tribe inhabited in aforesaid villages of Kota block of Bilaspur district purposively selected for the administration of the questionnaire. A structured questionnaire together with open-ended question is used to collect quantitative and qualitative information on demographic, household and community characteristics including population, Age-Sex Structure, working population, household incomes, farm sizes and tenancy arrangements, housing condition, health and sanitary condition, education and literacy and transport and communication. An open-ended questionnaire is design for selected group and community leaders (such as village chief, assembly men and Panchayat committee members) to solicit their views and perceptions.

Respondence was then interviewed in each of the selected settlements. In addition to the community questionnaire, institutional level data is also collected from forest offices and also from the tribal development institutions or board of Bilaspur district.

RESULTS AND DISCUSSION:

The Baigas are a forest community of Chhattisgar. The Baigas are a Primitive Tribal Group (PTG), also known as Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) inhabiting the remotest forest areas of Chhattisgarh. Ethnically the Baigas belong to proto-Australoid group of people. The name "Baiga" implies priest, sorcerer or medicine-man. They are famous for their traditional healing practices. The Baigas are some of the very few tribes remaining in Chhattisgarh, who have not been greatly affected by mainstream civilization and exhibit the earliest form of human life and cultural evolution.

Population:

According to census 2011, the total population of the Baiga tribe in the country is 3, 90,000.According to census 2011 the total population of the Baiga tribe in Chhattisgarh is 89744, which is 0.35% of the total population of the state (25545198).

Baiga Tribe Population In Chhattisgarh

Sl.	Census	Total Population	Baiga Tribe Population	%
1	2001	20833803	[illegible]	[illegible]
2	2011	25545198	89744	0.35

Source: Census of India

Location:

Baiga tribal community mainly settled in northern districts of Chhattisgarh. They are mainly inhabited in Surguja, Korea, Bilaspur, Korba, Rajnandgaon and Kawardha district of Chhattisgarh.

Occupation:

The Baiga tribes have various mode of livelihood. They still enjoy their traditional mode of livelihood such as hunting, food-gathering and fishing. Previously they were shifting cultivators, but now they practice settled agriculture, craftsmanship, pastoralism and labor hood.

Socio economic condition of Baiga Tribe at Kota Block:

Among many tribes inhabited in Kota, Baiga is one of the most vulnerable tribal groups. They are mainly concentrate in forest fringe villages like Lufa, Upka, Baheramuda, Karwa, Kurdar, Umariya, Chhuiya, Tatidhar, Sargond, Nawapara and many other of such villages of kota block. In Kota block more than 1000 family of the Baiga tribe is settled in forest fringe villages.

There are some socio-economic condition of the studied group are given below-

- Previously they were totally depending on forest for their livelihood but due to the forest reserve acts they are now practiced settled agriculture, though in a subsistence manner. Due to lack of modern agricultural techniques and machineries the production from agriculture is very low. Besides that they also face drought during summer season. So low agricultural production and crop failure are the two main reasons of their dependency on traditional livelihood practices such as hunting, fishing and food gathering, till today.
- The young generations of this tribe are now engaged with various economic activities such as crafts making, worked as daily wage earners and in some cases non timber forest products seller. Some of them migrated to the nearby cities or town for earnings.
- The literacy rate is very low among the Baiga's. Most of the peoples are illiterate, in some places it is below 30%. Inadequate educational facilities are found in most of the villages, which

ISSN No. 2347-2685

hindrance the development of the tribe.

- Inadequate drinking water facility is another problem faced by this people. Most of the villagers suffer acute drinking water shortage during summer season. Though the government set up some tube well but is not sufficient enough to supply water at regular basis.
- Geographically isolation and backwardness coupled with their faith and reliance on magico-religious practices are the main reason of poor health status. Besides this Lack of sanitation, poor living condition are other major factors that attributed to poor health of the studied group. Intensity of skin disease and diarrhea is high among this tribe in studied areas.
- Due to their isolated living and unawareness they are constantly exploited by contractors, money lender and middle man.
- Various tribal development schemes and programmes of the central and state government for the development of the tribal people are not implemented properly in the studied areas.

REFERENCES:

- Bose, Nirmal Kumar: Tribal life in India. (National Book Trust, NewDelhi, 1971)
- Burman, B K R: Tribal situation and approach to tribal problems in India. (Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies, New Delhi,1995)
- Fuchs, Stephen: Aboriginal Tribes of India. (Macmillan India, 1974) Ghurye, Govind Sadashiv: Scheduled Tribes of India. (Transaction Publishers, 1980).
- Majumdar, D N: Fortunes of Primitive Tribes. (Universal
- Publishers, Lucknow, 1944).
- Gautam, Rajesh K: Baigas the Hunter Gatherers of Central India (Readworthy Publication Pvt. Ltd., 2011).
- Dube, S.C: Tribal Heritage of India (IIAS, New Delhi, 1977).

Debabrata Ghosh (Research Scholar)
Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur

ISSN No. 2347-2685

THE IMPACT OF CAPTIVITY ON BEHAVIOUR OF WILD ANIMAL: A CASE STUDY FROM KANAN PENDARI,BILASPUR(C.G.)

Dipak Mandal (Research Scholar)

ABSTRACT:

Zoological Park is the most important methods of biosphere reserve in any place. The zoo park is a place where many kinds of animals are kept so, that people can see them. The total no of top 10 zoos have in India. Therefore the Arignar Anna zoological park is the largest zoological garden in India. The three biggest zoos in India these are: Nandankanan zoological Park, Bhubaneswar Park and Odisha Park.

Kanan pendari is a small zoo park, located in Bilaspur Chhattisgarh; which protected areas contribute to the national income through protection of animal species and habitats attracting large number of tourist. This study aims at estimating the total local economic value of conserving the rivers ecosystem to contribute to an understanding of potentials for conservation through tourism.

A two stage systematic random sampling design will be used to select about 150 respondents' socio-economic, perception and attitude, and contingent valuation surveys. Data will be analysed with logic/probity models.

INTRODUCTION:

Kanan pendari is an ex-situ biodiversity conservation centre. It is located in bilaspur, Chhattisgarh. Chhattisgarh founded by Jharkhand and Orissa in east, Andhra Pradesh in south Maharashtra, Madhya Pradesh in west Uttar Pradesh in North.

Bilaspur is famous for Kanan pendari Zoo Park. It is a small zoo situated near Sakari, approx 10 kms from Bilaspur on Mungali road. Kanan pendari is situated in the extension of22° 06' 19.2"N to 22° 07' 0.40" N latitude, and 82° 03' 20.4"E to 82° 04' 23.5" E longitude.

Kanan pendari zoological garden situated In Bilaspur district, tehsil of Takhatpur, which is located near the Bilaspur tehsil. This is famous zoological garden of all over Bilaspur. The northern boundary of this district is bounded by Arpa River. Southern boundary is bounded by Maniari River and western is demarcated by Seonath River. The district covers of an area of 4905.59 heet. Approximately, the district is surrounded by Janjgir-champa and Korba to the east Kowardha, Durg and Raipur to the south, Koriya is the north and Madhya Pradesh is situated in the western portion of the district. Its altitude from the mean sea level is 262m.

We have also been collecting the secondary data from different sources. After collecting all the relevance data we have statistically analyzed the data prepared different diagrams for representation physical characteristics of the study area.

Last of all we have also recommended some management procedure for the sustainable

development of the study area.

Objectives:-

Captive enclosures are, by their very nature, likely to be more simplistic than natural habitats, and this has both advantages and disadvantages for the exhibited animals. On the one hand, food is in plentiful supply, travel distances are small, health is closely monitored, mates are often provided and there are no predators.

The basic objectives of the study area (Kanan pendari, bilaspur) has been maintained as below-

i. To know the physical environment of the study area.
ii. To assess the socio-economic environment of the study area.
iii. To identify the basic biosphere reserve of the study area.
iv. To know the occupational pattern change in occupation structure dew to development.
v. To analysis the life cycle on captive behavior of wild animals.
vi. To know the various problems in ecosystem of the study area.
vii. To know the development tourism and affect on wild animal of the study area.

Selection of study area:-

Chhattisgarh, being a new state after 1st November 2001, importance of Bilaspur district has increased. Bilaspur district had been broken and it was comprises with ten blocks. It is situated in almost north-western portion of Chhattisgarh. Here Kanan pendari is a very famous zoo of Chhattisgarh.

Bilaspur is famous for Kanan pendari zoo park. It is a small zoo situated near Sakari, approx 10 kms from Bilaspur on Mungali road.

Kanan pendari zoological garden situated In Bilaspur district, tehsil of Takhatpur, which is located near the Bilaspur tehsil. This is famous zoological garden of all over Bilaspur.

This is very well tourist spot and unique biodiversity zoo, I chosen this topic for analysis.

Methodology:

The whole system of field study can be divided into following process, these are-a) pre-field study, b) during field study and c) post-field study.

The main approaches to the study area (kanan pendari,Bilaspur district,chhattrishgarh) explain the physical condition given by the help of various information. This information collection from various methods, such as questionnaires and semi questionnaires interview structure. After that data will be analysed with logic/probity models. This information is sequence tabulation and used the different cartographics and statistical techniques, example- map, diagrams, charts, relationship between two variables and so on.

DISCUSSION:-

Concept of Biodiversity:

Biodiversity is the degree of variation of life.

ISSN No. 2347-2665

It is a measure of the variety of organism in different ecosystem. This can refer to genetic variation, ecosystem variation or species variation within an area or planet. Terrestrial biodiversity trend to be highest near the equatorial region which seems to be the result of the warm climate and high primary productivity. There are latitudinal gradient in the species diversity. Bio-diversity generally trend to cluster in hotspot and has been the future increasing through time but will be likely to show in the future.

The earliest evidences for life on the earth are graphite found to be biogenic in 37 billion. Year old met sedimentary rocks discovered in western Greenland and microbial mat fossil found in 3.48 billion year old sandstone discovered in Western Australia. Since life began on Earth. Five major mass extinction and several minor events have lead to large and sudden drop in diversity.

The period since the emergence of humans has displayed on ongoing biodiversity decrease and an accompanying loss of genetic diversity. Named the Holocene extinction, the decrease is caused primarily by human impact, particularly habitat destruction. Conversely, biodiversity impact human health in a number of ways. Both are positively and negatively.

The United Nations designed 2011-2020 as the united nation Decade on Biodiversity. The term biological diversity was used wildlife scientist and conservationist Rayond F. Dasman in the 1968 lay book a different kind of country advocating conservation.

Definition:-

"Biodiversity" is the most commonly used to replace the more clearly defined and long established term, species diversity and species richness. Biologist most obtain define biodiversity as the totally of "Genes, and ecosystems of a regions".

It has been defined variously such as –

"The richness in variety and variability of species of all living organisms in a given region (habitat)".

A concise definition of biodiversity is "the totality of genes, species, and ecosystems in a region (IUCN, UNEP, 1992).

Biological diversity is "the variety and variability among living organisms and the ecological complexes in which they occur". (U.S. Office Technology Assessment, 1987)

Concept of captivity:

Animals that live under human care are in captivity. Captivity can be used as a generalizing term to describe the keeping of either domesticated animals (livestock and pets) or wild animals. This may include, for example, farms, private homes, zoos and laboratories. Keeping animals in human captivity and under human care can thus be distinguished between three primary categories according to the particular motives, objectives and conditions.

Behaviour of animals in captivity:

Captive animals, especially those not domesticated, few times develop behaviours. One type of abnormal behaviour is *stereotypical behaviours*, i.e. repetitive and apparently purposeless motor behaviours. Examples of stereotypical behaviours include pacing, self-injury, route tracing and excessive self-grooming. These behaviours are associated with stress and lack of stimulation. Many who keep animals in captivity, attempt to prevent or decrease stereotypical behaviour by introducing novel stimuli, known as environmental

enrichment.

A type of abnormal behaviour shown in captive animals is self-injurious behaviour (SIB). Self-injurious behaviour indicates any activity that involves biting, scratching, hitting, hair plucking, or eye poke that may result in injuring oneself. Although its reported incidence is low, self-injurious behaviour is observed across a range of primate species, especially when they experience social isolation in infancy. Self-bite involves biting one's own body—typically the arms, legs, shoulders, or genitals. Threat bite involves biting one's own body—typically the hand, wrist, or Forearm—while staring at the observer, nonspecific, or mirror in a threatening manner. Self-hit involves striking oneself on any part of the body. Eye poking is a behaviour (widely observed in primates) that presses the knuckle or finger into the orbital space above the eye socket. Hair plucking is a jerking motion applied to one's own hair with hands or teeth, resulting in its excessive

Number of species:

List of table

Species	Earth			Ocean		
	catalogued	predicted	± se	catalogued	predicted	± se
Eukaryotes						
Animalia	953434	7770000	958000	171082	2150000	145000
Chromista	13033	27500	30500	4859	7400	9640
Fungi	43271	611000	297000	1097	5320	11100
Plantae	215644	298000	8200	8600	16600	9130
Protozoa	8118	36400	6690	8118	36400	6690
Total	1233500	8740000	1300000	193756	2210000	182000
prokaryotes						
Archaea	502	455	160	1	1	0
Bacteria	10358	9680	3470	652	1320	436
Total	10860	10100	3630	653	1320	436
Grand total	1244360	8750000	1300000	194409	2210000	182000

removal.

Hotspot:-

Keywords: -Chhattisgarh, Self-injurious behaviour

A biodiversity Hotspot is a region with a high level of endemic species that is under threat from humans. The term Hotspot was introduced in 1988 by Dr. Sabina Virk, while Hotspot is spread all over the world. The majority are forest areas and most are located in the tropics. Brazil's Atlanta forest in considered one such Hotspot, containing roughly 20000 plant species. Accurately measuring differences in biodiversity can be difficult. Selection bias amongst researchers may contribute to biased empirical research for modern estimates of biodiversity. In 1768 Rev Gilbert white succinctly observed of his seaborne, Hampshire "all nature is so full, that district produces the most variety which is the most examined".

Total species of earth and ocean

Conservation status of different animals groups (percentage values are out of total species survived for conservation)

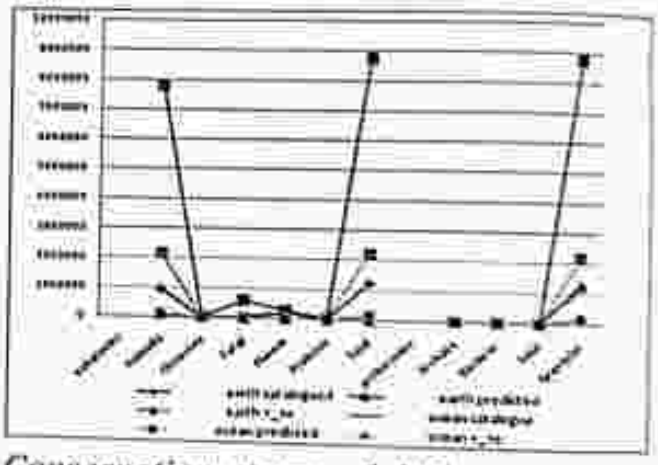

List of table

Status	Mammals	Birds	Reptiles	Amphibians	Fishes
Not currently threatened	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nearing threatened	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Vulnerable to extinction	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
In immediate danger	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Source: IUCN Red list of threaded animals, IUCN World conservation union, Gland, Switzerland (1997)

ISSN No. 2347-2685

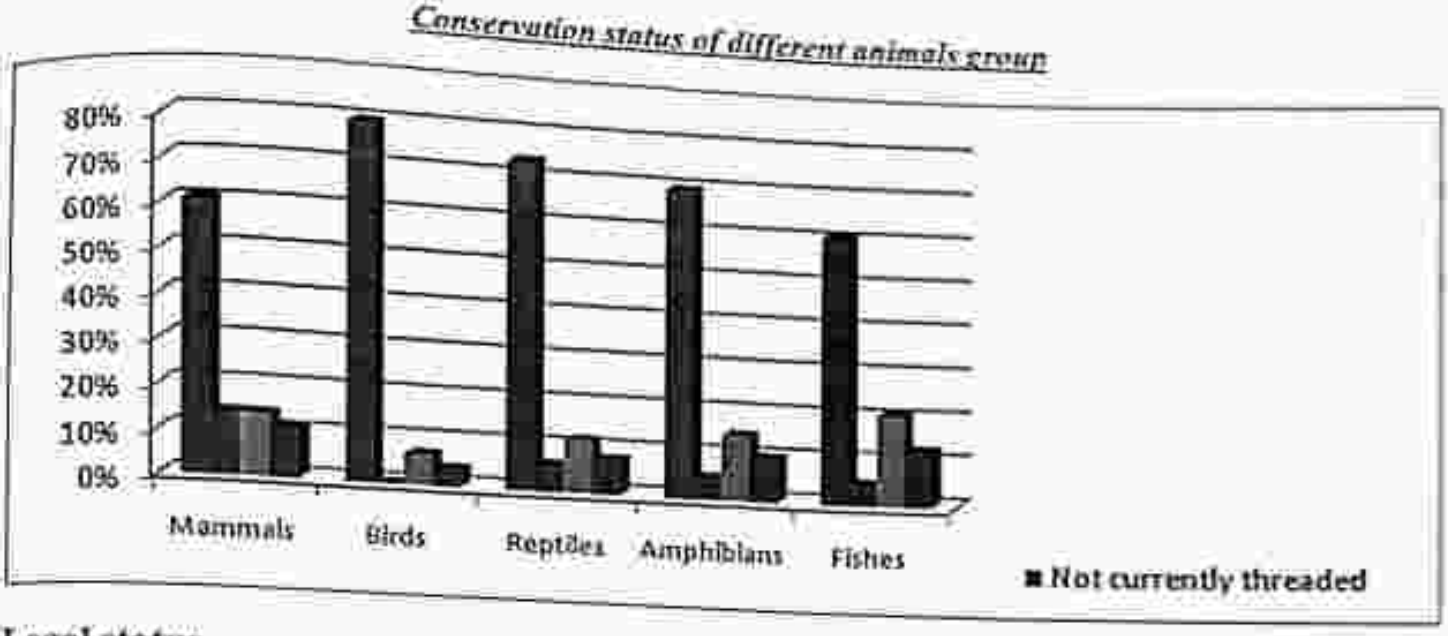

Legal status

A great deal of work is occurring to preserve the natural characteristics of Hopetown Falls, Australia while continuing to allow visitor access.

(A) International

- United Nations Convention on Biological Diversity (1952) and Cartagena Protocol on Bio safety;
- Convention on International Trade in Endangered Species (CITES);
- Ramset Convention (Wetlands);
- Bonn Convention on Migratory Species;
- World Heritage Convention (indirectly by protecting biodiversity habitats)
- Regional Conventions such as the Apia Convention
- Bilateral agreements such as the Japan-Australia Migratory Bird Agreement.

(B) National level laws

- Biodiversity is taken into account in some political and judicial decisions: and duties (for example, fishing and hunting rights).
- Law regarding species is more recent. It defines species that must be protected because they may be threatened by extinction. The U.S. Endangered Species Act is an example of an attempt to address the "law and species" issue.
- Laws regarding gene pools are only about a century old. Domestication and plant breeding methods are not new, but advances in genetic engineering have led to tighter laws covering distribution of genetically modified organisms, gene patents and process patents. Governments struggle to decide whether to focus on for example, genes, genomes, or organisms and species.
- India passed the Biological Diversity Act (B.D.A) in 2002 for the conservation of biological diversity in India. The Act also provides mechanisms for equitable sharing of benefits from the use of traditional biological resources and knowledge.

Keywords: Convention international trade Endangered species,
Biological Diversity Act
Kanan pendari as a biodiversity zone;

There is now unequivocal proof that biodiversity decreases reduces the efficiency by which ecological species capture biological essential resources, produce biomass, decompose and recycle biologically

essential nutrients. There is mounting proof that biodiversity enlarge the stability of ecosystem functions through time. Different types of communities are more productive because they contain key species that have a large affect on productivity and various in functional traits among organisms increase total resource capture. The impacts of diversity loss on ecological process might be enough large to rival the impact of many other global diver of environmental change.

It plays part in the regulating the chemistry of our atmosphere and water supply. Biodiversity is directly involved in water purification, recycling nutrients and providing fertile soil. Experiment with controlled environments has shown that humans cannot easily build ecosystem to support human needs. Kanan pendari is a short but very strong biodiversity zone.

List of Reptiles

Sl no.	Name of the reptiles	Total number
1	Corba Indian	15
2	Indian Monitor	2
3	Kait Common Indian	1
4	Python Indian-Rock	8
5	Sand Boa	4
6	Snake Banded Kaite	3
7	Snake Rat/Dhaman	7
8	Viper Russells	5

Reptiles of the Kanan pendari zoo

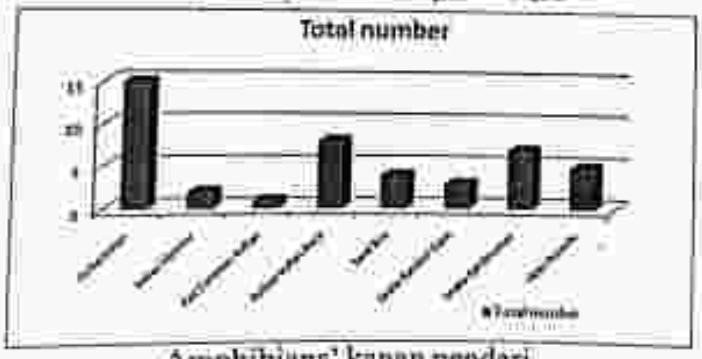

Amphibians' kanan pendari

List of table

Sl no.	Name of the amphibian	Total number
1	Ghariyal	2
2	Star Tortoise	2
3	Crocodile Marsh	6

Conclusion:-

The overall objective of a research design was to explore the role of forest ranger workers in collection and Distribution of forest wild animals.

Ab0ve the discussion we told that, kanan pendari zoo, Bilaspur district (C.G) is one of the most important zoological garden in India basis on ex-situ conservation. In this garden are affected different problems such as-i) increase children park ii) electrick iii) summer seasional problems iv) habitat problems v) meditation vi) deforestation vii) overpopulation etc. In this resent time such as that, the huge amount of tourist gathering ,as a result of this garden all the species don't the genetic growth. So, in this time all the local public, (nearest settlement) tourister and government activity are very strong.

References:

(1) Thomas. S. & Sidhartha. K.: Biosphere, A Geography of life- (2007), Kisalaya Publishers.
(2) Singh.S. Environmental geography-(2013). Prayag Pustak Bhawan, Allahabad.
(3) Tripathi. K. & Chandrakar. P. L. &: Chhattisgarh Atlas-(2012) Edition: Sarada publishers.
(4) Chapman. G. P.: Human and Environmental system-(1977): A Geographers Appraisal Academic Press, London.
(5) Das, N.G (1992) "Statistical method, Manasi Press. India
(6) Yin, R.K. 2003. Case study research: design and methods. Applied Social Research Methods Series 5. Sage, Thousand Oaks.
(7) Carl stead, K. 1996, Effects of captivity on the behavior of wild mammals. In: "Wild Mammals in Captivity", Eds. Kleiman D.G, Allen M.A., Thompson K.V. and Lumpkin S, University of Chicago Press, Chicago.
(8) P.D. Sharma "Ecology and Environment", eleven editions (2013), Rastogi publication.

Dipak Mandal (Research Scholar)
Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur

ISSN No. 2347-2685

MARKETING ORIENTED ORGANIZATION AND ITS VALUES

Dr. H.L. Agrawal, Dr. S.C. Bajpai

ABSTRACT :

Success of an organization depends upon its attitudes, feeling and behavior of its employees. The corporate must have human characteristics and qualities. These very human qualities are responsible for incredible, success of any business organization.

Business operation is subject to change, location change, people change but company must never change its principles. There may be certain bedrock but company's principles should be the guiding force for its business activities. Its principles must remain irrevocable, deeply embedded throughout times.

NTRODUCTION :

Companies must have a code of ehavior articulated for them. An ambitious ntrepreneur wants his company to be inancially successful but he also wants to eflect some personal values which become the foundation for his new company and he xpects that any one who worked for the ompany must know exactly what this rganization is all about.

Business organization must rticulate the following uncomplicated and asily understood values. They are:-

. Respect: - The individual must be espected

2. Service: - The customer must be given he best possible service

3. Excellence: - excellence and superior erformance must be pursued.

There commitments should emain at the heart of the company's peration. It should be so revered and en compassing that every action and policy should be directly influence by them .These philosophy has more to do with the company's success than its technological innovations, marketing skills or financial resources. These values. Principles and philosophy can not be patented however it can be said that any company can not become great without them. These commitments should not become an empty ' slogan. These principles are like muscles that turn soft and weak if they are not exercised regularly.

VALUES :

To be important in business environment principles values articulated must first be clearly understood by every one in management. They must be articulated to every employee and respected so often that every one understand just how seriously they are to be taken. The organization -should conscientiously drives home its philosophical message at meeting, in article, publications and memos, at company's gathering and in private conversations. These actions work and employees understand that not only company's success is dependent upon their faithful adherence to these values but so is their personal success. It takes time but once employees believe them, every facet of business positively affected.

1. **The First commitment: -**

The individual must be respected.

Almost all culture and religion advocate respecting the rights and dignity of individual. While almost everybody agrees to this idea but seldom is it found in the doctrine of business.

Many employers abuse their employees, demean them by overtly and outrageous action and hurt their self esteem subtly and covertly. The company should do something to stop such disrespect to employee who works for the organization. They should feel good about themselves and their work. No one can be paid enough money to be compensated for being made uncomfortable and unhappy by his supervisors. It is very simple that if we respect one people and help them respect themselves, the company would certainly profit.

It is to be understood that people, not money or things are company's greatest assets. The stress should be that every individual makes a difference. Every employee gets paid on the basis of what he produces not this longevity. Productive people need challenging assignments. It is important for them to go home at night with feeling that they did something worthwhile and when they enjoy their work and know company cares about them they want to contribute to its growth.

There should be a very democratic environment when everyone is treated with the same respect. Management should treat everyone who works in organization with respect and in turns expects everyone to treat customer and even the competitor the same way.

The code of conduct for selling must be on merit of products and services, self strengths and never try to exploit someone else's weakness.

When one respect the individual one show consideration for all people in and out of the company and that commandant must be reinforced constantly by one's actions.

Respect for the individual is not platitude. It is constant. It should be continuous, reemphasized and consciously made a part of our day to day business relationship. This will dramatically change business performance.

2. **Customer Service:-** A marketing organization should provide the best services in the world. To accomplish this company should mandate to be a customer oriented company. That is every part of company's operation should be focused on the customer requirements. Every employee's job profile should be related to company's goal of providing customers prospects and vendors with the best possible service. Company should provide such kind of treatment to every customer that makes them feel important.

To let the customers know how important he is. The organization should try to respond to if not resolve, any complaint within twenty four hours of its receipt. If the customer request is received by call center the response should be even quicker preferably within one hour. Specialist services may be provided via toll free numbers to solve problems.

An organization has to establish that each new product be superior in quality to the one it replaces and to comparable products in the market place .The organization has to strive to provide its customers with superior product and services.

The quality of its services depends

ISSN No. 2347-2685

upon the training and education capabilities of an organization. The largest financial allocation should be made for training and education programmed. Customers may be invited to participate in variety of classroom programs.

In marketing industries where repeat business is essential for long term growth it is essential to make sure that the initial order is only the beginning. Outstanding is what keeps the customer focus to do more business.

3. **Excellence** : Third ethics of marketing organization is excellence and superior performance .It means to pursuit all tasks to be accomplished in a superior fashion. The constant goal being zero defects in product and services. All though perfection is never possible but to aim for less would lower the expectation and weaker the goal for excellence. Yet striving for the impossible the company may establish certain satisfaction indexes to establish the quality of its services.

Excellence beings with the recruiting program .Best student of best school from all over the country be selected who may be responsible to company's training program and motivated to do superior work. After selection superior training be given so that they must feel compelled to succeed in highly competitive environment. There should be no room for individual complacency. The insistence should be on peek performance so that people began to think that anything can be achieved and is possible. This attitude will generate excitement.

When an organization demand and gets excellence from its employees eventually becomes contagions. Its customers also become optimistic and enthusiastic and think to do business with such organization

FINDINGS :

For any marketing organization to survive and achieve success above mentioned set of principles must be the base for its policies and actions. But the more important is to faithful adherence to these principles.

References :

1. Thomas, M. Garret, Business Ethics, The times of India Press, 1970.
2. Donald, P. Robin, Business Ethics, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 07632, 1989.
3. Edward, R. Freeman, Business Ethics, Oxford University Press, New York, 1991.
4. David, Murra;, Coopers and Lybrand, Ethics in Organisation, 1997.
5. Manuel, G. Velasquez, Business Ethics, 4th Edition, Prentice Hall International, 1998.

Dr. H.L. Agrawal, Professor & Head
Department of Commerce, C.M.D. P.G. College, Bilaspur (C.G)

Dr. S.C. Bajpai, Asstt. Professor,
Department of Commerce, C.M.D. P.G. College, Bilaspur (C.G)

New Frontiers Of Research Vol. 3 Dec. 2016 ISSN No. 2347-2685

Marketing Strategies in Library

Mr. SALIK RAM

ABSTRACT :

Libraries have been considered essential to educational and research endeavors and have relied on institutional financial support for their continuing operations. The value of the library is also being called into question with increasing "googleisation" and new generations of users are making new demands on library service provision. Directors of libraries are competing with multiple demands for funding on their campuses. They must understand client needs, plan service provision, promote the available services, deliver them efficiently and effectively and fight for financial and other support. Marketing has become an essential tool in justifying fund requirements. Using various market research techniques including surveys, focus groups and analysis of suggestions, libraries can understand the needs and design appropriate services and facilities. As librarians we should be actively marketing and promoting our library services. This paper aims to demystify marketing for librarians. Practical solutions are provided on how to implement a marketing strategy, with particular emphasis on the value of using electronic information resources.

Keywords: Marketing, Library Marketing, Marketing Strategies, process which identifies, anticipates and supplies customer requirements efficiently. Thus the essence of marketing involves finding out what the users want, then setting out to meet those needs. Librarians are participating in this process of assessing their users' needs and trying to fulfill them. Thus, we are already marketing our library information skills. However, in order to do this effectively librarians need to embrace the total marketing function involving market research and analysis, service planning and promotion.

Definition :

Marketing is a process which carries goods from producers to ultimate consumers. Marketing, in its broader sense, is the social instrument through which the material goods and culture of a society are transmitted to its members. Marketing, in the library context, refers to those instrument through which information (both raw and processed) are transmitted to its members. According to Kotler, "Marketing is the analysis, planning, implementation and control of carefully formulated programs designed to bring about voluntary

Introduction :

The challenges to library services from changes in educational approaches, the impact of technology, new methods for information provision and declining budgets have meant that marketing is now so essential that it cannot be considered a separate function. Many libraries have come

ISSN No. 2347-2685

to appreciate the contribution and application that marketing concepts can make. In designing the marketing mix and developing the marketing plan, the socalled 7Ps have become central to libraries – product, price, place, promotion, participants, physical evidence, and process. Marketing is frequently viewed as a set of strategies and techniques that belong to administrators other than librarians. However librarians are involved in the process of marketing. Marketing is the management exchanges of values with target markets for the purpose of achieving organizational objectives. It relies heavily on designing the organization's offering in terms of target markets needs and desires, and on using effective pricing, communication, and distribution to inform, motivate, and service the markets." Similarly Stanton has opined, "Marketing is a total system of interacting business activities to plan, price, promote and distribute want satisfying products and services, and present to potential customers." The above definitions call for various activities in marketing. They are:

1. Market research and customers' analysis
2. Development of products and services
3. Pricing
4. Distribution
5. Promotion
6. Evaluation of products and services.

All the above mentioned activities of marketing as applied to other industrial sectors are equally applicable in the area of information products and services. Whether it is for profit or nonprofit sector, methods remain the same while the policy varies.

Objectives and Marketing Goals:

Once users' needs, future trends and resources available have been established the librarian is in a position to plan the marketing objectives, the resources to be used, the place and the time scale of the operation and the strategies required achieving them. The process of setting aims and objectives will serve a number of purposes. It will provide a focused overview of the library service and give direction and guidance in achieving the objectives .If any of the objectives change over time then the market plan will need to be updated.

Why Marketing ?

Information professionals must understand that it is essential to actively market their services. Library marketing is critical for any information professional in order to spread the word about their library. It doesn't matter what library type, it doesn't matter how large or small the library is you need to draw attention to your library, your services, your worth to your community, your administration, your staff, and your users. It is important to understand the organization's mission to produce effective marketing material that builds the library's brand and image, drives traffic to your web site, and differentiates your library from its competitors. That's why in this highly competitive industry marketing plays a very important role

- Planning Model
- Vision
- Community Assessment
- Service Response
- Mission
- Goals

Objectives :

Staff Collection Development Plan
Technology Marketing Development Plan

What products and services is the library marketing?

The library has many products and services that it can market. Each library needs to identify what it wishes to market and how. Marketing is not just about developing and promoting new services and products but also about bringing awareness to clients of existing services and products and determining their appropriateness.

Products are using in library

1. Maps 2. Government Documents 3. Databases 4. Electronic Resources 5. Microforms 6. OPAC 7. LibGuides 8. Website 9. STARS 10. Music 11. Audiovisual Resource 12. Computer system 13. Encyclopedia 14. Pen drive 15. CD/DVD. 13. Year book's. 14. Library S/W 15. Furniture 16. Rack. 17. Other electronic instrument

Marketing plan needs to be developed and implemented with ongoing enhancement of the services and products should follow. When the library is marketing its collections, in particular, the availability of new acquisitions like a new online patent database or a set of electronic journals, must be communicated to clients who need them. Donations of large research collections of potential use to particular disciplinary areas must be publicized. There is an enormous responsibility to ensure that value is received for the significant resource expenditure being made on many of these areas. New services like online versions of examination papers, the development of an eprint archive of institutional research papers, the use of plagiarism detection software and online thesis submission must all be publicized to potential users. For new products or services, part of the planning must involve the creation of a marketing and promotional strategy and the allocation of responsibility to library staff to ensure that the plan is carried through.

Marketing is directly linked to the planning process. Having a formalized plan and direction of where the library is going as opposed to being reactive to change and problems that arise, enables managers to successfully develop marketing strategies and successfully identify new services and products. Part of the planning is development of a suitable mission statement for both internal and external use.

Market Plan

In the light of information gathered from the market research the conclusions should be summarized and stated as the basis upon which the market plan is based. The market plan is the actual process which will establish the library's business goals and objectives and figure out how to achieve them. Katz (1988) calls marketing action most effective when the relevant activities are planned and coordinate. The suggestions for marketing the library services to the readers:

- Create a library web page for the users. A web page is a good way of promoting library information services and resources.
- Emails containing new library resources and tips on finding information are of great value at the critical stage.
- Use library wall space. The library can display different language study tools such

ISSN No. 2347-2685

as bilingual dictionaries, English thesaurus, dictionary of synonyms and antonyms, subject related dictionaries and encyclopedias.

- Attend academic lectures if the department you are responsible for has a prominent number of users. Librarians can meet users to discuss and gather information about their ineeds as well as to promote the offered information services.
- Links to "Help" services from all appropriate library web pages, where assistance may be needed.

7Ps of Marketing Strategies of libraries -

1. **Product :** Products or services of the general reference and information service department. This is, of course, the information, reference, and ancillary services that add value such as personal assistance, referral services, online database searches, document delivery, and interlibrary loan.

2. **Price :** Pricing of use of the library is usually that of the time and effort the user spends traveling to the library, as well as the time and effort spent

3. **Place :** Place of service, based upon knowledge of the market of a library, is essential in order to identify users and their discrete information needs and wants.

To expand the service area, the library may have branches, bookmobiles, or electronic
access, etc.

4. **Promotion :** Promotion includes utilizing persuasive information about general information services, and communicating this information to target market segments that are potential users. Five kinds of promotion include: publicity, public relations, personal representatives, advertising, and sales promotion.

5. **Participants Physical :** All human actors who play a part in reference and information services delivery, namely the library's personnel.

6. **Evidence :** The environment in which the reference and information services are delivered that facilitates the performance and communication of the service.

7. **Process :** The procedures, mechanisms and flow of activities by which the reference and information services are acquired.

Promotion :

Promotion is essentially the means of informing to users what you do and what you can do. The benefits for those who promote their library services include: increased usage, increased value in the organization, education of users and changed perceptions.

Promotion:

I. *How do we currently promote the Library and its products?*

A. Library News Blog/ Website Homepage
B. Library Facebook, Flickr, other social networks
C. Weekly campus announcements
D. Community Outreach
E. Campus Outreach
F. Website Events Calendar
G. Flyers on campus
H. Brochures
I. Advertised as a depository library

ISSN No. 2347-2685

J. Direct email to the department faculty
K. Outreach to departments
L. Signage
M .Publicity team
N. Library Tours and Orientations
O. Friends of the Library
P. Advertised on TV in galleria "Scala" Digital display

II. Future Promotional Ideas:

A. Promotional Events:

i. Authors Series
ii. Library Jeopardy
iii. Exhibits

B. Strategic promotion of new or existing services and resources

C. Web:

i. Blogs ii. Vlogs (Library TV)
iii. Social Networks
iv. Blended Courses
a) Giving
b) Supporting
v. Online Courses

The promotional plan emerges from the marketing plan. It is to do with how to achieve the objectives that have been forecast. It involves:

- a description of the service requiring publicity;
- description of the audience at which publicity is targeted;
- details of the campaign method to be employed including type of publicity to be used and method(s) of distribution;
- execution of campaign;
- analysis of campaign performance.

The setting of clear promotional objectives will also ensure that the success of the advertising campaign can be evaluated. From time to time it should be accepted that promotional activities have not met their objectives. The Medium Promotional activities can take many forms and the promotional media will depend on the nature of the target audience and on promotional objectives.

1. Personal Skills

Your manner whether in person or on the telephone, will affect your users' rating for the library. You need to be professional and use quality procedures but you also need to smile and establish a personal relationship with as many of your users as possible. If you react positively to complaints, people will be encouraged to tell you about other things they would like to be changed. Instead of defending your position think about their suggestions.

2. EMail

Where a large proportion of the users are on email it is an easy way of reaching them, quickly and cheaply. It can be targeted more precisely than most other methods and so are effective at reaching specific audiences. The staff responds quicker to emails than any other medium. By maintaining uptodate address lists different user groups can be targeted with different versions of the advertising 'message'.

3. The Internet

The Internet has the power to improve the library's image and to allow the library to offer enhanced services. Although it takes time to set up and maintain .services on the Internet, it can reap rewards in terms of user satisfaction and recognition. A library Web home page serves as a promotional tool advertising inhouse library services be handed out, and displayed on notice boards. The library notice board should be in a

ISSN No. 2347-2685

prominent place. Challenges faced by Librarians There are, f'course, challenges and difficulties faced by users, but it is also very important to consider the challenges to information librarians. Here are some of the major challenges:

1. Create a positive image

One of the biggest challenges faced by information librarians is to create a positive image as most users hold negative attitudes towards librarians. For decades, people thought of librarians as "trained" or "skilled" but not necessarily as "professionals" and have no idea about the qualifications or training requirements(Ajileyelaogun, 2004). In some Asian countries, librarians are simply retrieval clerks or have low social status, so users may consider themselves more competent and more knowledgeable than library staff and regard it unnecessary to approach a librarian for help. Therefore, the librarians need to demonstrate that they have got both qualifications and a variety of skills.

2. Be proactive

Language problems may hinder users from seeking assistance offered by the library (Patton, 2002). Some users have to rely on friends rather than librarians for information or instruction. All professional librarians have got to communicate with users about their services because exchanges between the service agent (librarians) and the customer (users) can elicit information about customer requirements, and also permit the services agent to explain the organization's products and how these can meet the customer needs (Rowley, 1998).

3. Build good relationship There is no real shortcut to providing good information services to users. According to (Curry & Copeman 2005), quality reference service involves a relationship between the user and librarian within a "Cycle of Dimension of Service": willingness to assist user~ knowledge (how to assist user)~ assessment (of user's need), and action (physically moving with the user).

4. Create a welcoming environment Librarian needs to develop the ability to create a welcoming environment, be patient, and build confidence with the users. When librarians are friendly, and welcoming and helpful, users are encouraged into the library, whereas, in a library where the librarians are unfriendly and lazy, users are driven away. It is reported the personality of the librarian determines the rate of utilization of the library by its users. If she/he is friendly and professional, the user will beconvinced that there is an approachable and reliable information expert in that library. If they are drawn to the library by the mien of the librarian, they will then be able to browse through the books and thus become aware of the availability of materials relevant to their studies and research, and the use of the collections increases (AjileyeLaogun,2004).

5. Know how to communicate well with users from different culturesInformation librarians need to learn ways of styles because the way people communicate varies widely between one aspects of communication style is language usage. Across cultures, some words and phrases are used in different ways (DuPraw, 2002). For instance, one user who had huge fines for a book he borrowed because he misunderstood the concept of returning a book. To him, "return" a book means putting it back on the shelf. Don't assume that the way you are

ISSN No. 2347-2685

behaving is the "right" way of doing things. Consider a variety of approaches to a procedure.

6. Respect for cultural differences

One of the significant barriers in crosscultural communication is the use of language. Librarians are not changing their style because of users communication difficulties~they are unaware of the language used and of the need to provide definitions or demonstrations of "peer reviewed", "call number" " fulltext", "subject heading" or "Boolean search". (Wang & Frank 2002) recommend that information services in libraries that are sensitive to and encompass differences in culturally influenced styles are more likely to be responsive to the information needs and interests of users. As information librarians become more aware of cultural differences, they will become better listeners and communicators and could communicate better with users from different cultural background. Indian Scenario The developments taking place the worldover have influenced the Indian librarianship as well. There have been a number of developments in marketing of library and information services in the country and some of these are mentioned below: The beginning of publication of literature on marketing of library dates back to 1980. The Indian Library and Information Science Abstract (ILSA) started abstracting in this area in early 80s. IIM, Ahmedabad, has developed a database on marketing of library services which is very helpful for researchers in many of the national professional associations and organizations, like Indian Association of Special Libraries and Information Centers (IASLIC), Indian Library Association (ILA), Society for Information Science (SIS), Medical Library Association of India (MLAI) and Management Libraries Network (MANLIBNET). In 1988, the first national conference was organized by IASLIC in 1988 (Kapoor & Chaterjee, 1988). SIS also selected the theme Information Marketing for its conference in 1995 (Kuldip Chand, 1996). During recent years it can be observed that marketing of library services has been included as subtheme in quite a good number of conferences and seminars. DESIDOC Bulletin of Information Technology has brought out special issues on marketing of library and information services twice in 1998 and 2002 besides covering articles regularly in volumes of the journal.

There has been increasing interest among researchers in this area. The topic of Marketing of Information and Library Services has been included in the syllabi of some universities in the country. The Indian National Scientific Documentation Centre's (INSDOC) MLIS programme of the Indira Ghandhi National Open University (IGNOU) have a blog on Marketing of Information Products and Services. Some other universities also give emphasis on this area in the syllabi, but only to a limited extent. Besides, associations, various agencies and institutions are organizing training programmes. Conclusion Marketing approaches are proving to be effective in assisting academic libraries to adjust to changes in its client base and will ensure that services delivered continue to fit the needs. The products and services provided by libraries range from knowledge access and research support to printing services and the provision of information skills, supported by one on one assistance and advice. Strategies examining the distribution and delivery of

ISSN No. 2347-2685

services and their successful promotion will ensure that those who need information are provided it. The budget cuts and the advent of sophisticated technology in the libraries have opened up the new vistas for marketing information products and services. If the libraries fail to catch hold of the opportunities, the scene will be captured by the commercial vendors.

We know that the users do not mind paying for the services if they are useful and available at reasonable price. Therefore, the marketing policy of the libraries needs 'careful planning, structuring, execution and evaluation with regular review'.

References :

1. Wang, J & Frank, D (2002). CrossCultural Communication: Implications for Effectiveinformation Services In Academic Libraries., Portal:Libraries and the Academy, 2 (2), 207216.
2. Katz, B. (1988). How to market professional services, Prentice Hall
3. Knealle, RA (2002). You don't look like a librarian. Retrieved: 10 March 2006, from http://www.librarianimage.net/perc.html.
4. Koontz C. M. & Rockwood, P. E. (2001). Developing Performance Measures within a Marketing Frame of Reference, New Library World, 102 (1163/1164), 146153.
5. Kotler, P. (1972). Marketing Management: Analysis, Planning and Control, NJ: PrenticeHall.
6. Kumar, SL & Suresh, RS (2000). Strategies for providing effective reference services for international adult learners. Reference Librarian no. 6970, 327336.
7. Patton, BA (2002). International Students and the American University Library'. ERIC Document No. ED469 810, p.132, 2002.
8. Rafiq, M. Ahmed, P. K. (1995). Using the 7Ps as a Generic Marketing Mix: An Exploratory Survey of UK and European Marketing Academics. Marketing Intelligence & Planning, 13 (9), 415.
9. Rowley, J (1998). Promotion and marketing communications in the information marketplace.' Library Review, 47 (8), 383387.
10. Wolfe, Lisa. Library Public Relations, (1997).Promotions and Communications: A HowToD
11. AjileyeLaogun, JO Summer (2004), Reference librarian/user relationship at the Obafemi Awolowo
12. Allen, MB (1993). 'International students in academic libraries: a user survey', College & Research Libraries, 54, July, 323333.

Mr. SALIK RAM
LIBRARIAN
CENTRAL LIBRARY, CMD PG COLLEGE BILASPUR (C.G)

New Frontiers Of Research Vol. 3 Dec. 2016 ISSN No. 2347-2685

Changes of Food habits among the Tribes of Korba District (C.G)

Dr. Mojaffar Ahamad, Dr. P.L. Chandrakar

ABSTRACT :

The tribals constitute around 40.90% of the total population Korba District. They are widely distributed all over the part of the district. This paper deals about the change of food habits among the tribes of Korba district. To meet the daily requirement of food people belonging to tribal groups of Korba District consume cheaply available food during different season for their livelihood. In this paper try to highlight the changes of food habits among all the tribal communities of Korba district.

Introduction:

The life style and tradition of each tribal community is unique and is related to the utilization of particular natural resource and particular type of work. They had been collecting resources from forest without causing any damage to it. The forest provides them with food and livehood security.

Like all tribal people across the world, the tribals of Korba district were happy to live for lives that were uncomplicated by Money. Till recently, they were living in harmony with their surroundings. Since the down of human civilization, human beings have been known to possess some basic needs in their lives, which comprise food, shelter, and clothing. The wants and needs of tribal people have multiplied due to change from rural economy to urban economy. There is, for instance, distinct change in general fooding, general outlook and even in philosophy of life. The necessities have increased with the increase of income and with of environment. Modern luxuries have become more or less a part of their life. Here environment plays a deterministic role for the nature of all the basic needs for human beings and these are interrelated with each other.

Culture changes continuously with the progress of time in response to change in the physical and social environment and therefore the basic needs of human beings are changed.

The forest gave them foods as well as other needs. The tribes believe in the divine nature of "Nature". To them, all things are imbibed with the divine sprite and are deserving of respect. Later, Hinduism absorbed their Gods and Goddesses in to its rich tapestry of scriptures, myths and legends and added their myths and legends to its own.

Study Area:

Korba district is a part of newly formed state Chhattisgarh of India separated from Madhya Pradesh on 1st Nov 2000. The district comes under Bilaspur division in 1998 and it is the inhabited mainly by tribals including the protected tribe 'Korwas' (known as Pahari Korwa). Korba district is situated in the Northern rocks and Hill area in between 22°8′ N to 23°3′ N and 82°8′ E to 83°5′ E. The geographical area of the district is 6599.00 sq. km, which is 3.15% of the total area of Chhattisgarh. The average height of the district 450mts from the mean sea level (MSL) and this is the 7th largest district of Chhattisgarh. Korba

ISSN No. 2347-2685

district is situated in the northern half of the Chhattisgarh state and surrounded by the five different districts of this state, Koriya in the north, Bilaspur in the west, Jangir-Jampa in the south, Raigarh in the East and Surguja in the north-eastern portion. According to 2011 Census of India Korba district represents 12,06,640 population which is 4.72% of Chhattisgarh total population.

The headquarter of the study district is Korba, situated about 200 km from the Capital city Raipur of Chhattisgarh. In 1998-99 this district was constituted with five tehsil (Korba tehsil, Kartala tehsil, Pondi-Uprora, Katghora tehsil, and Pali tehsil) and five development block (Korba, Kartala , Pondi-Uprora, Katghora, Pali) . The distrct has 5 statutory towns and 2 census town. Total number of villages in the district is 719 which includes 707 inhabited villages and 12 un-inhabited villages. The proportion of Scheduled Tribes population of the district is 40.90% in Census 2011, against 41.50% in Census 2001.

KORBA DISTRICT
LOCATION MAP

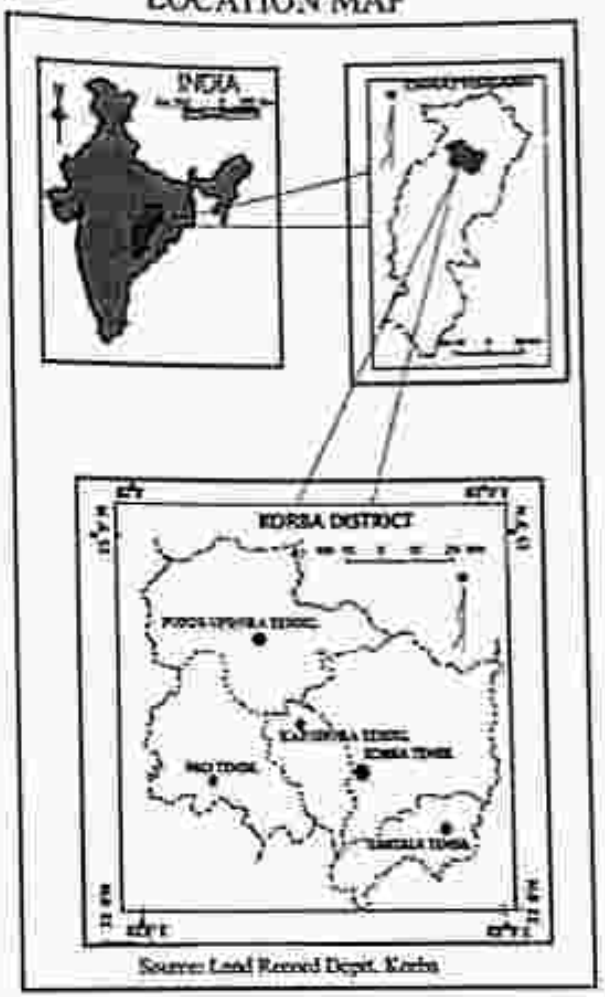

Source: Land Record Dept. Korba

The Problem:

In this paper an attempt has been made to analyze and asses the changes in the status of fooding habits and livelihood of the tribes of Korba District due to different Government programmes.

After the implementation of different developmental programme by the Chhattisgarh Govt. the study area witnesses a rapid change, epecially in socio-economic base as well as food habits among the tribes.

Objectives:

The main objectives are:

1. To identify the major tribals groups of the study area.
2. To know the change of food habits among the tribes of Korba district how the different Govt, policy implemented.
3. To assess how far the food habits changed in different season.
4. To understand the traditional food habits among the different tribal communities.

Methodology:

This article is based on a research work on "Cultural Changes in the Tribes of Korba District (C.G), A Geographical Analysis." Both primary and secondary data has been used in

ISSN No. 2347-2685

this research paper.

The methodology adopted for the present study is based on qualitative and quantitative approaches. The Secondary data are collected from various sources i.e. internet, books, journals, news paper, electronic media and print media. Keeping the above stated objectives in mind, proper collection of data, interviews and keen observation is followed by the researcher to formulate conclusion. Simple statistical techniques are used to drive fruitful results and cartographic techniques have been employed to facilitate visual interpretation.

In order to know the food habits of the Tribes of Korba District, a random survey was conducted by the research scholar in 2015 within different season. He adopted multistage sampling method. There are five Tehsils, 9 Revenue Infection Circles, 90 Patwari Circles, 719 villages in Korba district. Out of which field survey was conducted in 20 tribal villages among 10 tribal communities. 305 families in these 20 tribal villages were interviewed. From the surveyed villages door to door surveyed was conducted within the 305 tribal families. Among them the percentages of male interviewee were 79.67% and female interviewee were 20.33%. A total of 1709 tribal people reside in 305 surveyed families. Out of which 862 are males and 847 are females.

These families belonged to several tribal groups. Based on this survey, a scheduled has been made for the purpose of their socio-cultural information. Door to door survey was conducted and information related to these tribal people has been collected which includes their photographs also. This scheduled was filled in for all the facilities of the villages by personal interview method.

Distribution of Tribal groups in the study area:

In Korba district, the tribals are concentrated not evenly, due to undulating topography, less agricultural opportunities, and many more. There has been a decreased of 0.59% in the proportion ST population during the decade 2001-2011. As mentioned above, the percentage of ST population in the district is 40.90. it constitutes 57.1% in rural areas and 13.32% in urban areas in the district. Maximum concentration of ST population is in Pondi-Uprora tahsil i.e. 72.94% and the lowest is recorded in Katghora tahsil (23.87%).

There are mostly 25 or more tribal groups are residing in the different places with their different traditional culture. Here Gonds are ranked first for their total number of population with 36.57% as per 2011 census. They are well known as 'cultivator'. Kanwar ranked second with (34.16%). There has been a decreased of 0.88% in the proportion Kanwar population during the decade 2001-2011. It is followed by Oraon (5.95%), Binjhwars

Table No: 1

Korba District: Tahsil wise of ST population, 2011

DIST./TAHSIL	Total Population	ST Population	
		TST	%
Korba Tahsil	369257	106654	28.88
Kartala Tahsil	145796	71556	49.08
Pali Tahsil	198746	105074	52.87
Katghora Tahsil	304058	72572	23.87
Pondi-Uprora	188783	137703	72.94
KORBA DIST	1206640	493559	40.90

Source: Census of India 2011

ISSN No. 2347-2685

(5.5.149%), Dhanwars (4.82%) Majhwars (4.13%), Agariya (1.75%). Most of the tribes of the study area belong to forest and hilly area. Among them this study based on only 10 tribal communities as per their concentration.

But in Korba district the study will remain incomplete if the name of very backward community like Pahari Korwa is not explain. The name of this district is derived from the name of the Pahari Korwa, they are nearly .069% out of the total tribal population of this district in 2011.

Fooding Changes among the Tribal Communities:

Food is an important need for human life. Man is distinguished from other mammals by consumption of extremely wide range of foods, he is able to secure and utilize.

Table No-2

Tribal Groups Wise population Of Korba District 2001 and 2011

Sl No	Tribal Groups	Group wise S.T. population			
		2001		2011	
		Total	%	Total	%
1	AGARIYA	7,475	1.78	8452	1.75
2	BAIGA	558	.12	606	.125
3	BHIL	38	.008	41	.008
4	BHANIA	839	.20	1015	.208
5	BHARIA	4,513	1.01	4882	1.009
6	BHUNJIA	8	.002	—	—
7	BINJHWAR	24,221	5.08	25013	5.149
8	DHANWAR	19,867	4.68	23421	4.82
9	GADABA	2,781	.64	1334	.37
10	GOND	1,22,094	29.27	181469	36.47
11	KAMAR	11	.002	1	.001
12	KANWAR	1,47,141	33.84	165338	34.16
13	KHAIRAWE	3,008	.71	4119	.85
14	KHARIA	2,880	.68	3829	.79
15	KOL	1,362	.32	1731	.36
16	KORWA	2,639	.63	3115	.49
17	MAJHI	3,412	.83	3198	.65
18	MAJHWAR	18,158	4.33	20038	4.13
19	MUNDA	1,442	.34	1441	.30
20	NAGESIA	973	.23	1978	.25
21	ORAON	21,988	4.93	30132	6.22
22	PAO	462	.11	512	.103
23	PARDHAN	782	.16	792	.18
24	SOANTA	486	.11	796	.16
25	SAWAR	843	.20	882	.182
	District Total	418889	41.40	480000	40.96

Source: Census of India, 2001 and 2011

Obviously there is nothing more important to man that what he eats and how he eats. The tribes are true sons of Forest and collect their varied foods directly from forest. The forest product provides them sustenance in tune with the changing seasonal conditions so the food intake of the tribes varies from season to season. Rainy season can be termed as 'starving season' for them due to difficult availability of foods from forest.

Food Habit:

The main food grains of the tribes are Jowar and Rice. Now the tribals are not satisfied with millets and cereals. They require wheat, rice, vegetable, meat and fish. They consume pulses 'Adad', 'Tuver', 'Val' and 'Vatana' etc. Leafy vegetables are consumed in large quantity in the rainy season but very little in winter and summer. There are 'Khati Bhaji' (Hibiscus Canabinus), 'Tandalaja' (Amarnathus), 'Vatanani Bhaji' (Peo leaves), 'Channa Bhaji' (Leaves of Cicer arifinam), 'Palak Bhaji' (Spinach) etc. Sun dried leafy vegetables are stored for the off season. But time now no need to store their leafy vegetable for future because they are producing green vegetables all of a year with support of Government and irrigation facilities. Now they get surplus from their agricultural product after fulfil their needs and therefore they buy some necessary products for their daily life for foods, like salt, oil, spice, etc.

The observation is made among the tribal communities of the surveyed villages, they consumed various kinds of foods in different seasons. They do not prepare many varieties of food items.

4. The Central Govt. of late, has realized that production of millets has been drastically declining in the rural areas of the tribal villages. It has woken up to the negative impact of their changing food habits and on a war footing launched the millets mission to boost its cultivation.

Conclusion:

The Govt. has formed various policies and programmes for the upliftment of the tribal people but even after 64 years of achieving independence, they are still backwards. They are underdeveloped. Though a glimpse of changes in tribal food habits has observed in some tribal groups but the rate of changes for the majority of the tribal groups is moderate and is not up to the mark.

Above all the discussion, in order to have deeper insight into changes of food habits in the tribes of Korba district, primary data have been collected from 305 tribal surveyed families. Since, it was very difficult to determine the change of tribal food habits from field enquiry. Although changes of tribal food habits among the tribal communities of Korba district is moderately changed, nevertheless the pace of improvement indicates that the fooding changes among them seems to be spreading across the tribal villages. More so in urban areas where a considerable changes has been achieved. But it must be mentioned that such improvements or rather changes in a period of ten years is some remarkable. During the past decade, tribal people got accustomed to consumption of rice and, in the process brought down consumption of millets as well as their cultivation. Availability of rice at such a cheap price has induced the tribal communities to shift gradually from the highly nutritious millets to rice consumption.

As it will not be possible to provide nutrition at optimum level to every individual, priority in improving nutrition should be the vulnerable groups of tribal society. Certain points which may be emphasized for improving the nutritional status of the tribes of Korba District are:

1. Raising of kitchen garden and horticulture to combat their lean period monsoon;
2. Encouraging poultry, piggery, and fishery development to provide good quality proteins;
3. Rearing of milk cattle for increasing the consumption of milk among the tribes.

Reference:

1. Ahamad Mojaffar, (2011), *"Cultural Changes in the Tribes of Korba District (C.G): A Geographical Analysis"*, Unpublished Thesis.

2. Ali Asfaq Syed- (1973), *"Tribal Demography in Madhya Pradesh (A Socio-economic Study 1901-1973))*, Jai Bharat Publishing House,

3. *Bulletin*- (July – December 2005), Tribal Research and development Institute, Bhopal

4. *Census of India 2001, Chhattisgarh series – 23*, Directorate of Census Office, Chhattisgarh

5. Chandrakar P.L- (1994), *"A Socio Economic Analysis of Korwa Tribes in Madhya Pradesh: A Geographical Study"*, *Unpublished thesis.*

6. Chandrakar P.L and Tripathi K- (2001), *"Chhattisgarh Ka Bhogal"*, Sarda Publication.

7. District Hand Book-2011

Dr. Mojaffar Ahamad
Asstt. Teacher, Geography, Sukrabari A.K. H.M (H.S), Chanchal, Malda, WB
Dr. P.L. Chandrakar
Asstt. Professor, Department of Geography, C.M.D.P.G. College, Bilaspur, C.G

NEW FRONTIERS OF RESEARCH

Six Monthly Multidisciplinary Multilingual Referred Research Journal

MEMBERSHIP FORM

Address for communication regarding the publication subscription advertisement

Editor
New Frontiers of Research
C.M.D. P.G. College Campus Bilaspur (C.G.)
Mob. No. : 08871291000, E-mail Add. : nfr2013@gmail.com

Name : .....
Academic Qualifications : .....
Field of Specialisation : .....
Designation : .....
Mailing Address : (i) Permanent.....
.....
.....
(ii) E-mail Add. .....
Contact No. .....
.....

Membership Fee : .....
Subscription Rate : .....

S.No		Individual	Institutional
1.	Annual	1000.00	1500.00
2.	Life Member	10000.00	12000.00
3.	Student Member(Annual)	800.00	

Please send your payment by cash / D.D. in the name of "Pt. Bhagwat Prasad Dubey Smriti Samaj Evam Vigyan Unnayan Samiti" Payable at Bilaspur (Chhattisgarh).

Patrons :

Pt. Sanjay Dubey, Chairman GB, CMD College, Bilaspur (C.G.),

Executive Committee :

Bhagwat Prasad Dubey Smriti Samaj Evam Vigyan Unnayan Samiti Bilaspur (C.G.)

...dent	: Dr. D.K. Chakraborty, Bilaspur (C.G.)
... President	: Dr. K.K. Jain, Bilaspur, (C.G.)
Secretary	: Dr. Vinit Nayar, Bilaspur, (C.G.)
Treasurer	: Dr. P.L. Chandrakar, Bilaspur, (C.G.)
Joint Secretary	: Dr. Sanjay Singh, Bilaspur, (C.G.)
Members	: Smt. Anjali Chaturvedi, Bilaspur, (C.G.) Mrs. Kajal Kiran Gulhare, Bilaspur, (C.G.)

न्यू फ्रन्टियर्स ऑफ रिसर्च के प्रकाशन एवं स्वामित्व आदि के सम्बंध में घोषणा

(फार्म 4)

1.	प्रकाशन का स्थान	बिलासपुर छत्तीसगढ़
2.	प्रकाशन अवधि	छः माही
3.	प्रकाशक का नाम राष्ट्रीयता पता	डॉ. के.के.जैन भारतीय सी.एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर
4.	संपादक का नाम राष्ट्रीयता पता	डा. के.के. जैन भारतीय
5.	पत्रिका का स्वामित्व	पं. भागवत प्रसाद दुबे स्मृति समाज एवं विज्ञान उन्नयन समिति बिलासपुर (छ.ग.)

6. सभी विवादों का निपटारा बिलासपुर नगर के सीमान्तर्गत सक्षम न्यायालय में होगा।

मै डॉ. के.के. जैन यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है।